



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19]

नई विल्ली, शनिवार, मई 12, 1979/वैशाख 22, 1901

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12, 1979/VAISAKHA 22, 1901

इस पाँग में चिन्ह पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के लिए में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—चर्चा 3—उप-चर्चा (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सार्विक आदेश और प्रधिकारियां

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India  
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the  
Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई विल्ली, 28 मार्च, 1979

क्रा० आ० 1483.—यह, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि करवरी, 1978 में हुए आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिए सावारण निर्वाचन के लिए 247-चिन्नूर (क्रा० आ०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री तेगराम वेनकटी, चिन्नूर, तालुक चिन्नूर, जिला मालविलालाबाद (आंध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व प्रतिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रभेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेहा वाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यह, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस अप्रकल्पता के लिए, कोई कारण अवश्य स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस अप्रकल्पता लिए कोई पर्याप्त कारण या स्पष्टीकरण नहीं है;

अतः इब्द, उक्त प्रतिनियम की धारा 10-के प्रत्युत्तरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री तेगराम वेनकटी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद के मद्द्य जूने जाने और हीमे के लिए इस आदेश की तारीख से तीन बर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० आ०प्र-वि०स०/247/78(24)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 28th March, 1979

S.O. 1483.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tengaram Venkaty, Chinnur, Taluk Chinnur, District Adilabad (Andhra Pradesh), a contesting candidate for General Election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 247-Chinnur (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tagaram Venkaty to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-1A/247/78(24)]

क्रा० आ० 1484.—यह, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए विहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन

के लिए 305-खिजरी (प्र०ज०जा) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री छन्दपति महाबीर प्रसाद शाही, प्राम-नवागढ़, पी० गेतालसूर, जिला-राजीवी, बिहार लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेख दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यह, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री छन्दपति महाबीर प्रसाद शाही को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि.स./305/77(2)]

**S.O. 1484.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chhatrapati Mahabir Prasad Sahi, Village Navagarh P.O. Gatlisd, District Ranchi, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 305-Khijri (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chhatrapati Mohabir Prasad Sahi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/305/77(2)]

प्रादेश

मई दिल्ली, 4 प्र०प०, 1979

**का० आ० 1485.**—यह, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 251-इमामगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगदीश प्रसाद, प्रामनारायणपुर, पोस्ट-मैगरा, याता-जुमरिया, जिला-गया (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेख दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यह, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उक्त उम्मीदवार 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री दलीप सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० पंजाब-वि.स०/73/77]

## ORDER

New Delhi, the 4th April, 1979

**S.O. 1485.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dalip Singh, Village Khansian, Tehsil and District Patiala (Punjab) a contesting candidate for general election to the Punjab Legislative Assembly held in June, 1977 from 73-Dakala constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dalip Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/73/77]

**का० आ० 1486.**—यह, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 251-इमामगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगदीश प्रसाद, प्रामनारायणपुर, पोस्ट-मैगरा, याता-जुमरिया, जिला-गया (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेख दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यह, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री जगदीश प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि.स०/251/77(4)]

**S.O. 1486.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jagdish Prasad, Village Narayanpur, P.O. Maigra, Police Station—Dumarla, District Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 251-Imamganj constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jagdish Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/251/77(4)]

## आदेश

नई विली 6 प्रत्रैल, 1979

का० आ० 1487.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 306-रांची निर्वाचन-ज्योत से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री निधिकान्त उपाध्याय, ब्रह्मचारी आश्रम, पोस्ट ध्रुवा, जिला-राज्यी (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदर्थीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने से असफल रहे हैं।

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पर्क सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अपवाह स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या आयोगित्य नहीं हैं;

यतः यद्य, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री निधिकान्त उपाध्याय को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अपवाह विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं बिहार-वि०स०/306/87(5)]

## ORDER

New Delhi, the 6th April, 1979

S.O. 1487.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nidhikant Upadhyay, Brahmchari Ashram, P.O. Dhurwa, District Ranchi, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 306-Ranchi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nidhikant Upadhyay to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/306/77(5)]

का० आ० 1488.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 314-विशुनपुर (ग्र०ज०जा०) निर्वाचन-ज्योत से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम नारायण खलखो, करमटोली, पोस्ट भोजाहारी, रामी (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उद्धीष्ट बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पर्क सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अपवाह स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या आयोगित्य नहीं है;

यतः यद्य, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम नारायण खलखो को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अपवाह विधान परिषद् को सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं बिहार-वि०स०/314/77(11)]

S.O. 1488.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Narain Khalkho, Karamtoli, P.O. Morhabadi, District Ranchi (Bihar) a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 314-Bishnupur (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Narain Khalkho to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/314/77(11)]

का० आ० 1489.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 219-पालयमकोट्टौर्ह निर्वाचन-ज्योत से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एस० जस्टिन सुपूर्ण एस० शनमुगावेल जोनेपुरम एम०के० पौड्हाल डाक० (वाया) नारेकोइल जिला कन्याकुमारी (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा सदर्थीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यर्थों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पर्क सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अपवाह स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या आयोगित्य नहीं हैं;

यतः यद्य, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री एस० जस्टिन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अपवाह विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं त०ना०वि०स० 219/77(24)]

S.O. 1489.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri S. Justin S/o S. Shanmugavel, Jonepulam M.K. Pottal P.O., (Via), Nagercoil, Kanyakumari District (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu legislative assembly held in June, 1977 from 219-Palayamcotai assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And Whereas, the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri S. Justin to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/219/77(24)]

**का० आ० 1490.**—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आनंद प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 14-पालकोंडा (प्र० आ०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सामला माधवराव, कोंयेशु, पेडासाखा (डाक०), (वाया) कोमाराडा पार्वथीपुरम तालुक, श्रीकाकुलम जिला (आनंद प्रदेश) सोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदृशीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ओर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री सामला माधवराव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० आ० प्र०-वि० स० 14/78(28)]

**S.O. 1490.**—Whereas, the Election Commission is satisfied that Shri Samala Madhavarao, Konthesu, Pedasakha (Post), (Via) Komarada, Parvathipuram Taluk, Srikakulam District, (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 14-Palakonda (SC) Assembly Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Samala Madhavarao to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/14/78(28)]

**का० आ० 1491.**—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 28-पोलपोखर सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरी प्रसाद धोष, शाम-कनकी, डाक० कनकी, जिला पश्चिमी दिनांजपुर, पश्चिमी बंगाल थोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदृशीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ओर यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री हरी प्रसाद धोष की संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० प्र०-वि० स० 29/77(1)]

**S.O. 1491.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hari Prasad Ghose, Village Kanki, P.O. Kanki, District West Dinajpur, West Bengal, a contesting candidate for general election to the West Bengal Legislative Assembly from 29, Goalpokhar assembly constituency, held in June, 1977, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hari Prasad Ghose, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/29/77(1)]

**का० आ० 1492.**—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 28-पोलपोखर सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एनामुल हक, गांव महिसाखोर, पी० आ० मानोरा, पुलिस स्टेशन चकालिया, जिला पश्चिम दिनांजपुर, पश्चिमी बंगाल थोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदृशीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

ओर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री एनामुल हक को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० प्र०-वि० स० 29/77(2)]

**S.O. 1492.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Enamul Haque, Village Mahisakhore, P.O. Manora, Police Station Chakalia, District West Dinajpur, West Bengal, a contesting candidate for general election to the West Bengal Legislative Assembly from 29, Goalpokhar assembly constituency, held in June 1977, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Enaul Haque, to be disqualified for being chosen, as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/29/77(2)]

**का०आ० 1493।—यतः** निर्वाचित आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 29-गोलपोखर सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नुरुल हुदा, गांधी भालवार, पो० गोहाँसा, पुलिस स्टेशन गोलपोखर, जिला पश्चिम दिनाजपुर, पश्चिमी बंगाल लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा नद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अवश्य स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचित आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

यतः अब, उक्त उम्मीदवार की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचित आयोग एतद्वारा उक्त श्री नुरुल हुदा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अवश्य विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० प०बं०-वि०स०/29/77(3)]

**S.O. 1493।—Whereas** the Election Commission is satisfied that Shri Nurul Huda, Village Malduar, P.O. Goharra, Police Station Goalpokhar, District West Dinajpur West Bengal, a contesting candidate for general election to the West Bengal Legislative Assembly from 29, Goalpokhar assembly constituency, held in June, 1977, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nurul Huda, to be disqualified for being chosen, as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/29/77(3)]

**का०आ० 1494।—यतः** निर्वाचित आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 29-गोलपोखर सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मो० नासिर अहसेन, गांधी बिजारी देवीगंज, पो० गोल पोखर, जिला पश्चिम दिनाजपुर, पश्चिमी बंगाल लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा नद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अवश्य स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचित आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि

उसके पास इस सफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

यतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचित आयोग एतद्वारा उक्त श्री मो० नासिर अहसेन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अवश्य विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करत है।

[सं० प०बं०-वि०स०/29/77(4)]

**S.O. 1494।—Whereas** the Election Commission is satisfied that Shri Md. Nazir Ahsen, Village Bijbari Debiganj, P.O. Goalpokhar, District West Dinajpur, West Bengal contesting candidate for general election to the West Bengal Legislative Assembly from 29, Goalpokhar assembly constituency, held in June, 1977, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mohd. Nazir Ahsen, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA/29/77(4)]

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1979

**का०आ० 1495।—यतः** निर्वाचित आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में बिहार में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 44-चनरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरिबंश चिह्न, महल्ला बेलवां टिकंर, डाल्टनगंज (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा नद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अवश्य स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचित आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है,

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचित आयोग एतद्वारा उक्त श्री हरिबंश चिह्न को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अवश्य विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० बिहार-स०० स०/44/77 (1)]

## ORDER

New Delhi, the 7th April, 1979

**S.O. 1495।—Whereas** the Election Commission is satisfied that Shri Haribansh Singh, Mohalla Belwan Tikar, Daltanganj (Bihar), a contesting candidate for general election to the House of the People held in Bihar from 44-Chatra constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Haribansh Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-HP/44/77 (1)]

### आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1979

का०आ० 1496.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया कि एकवरी, 1978 में हुए आसाम विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 24-गोरीपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री इनामुल मजीद, ग्राम व डाक० बालाजान, जिला गोलापारा (आसाम) लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एकद्वारा उक्त श्री इनामुल मजीद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[स० आसामवि०स०/24/78]

### ORDER

New Delhi, 9th April, 1979

**S.O. 1496.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Inamul Mazid, Village and P.O. Balajan, District Gauripur (Assam), a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in February, 1978 from 24, Gauripur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Inamul Mazid to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AS-IA/24/78]

### आदेश

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1979

का०आ० 1497.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए असमनाडु विधान चाना के लिए साधारण निवाचन के लिए 186-वालंगिमत ( श्र० जा० ) सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी० श्रीनिवासन, बेगलौं स्ट्रीट, थिरुवृष्टीपुर, जिला असम ( असमनाडु ) लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है।

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उक्त व्याधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एकद्वारा उक्त श्री पी० श्रीनिवासन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[स० न० न० न० वि० स०/186/77 (25)]

### ORDER

New Delhi, the 11th April, 1979

**S.O. 1497.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P. Srinivasan, Bangalore Street, Thiruvaiyaru, District Thanjavur (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in June, 1977 from 186, Valangiman (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri P. Srinivasan, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/186/77(25)]

का० आ० 1498.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निवाचन के लिए 270-वरकटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्रनिलद्वादश, द्वाम-देवरिया, पोस्ट-पुनाई, जिला हजारीबाग (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है;

अतः अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एकद्वारा उक्त श्री प्रनिलद्वादश को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[स० बिहार-वि० स०/270/77 (10)]

**S.O. 1498.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Anrudh Singh, Village Devria, P.O. Punai District Hazaribagh, Bihar a contesting candidate for general election

to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 270-Barkatha constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Anirudh Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/270/77 (10)]

**का०आ० 1499**—यतः निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 152-केश्लूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री धेनवा लखमा, आम व पो० कूकानार, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश सोक प्रतिनिधित्व प्रतिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रयोक्तिरति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेन्डा वाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकात्तिय नहीं हैं;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री धेनवा लखमा, को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[मं० म०प्र० वि० स० /152/77]

**S.O. 1499.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ghenwa Lakhma, Village Kukanar, P. O. Kukanar, District Bastar, Madhya Pradesh a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 152-Keshloor constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all within the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ghenwa Lakhma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/152/77]

आवेदन

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1979

**का० आ० 1500**—यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 74-नवबर्ठी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोहम्मद मिह, कोठी रोजविला, भरतपुर, राजस्थान, सोक प्रतिनिधित्व प्रतिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रयोक्तिरति

अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेन्डा वाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकात्तिय नहीं हैं;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री मोहम्मद कोई संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० राज०-वि० स० /74/77 (10)]

## ORDER

New Delhi, the 16th April, 1979

**S.O. 1500.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Arun Singh, Kothi Rojwila, Bharatpur, Rajasthan a contesting candidate for general election to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 74-Nadbai assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And Whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Arun Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ-LA/74/77 (10)]

आवेदन

**का० आ० 1501**—यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 15-गुम्मिपुँडी सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री टी० मोहम्मद ग्रामीशा, पुत्र धूरब ग्रामीशा, नक्की रेडियो कॉ०, उथुकोटई, नाल्सुक मिल्कलूर, जिला चिङ्गलपट्टू (तमिलनाडु) सोक प्रतिनिधित्व प्रतिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रयोक्तिरति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेन्डा वाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायीकात्तिय नहीं हैं;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री टी० मोहम्मद ग्रामीशा को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[मं० न० न०-वि० स०/15/77 (28)]

## ORDER

**S.O. 1501.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri T. Mohamad Ali Khan, S/o Thurab Alikhan, Lucky Radio Co., Uthukottai, Tiruvallur Taluk, Chengalpattu District, (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the Tamilnadu legislative assembly held in June, 1977 from 15-Gummidipoondi assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required

by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri T. Mohamad Alikhan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/15/77/ (28)]

**का० आ० 1502**—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए माध्यारण निर्वाचन के लिए 13-माइलपोर सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार डा० यिरुनागर रथनाम, 10, थूकाराम 1 स्ट्रीट टी० नगर, मद्रास-17 (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदृशीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रभेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा शाखिल करने में असफल रहे हैं;

ग्रोर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी हस असफलता के लिए कोई कारण अध्यवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ग्रोर, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास हस असफलता के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है;

ग्रातः ग्रब, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी हस असफलता के लिए कोई कारण अध्यवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ग्रोर, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास हस असफलता के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० न० न०-वि० स० /13/77 (27)]

**S.O. 1502.** Whereas the Election Commission is satisfied that Dr. Thirunagar Rathnam, 10, Thukkaram I Street, T. Nagar, Madras-17 (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in June, 1977 from 13-Mylapore assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Dr. Thirunagar Rathnam to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/13/77 (27)]

आयोग

मई दिल्ली, 19 प्रैल, 1979

**का० आ० 1503**—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए माध्यारण निर्वाचन के लिए 67-कट्टुमश्वारकोहल (म० ज०) निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी० ए० सामीदुराय सुपुत्र अल्हो, टी० प्रश्नमोहीदेवन, ईम्यालुर पोर्ट, चिरम्बरम तालुक, विकाश अकाट जिला (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदृशीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रभेक्षित समय के प्राप्तर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा शाखिल करने में असफल रहे हैं;

ग्रोर, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अध्यवा स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास हस आदेश के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायैवित्य नहीं है;

ग्रातः ग्रब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री पी० ए० सामीदुराय को संसद के किसी भी क्षेत्र के या किसी राज्य की विधान सभा अध्यवा विधान परिषद् के मध्यस्थ चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० न० न०-वि० स० / 67/ 77 (29)]

## ORDER

New Delhi, the 19th April, 1979

**S.O. 1503.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P. A. Samidurai, S/o Adhi, T. Arunmozhidevan, Eyyalur Post, Chidambaram Taluk, South Arcot District (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in June, 1977 from 67- Kattumannarkoil (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri P. A. Samidurai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/67/77(29)]

**का० आ० 1504.**—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए सामाधारण निर्वाचन के लिए 253-धोल निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शान्तीनाथ महाराज ओंकारनाथ, मुकाम व डाक० पिम्पलगांव धोल त.लुक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदृशीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रभेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा शाखिल करने में असफल रहे हैं;

ग्रोर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी हस असफलता के लिए कोई कारण अध्यवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ग्रोर, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास हस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या व्यायैवित्य नहीं है;

ग्रातः ग्रब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री शान्तीनाथ महाराज ओंकारनाथ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अध्यवा विधान परिषद् के मध्यस्थ चुने जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[सं० महा०-वि० स० /253/ 78(127)]

**S.O. 1504.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shantainath Maharaj Onkarnath, At and P.O. Pimpla-

gaon, Daud taluk, a contesting candidate for General Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in February, 1978 from 253, Daund constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shantanu Mahajani Okarnath to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/253/78(127)]

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1979

का० का० 1505.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 53-मेलमलायानुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एम० ए० कुथार०, देवदानमपेट्टाटाह ग्राम धीर डाक०, गिरी लालुक जिला विधिन मकान, तमिलनाडु लोक प्रतिनिधित्व प्रबिनियम, 1951 तथा तद्विन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायालिक नहीं हैं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री एम० ए० कुथार० को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[स० त० ना० - वि० स० /53/77(30)]

## ORDER

New Delhi, the 20th April, 1979

S.O. 1505.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri M. A. Kuthan, Devadanampettai Village and Post, Gingee Taluk, District South Arcot (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in June, 1977 from 53, Melmalayanur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri M. A. Kuthan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/53/77(30)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1979

का० का० 1506.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन

के लिए 30-नि रुद्यारी निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्री एम० नरायणाडु (उर्फ़) नागयण डोस्स, श्रीलंग कालोनी, चिवडा ग्राम व डाक०, तिरुत्तानी नालूक, जिला चिंगलपट्टू, (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व प्रबिनियम, 1951 तथा नदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या स्थायीचित्य नहीं हैं;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री एम० नरायणाडु (उर्फ़) नरायण डोस्स को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[स० त० ना०-वि० स० / 30/77/(31)]

## ORDER

New Delhi, the 21st April, 1979

S.O. 1506.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri R. Narayanan (alias) Narayananadoss, Old Colony, Chivada village and Post, Tiruttani Taluk, Chengalpatu District (Tamil Nadu) a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in June, 1977 from 30-Tiruttani constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri R. Narayanan (alias) Narayananadoss be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/30/77(31)]

आदेश

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1979

का० का० 1507.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि कार्यरी, 1978 में हुए कलाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 79-चिकपेट निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एम० वासपा, 6, 25वीं फास, किलारी रोड, बंगलोर-53 लोक प्रतिनिधित्व प्रबिनियम, 1951 तथा तदीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पूर्ण सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्थायीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या स्थायीचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री एम० वासपा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है।

[स० कर्नाटक-वि० स० / 79/78(5)]

## ORDER

New Delhi, the 25th April, 1979

**S.O. 1507.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri N. Dasappa, 6, 25th Cross, Kilari Road, Bangalore-53 a contesting candidate for general election to the Karnataka Legislative Assembly held in February, 1978 from 79-Chickpet Assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason, or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri N. Dasappa to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. KT-LA/79/78(5)]

नई विल्सी, 26 मार्च, 1979

**का० आ० 1508.—मुस्लिम लीग (विपक्ष) ने, जो केरल राज्य में एक मान्यता प्राप्त राज्यीय वल है, अपना नाम “ऑल इंडिया मुस्लिम लीग” के रूप में बदलने के लिए आवेदन किया है;**

और निवाचित आयोग का यह समावान हो गया है कि यथा निवेदित नाम का परिवर्तन स्वीकार कर दिया जाना चाहिए;

प्रतः, अब, निवाचित आयोग, निवाचित प्रतीक (प्रारूपण और आबंटन) प्रावेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (अ) और उप-पैरा (2) के अनुसरण में, तारीख 25 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3 (ii) में का० आ० 40 (ग्र) के रूप में यथा प्रकाशित अपनी तारीख 25 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं० 56/78 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अधिकृत :—

उक्त अधिसूचना की सारणी 2 के स्तम्भ 2 में, केरल राज्य के सामने “4. मुस्लिम लीग (विपक्ष)” प्रविष्टि के स्थान ५८, “4. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग” प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं० 56/79 (3)]

बी० नागसुब्रामण्यन, सचिव

New Delhi, the 26th April, 1979

**S.O. 1508.**—Whereas the Muslim League (Opposition), a recognised State Party in the State of Kerala, has applied to the Commission for the change of its name to 'All India Muslim League' ;

And whereas the Commission is satisfied that the change of name requested for should be acceded to;

Now, therefore, in pursuance of clause (b) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendments to its notification No. 56/78, dated the 25th January, 1978, published as S.O. 40(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3(ii), dated 25th January, 1978, namely :—

In column 2 of table 2 of the said notification, for the entry '4. Muslim League (Opposition)' against the State of Kerala, the entry '4. All India Muslim League' shall be substituted.

[No. 56/79(3)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

## विधि, स्थाय और कामनी कार्य मंत्रालय

(स्थाय विभाग)

नई विल्सी, 28 मार्च, 1979

**का० आ० 1509.—**इसके द्वारा, नेहरू प्रमाणक नियम (नोटरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सकाम प्रविकारी द्वारा सूचना दी जाती है, कि उक्त प्राधिकारी को श्री अवधीश कुमार वर्मा, एडवोकेट (सिक्किल कोर्ट, वाराणसी) ने उक्त नियमों के नियम 4 के मध्यम, वाराणसी में नेहरू प्रमाणक (नोटरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है।

उक्त व्यक्ति को नेहरू प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियाँ हो तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के बादही विन के अध्यारी नीचे हस्ताक्षर करने वाले को सिद्ध कर देज दिये जायें।

[संख्या 22/25/79-स्थाय]

ल० १० हिन्दी, सकाम अधिकारी

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY

## AFFAIRS

(Department of Justice)

New, Delhi, the 28th April, 1979

**S.O. 1509.**—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Awadesh Kumar Verma, Advocate Civil Courts, Varanasi for appointment as a Notary to practise in Varanasi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/25/79-JUS]

L. D. HINDI, Competent Authority

## पूर्ण मंत्रालय

## (कारीबिंक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई विल्सी, 21 अप्रैल, 1979

**का० आ० 1510.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शरीकतों का प्रयोग करते हुए, तथा भारतीय लेखा परीक्षा और सेल्क विभागों में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अधिकृत :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 18 के उप-नियम (1) के खण्ड (अ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अधिकृत :—

(अ) यथास्थिति, अपनी पेंशन न लेने का अधिकार उपदान, जिसके अन्तर्गत मूल्य तथा सेवा निवृत्ति उपदान यदि कोई हो, भी है, वापस करने का और अपनी पूर्व सेवा की गणना महेक सेवा के रूप में कराने का विकल्प कर सकता है जिस दशा में मध्यवर्ती अवधि में लो गई पेंशन वापस करने की अपेक्षा नहीं होगी। किन्तु पेंशन, का वह प्रांश जो पुनर्नियोजन के समय बेतन नियत करने के लिए गणना में नहीं लिया गया था वापस कर दिया जायगा।

[सं० का० 3 (9)-ई० शी० (ए)/76]

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
**(Department of Personnel & A.R.)**  
 New Delhi, the 21st April, 1979

**S.O. 1510.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, in sub-rule (1) of Rule 18, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

“(b) to cease to draw his pension or refund the gratuity, including the death-cum-retirement gratuity, if any, as the case may be, and count his previous service as qualifying service in which case the pension intermediately drawn shall not be required to be refunded but the element of pension which was not taken into account for fixation of pay on re-employment shall be refunded.”

[No. F. 3 (9)-EV(A)/76]

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1979

**का० अ० 1511.**—राज्यपत्रि, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शास्त्रियों का प्रयोग करते हुए साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रथमतः—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) संशोधन नियम, 1979 है।  
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी।

2. साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में पांचवीं प्रान्तसूनी में, वैगा 2 में, “नमूना सर्वेषण संगठन के केन्द्रीय संक्रिया प्रभाग के प्रधीन वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारिकृत की दशा में उसका विशेष कार्य प्रधिकारी या उपनिवेशक,” प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, या प्रथमतः—

“राज्यपत्र नमूना सर्वेषण संगठन के केन्द्रीय प्रभाग के प्रधीन समूह 'ग' और समूह 'घ' कर्मचारियों की शास्त्र उसका मुख्य प्रशासनिक प्रधिकारी”।

[सं० 13 (5)/78-ई-V (बी)]  
 एस० प्रार० प्रयोगाल, प्रबन्ध सचिव

New Delhi, the 23rd April, 1979

**S.O. 1511.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely;

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Funds (Central Services) Rules, 1960 in the Fifth Schedule, in paragraph 2, for the entry “Officer on, Special Duty or Deputy Director in the Field Operations Division of the National Sample Survey Organisation in respect of Class III and Class IV staff under him”, the following entry shall be substituted, namely :—

“The Chief Administrative Officer in the Field Operations Division of the National Sample Survey Organisation in respect of Group C and Group D.”

[No. 13 (5)/78-EV (B)]  
 S. R. AGRWALA, Under Secy.

(राजसाहा विभाग)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1979

**का० अ० 1512.**—केन्द्रीय सरकार राजसाहा (संघ के सासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित विभागों को जिनके कर्मचारिकृत में हिन्दी का कार्य साक्षक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, प्रधिमूलत करती है :—

1. विधायी सिमाग

2. संघ लोक सेवा प्रायोग।

[संख्या 12022/1/78- रा०भा० (ब०-२)]

हस्तिमू कंसल, उप सचिव

**Department of Official Language**

New Delhi, the 26th April, 1979

**S.O. 1512.**—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following Departments, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

(1) Legislative Department,

(2) Union Public Service Commission.

[No. 12022/1/78-OL (B-2)]

H. B. KANSAL, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1979

प्राप्त-कर

**का० अ० 1513.**—प्रायोगकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 2 के अण्ड (44) के उप-अण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री के० एम० लाल को, जो केन्द्रीय सरकार के राजकारित प्रधिकारी हैं, उक्त प्रधिनियम के प्रधीन कर बसूली प्रधिकारी की विभिन्नों का प्रयोग करने के सिये प्राप्तिहत करती है।

2. यह प्रधिनियम, श्री के० एम० लाल के कर बसूली प्रधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 2768 (फा० सं० 404/158/77-भा०क० स० क०)]

एच० वेंकटरमन, उप-सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

New Delhi, the 12th April, 1979

**INCOME TAX**

**S.O. 1513.**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri K. M. Lal being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri K. M. Lal takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 2768 (F. No. 404/158/77-ITCC)]

H. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 12 मई, 1979

(सीव-शुल्क)

**का० अ० 1514.**—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क प्रधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शास्त्रियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और सीमा विभाग) की प्रधिनियमा सं० 95-सीमा-शुल्क, तारीख 30 अक्टूबर, 1975 को वित्तित करती है।

[सं० 96/79-सीमा शुल्क/का० सं० 481/35/75-सी०श० VII]

एम० हेण्ड्रमूर्स, प्रधर सचिव

New Delhi, the 12th May, 1978  
(CUSTOMS)

S.O. 1514.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 95-Customs, dated the 30th October, 1975.

[No. 96/79-Customs/F. No. 481/35/75-Cus. VII]

N. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

( अधिकारी कार्य विभाग )  
( बैंकिंग प्रबंध )

नई विल्सनी, 2 अप्रैल, 1979

का० अ० 1515—बैंककारी विभागम अधिनियम, 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय बैंकों की सिफारिश पर एतत्पूर्वारा धोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबंध, प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत स्थापित तथा निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट शक्तीय ग्रामीण बैंकों पर, उस सीमा तक लागू नहीं होने जहाँ तक इनका संबंध उक्त धारा के अन्तर्गत उनके तुलन पक्ष तथा 31 दिसम्बर, 1978 तथा 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त होने वाले वर्षों के बारे में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, इन बैंकों के साथ तथा हासि के लेखे के प्रकाशन से है:—

बनुसूची

क्रम	शक्तीय ग्रामीण बैंक का नाम
1.	प्रथमा बैंक, मुरावाबाद ( उत्तर प्रदेश )
2.	गोरखपुर शक्तीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर ( उत्तर प्रदेश )
3.	हरयाणा शक्तीय ग्रामीण बैंक, मिदानी ( हरयाणा )
4.	जयपुर नाशपुर शक्तिलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर ( राजस्थान )
5.	गोड ग्रामीण बैंक, मालदा ( पश्चिम बंगाल )
6.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा ( बिहार )
7.	समयुक्त शक्तीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़ ( उत्तर प्रदेश )
8.	शक्तीय ग्रामीण बैंक, घेरावाबाद ( मध्य प्रदेश )
9.	तुंजमद्दा ग्रामीण बैंक, बेलारी ( कर्नाटक )
10.	पुरी ग्रामीण बैंक, विपरी ( उडीसा )
11.	जम्मू सरल बैंक, जम्मू ( जम्मू और काशीर )
12.	चम्पाराम शक्तीय ग्रामीण बैंक, मोत हारी ( बिहार )
13.	बारावंकी ग्रामीण बैंक, बारावंकी ( उत्तर प्रदेश )
14.	गुडगांव ग्रामीण बैंक, गुडगांव ( हरयाणा )
15.	रायबरेली शक्तीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली ( उत्तर प्रदेश )
16.	फरीखाबाद ग्रामीण बैंक, फरीखाबाद ( उत्तर प्रदेश )
17.	मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बोकुरा ( पश्चिम बंगाल )
18.	बोलंगनगर शक्तिलिक ग्रामीण बैंक, बोलंगनगर ( उडीसा )
19.	नागर्जुन ग्रामीण बैंक, अमाम ( आंध्र प्रदेश )
20.	प्रागृज्योतिष्य गंवालिया बैंक, नलबारी ( असम )
21.	रायलासीमा ग्रामीण बैंक, कुडपा ( आंध्र प्रदेश )
22.	मालप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड ( कर्नाटक )
23.	मध्यराष्ट्री ग्रामीण बैंक, सूरी ( पश्चिमी बंगाल )
24.	मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली ( राजस्थान )
25.	मराठाबाड़ा ग्रामीण बैंक, बान्डे ( महाराष्ट्र )
26.	मणीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर ( उत्तर प्रदेश )
27.	श्री विश्वाला ग्रामीण बैंक, श्रीकाळुम ( आंध्र प्रदेश )
28.	कावेरी ग्रामीण बैंक, मेसूर ( कर्नाटक )
29.	मेघावटी ग्रामीण बैंक, सीकर ( राजस्थान )
30.	कटक ग्रामीण बैंक, कटक ( उडीसा )

क्रम संख्या	शक्तीय ग्रामीण बैंक का नाम
31.	बिलासपुर शक्तीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर ( मध्य प्रदेश )
32.	मगध ग्रामीण बैंक, गया ( बिहार )
33.	कोरापुट पंचवटी ग्रामीण बैंक, जैपुर ( उडीसा )
34.	माउथ मालाबाद ग्रामीण बैंक, मल्लपुरम ( कर्नाटक )
35.	नाय मालाबाद ग्रामीण बैंक, कपोरी ( केरल )
36.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला ( त्रिपुरा )
37.	रीवासियों ग्रामीण बैंक, रीवा ( मध्य प्रदेश )
38.	हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी ( हिमाचल प्रदेश )
39.	कोस्टी शक्तीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया ( बिहार )
40.	बलिया शक्तीय ग्रामीण बैंक, बलिया ( उत्तर प्रदेश )
41.	सुलतानपुर शक्तीय ग्रामीण बैंक, सुलतानपुर ( उत्तर प्रदेश )
42.	उत्तर बंग शक्तीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार ( पश्चिम बंगाल )
43.	पांडुन ग्रामीण बैंक, सत्तूर ( तमिलनाडु )
44.	वैशाली शक्तीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर ( बिहार )
45.	मुरोर शक्तीय ग्रामीण बैंक, मुरोर ( बिहार )
46.	बुंदेलखण्ड शक्तीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ ( मध्य प्रदेश )
47.	सथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका ( बिहार )
48.	हरवोई उत्तराय ग्रामीण बैंक, हरवोई ( उत्तर प्रदेश )
49.	हुत्ता ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा ( कर्नाटक )
50.	कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज ( गुजरात )
51.	जामनगर ग्रामीण बैंक, जामनगर ( गुजरात )

[एफ० 2-8/79-भार० आर० भा०]

सी० आर० बिश्वास, उप सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 2nd April, 1979

S.O. 1515.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of section 31 of the said Act shall not apply to the Regional Rural section ( 1 ) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, Banks specified in the schedule below, established under sub-section ( 1 ) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) in so far as the said section requires the publication of their balance sheets and profit and loss accounts together with the Auditor's Reports thereon in respect of the years ending the 31st December 1978 and 31st December, 1979.

#### SCHEDULE

Sr. No.	Name of the Regional Rural Banks
1	1. Prathama Bank, Moradabad (U.P.)
2.	2. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank, Gorakhpur (U.P.)
3.	3. Haryana Kshetriya Gramin Bank, Bhiwani (Haryana)
4.	4. Jaipur Nagaur Aanchalk Gramin Bank, Jaipur (Rajasthan)
5.	5. Gaur Gramin Bank, Malda (West Bengal)
6.	6. Bhojpur Rohtas Gramin Bank, Arrah (Bihar)
7.	7. Samyut Kshetriya Gramin Bank, Azamgarh (U.P.)
8.	8. Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad (M.P.)
9.	9. Tungabhadra Gramin Bank, Bellary (Karnataka)
10.	10. Puri Gramya Bank, Pipli (Orissa)
11.	11. Jammu Rural Bank, Jammu (J. & K.)
12.	12. Champaran Kshetriya Gramin Bank, Motihari (Bihar)
13.	13. Bara-banki Gramin Bank, Bara-banki (U.P.)
14.	14. Gurgaon Gramin Bank, Gurgaon (Haryana)
15.	15. Rae Bareli Kshetriya Gramin Bank, Rae Bareli (U.P.)
16.	16. Farrukhabad Gramin Bank, Farrukhabad (U.P.)
17.	17. Mallabhum Gramin Bank, Bankura (West Bengal)
18.	18. Bolangir Anchalik Gramya Bank, Bolangir (Orissa)
19.	19. Nararjuna Gramenea Bank, Khammam (A.P.)
20.	20. Pragjyotish Gaonlia Bank, Narbari (Assam)
21.	21. Rayalaseema Grammena Bank, Cuddapah (A.P.)

1	2
22. Malaprabha Gramenea Bank, Dharwar (Karnataka)	
23. Mayurakshi Gramin Bank, Suri (West Bengal)	
24. Marwar Gramin Bank, Pali (Rajasthan)	
25. Marathwada Gramin Bank, Nanded (Maharashtra)	
26. Bhagirath Gramin Bank, Sitapur (U.P.)	
27. Sri Visakha Gramenea Bank, Srikakulam (A.P.)	
28. Cauvery Gramenea Bank, Mysore (Karnataka)	
29. Shekhawati Gramin Bank, Sikar (Rajasthan)	
30. Cuttack Gramya Bank, Cuttack (Orissa)	
31. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank, Bilaspur (M.P.)	
32. Magadh Gramin Bank, Gaya (Bihar)	
33. Koraput Panchabati Gramya Bank, Jeypore (Orissa)	
34. South Malabar Gramin Bank, Malappuram (Kerala)	
35. North Malabar Gramin Bank, Cannanore (Kerala)	
36. Tripura Gramin Bank, Agartala (Tripura)	
37. Rewa Sidhi Gramin Bank, Rewa (M.P.)	
38. Himachal Gramin Bank, Mandi (M.P.)	
39. Kosi Kshetriya Gramin Bank, Purnea (Bihar)	
40. Balia Kshetriya Gramin Bank, Ballia (U.P.)	
41. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, Sultanpur (U.P.)	
42. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (West Bengal)	
43. Pandyan Grama Bank, Sattur (Tamil Nadu)	
44. Vaishali Kshetriya Gramin Bank, Muzaffarpur (Bihar)	
45. Monghyr Kshetriya Gramin Bank, Monghyr (Bihar)	
46. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank, Tikamgarh (M. P.)	
47. Santhal Parganas Gramin Bank, Dumka (Bihar)	
48. Hardoi-Unnao Gramin Bank, Hardoi (U.P.)	
49. Krishna Gramenea Bank, Gulbarga (Karnataka)	
50. Kutch Gramin Bank, Bhuj (Gujarat)	
51. Jamnagar Gramin Bank, Jamnagar (Gujarat)	

[F. 2-8/79-R.R.B.]

C. R. BISWAS, Dy. Secy.

नई विल्सो 27 अप्रैल, 1979

का० ३० १५१६.—कृषि क्षेत्रिक पुनर्वित्र और विकास निगम अधिनियम, १९६३ (१९६३ का १०) की धारा १० के स्पष्ट (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं विद्युत विभाग के मंत्रियों के द्वारा कृषि विभाग के मंत्रियों के स्थान पर कृषि पुनर्वित्र और विकास निगम के नियंत्रण के रूप में नामित करती है।

[सं० एफ० 10-31/ 79- ए० सं०]

यशवंत राज, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 1979

S.O. 1516.—In exercise of the powers conferred upon it by clause (c) of section 10 of the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963 (10 of 1963), the Central Government hereby nominates Dr. M. S. Swaminathan, Secretary, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation, as a Director of the Agricultural Refinance and Development Corporation vice Shri G. V. K. Rao.

[No. F. 10-31/79-AC]

YASHWANT RAJ, Under Secy.

(Department of Expenditure)

CORRIGENDA

New Delhi, 26th April, 1979

S.O. 1517.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) No. S.O. 2131, dated the 7th June, 1978, published in the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-section (ii), dated the 22nd July, 1978, at pages 1991 to 2017,—

Page 1991—

(1) in rule 3,—

- (i) in line 7, for "appropriation.", read; "appropriation"; and
- (ii) in line 9, for "stores.", read "stores";

Page 1992—

- (2) in rule 8,—
- (i) in line 5, for "or", read "of"; and
- (ii) in line 18, for "Plant", read "Plants";

Page 1992—

- (3) in rule 10(5),—in line 34, for "or", read "no";

Page 1993—

- (4) in rule 14,—in line 4, for "Officer", read "Office";

Page 1993—

- (5) in line 1 of rule 15,—for ":", read "—";

Page 1994—

- (6) in sub-rule (2) of rule 17,—in line 2, for "—", read ":";

Page 1994—

- (7) (a) in rule 18,—
- (i) in line 6, for ":", read ":";
- (ii) in line 13, for ":", read ":";
- (iii) in line 18, for ":", read ":";
- (b) in sub-rule (2),—
- in line 6, for "High-ways", read "Highways";

Page 1995—

- (8) in rule 22,—
- in line 1, for "operation", read "operations";

Page 1995—

- (9) in sub-rule (2) of rule 26,—
- in line 1 for "—", read "—";

Page 1996—

- (10) in Schedule I,

- (i) under Department of Agriculture, item 7 :—
- for "Badni", read "Budni";

- (ii) under Ministry of Communications,—for "(A) Department of Electronics" read "DEPARTMENT OF ELECTRONICS".

Page 1997—

- (iii) under Department of Education, item 7 :—
- for "(Control of Accounts)"
- read "(Controller of Accounts)".

Page 1997—

- (iv) under 'Department of Revenue', in item 26, in line 3, for "(Forfeiture of Property)", read "(Forfeiture of Property)".

- (v) under 'Ministry of Home Affairs',

- (i) item 20 and the entries relating thereto may be omitted; and
- (ii) for item "21", read "20".

Page 1998—

- (vi) under the heading 'Chandigarh',—omit item 1 and the entries relating thereto; and items 2, 3 & 4 may be renumbered as 1, 2 & 3, and the entries relating thereto.

- (vii) under the heading 'Department of Industrial Development'.

- for "6. Director, Enforcement Directorate",
- read "6. Economic Adviser to the Government of India".

- (viii) under the heading 'Ministry of Information and Broadcasting',

- "2. Principal, Information Officer",
- read "2. Principal Information Officer".

(ix) under the heading 'Department of Company Affairs', for "3. Member Secretary High Powered Expert Committee", read "3. Member Secretary, High Powered Expert Committee".

(x) under the heading 'Ministry of Labour',—

- (a) in item 2(i),—  
in line 3, for "Kanpur New Delhi", read "Kanpur/ New Delhi"; and
- (b) in item 2(v),—  
for "National", read "Regional";  
for "Institute", read "Institutes"; and  
for "New Delhi", read "Bangalore"

**Page 2000—**

(11) in Schedule III,—

- (i) in Note,—  
in line 2, for "temporaty", read "temporary";

(ii) in Table,—

- in column 2, for "Service", wherever it occurs, read "Services"; and

(iii) in Explanation,—

- in line 1, for ":", read "—".

**Page 2001—**

(12) in Schedule V,—

- (i) in Table, under column "Non-Recurring", in line 3, for ")", read ":";
- (ii) in Annexure, in Serial No.3, in column 4,—in lines 1 and 2 of para 1(A) (ii), for "officers", read "officer".

**Page 2002—**

(13) in column 4,—

- in line 1, for "conveyanc", read "conveyance".

**Page 2004—**

(14) in Schedule V, (i) in Serial No.3 of Annexure,—

in column 4,

- in line 5, for "th", read "the"; and

(ii) in Serial No.6(ii), in column 4,—

- in lines 3 and 4, for "Ministry Department", read "Ministry/ Department".

**Page 2008—**

(15) in Schedule V, in Serial No.13(ii) of Annexure, in column 4 for "proceed", read "proceeds".

**Page 2009—**

(16) in Schedule V, in Serial No.14 of Annexure, in column 4, in para 2,

- in line 13, for "one", read "and".

**Page 2010—**

(17) in Schedule V, in Annexure,—

- (i) in Serial No.14, in column 4,  
in line 30, after "where", read "it";

(ii) in Serial No.16, in column 3,

- in line 4, for "Madras", read "Madras"; and

(iii) in Serial No.16, in column 4, in sub-para(a),  
in line 2, after "hired", read "under"; and

- in line 11, for "placed", read "places".

**Page 2011—**

(18) in Schedule V, in Annexure,—

- (i) in Serial No. 16, in column 4, in para (2), in lines 8 and 9, for "officer", read "office".

**Page 2012—**

(19) in Schedule V, in Annexure,—

- (i) in Serial No.16, in column 4, para (9),  
in Line 3, for "residential", read "residential".
- (ii) in Serial No.-21, in column 3, in para (i),  
for "Chief Controller of Printing and Stationery",  
read "Controller of Stationery".

**Page 2013—2014**

(20) in Schedule V, in Annexure,—

- (i) in Serial No. 21, in column 4, in para (4) (C), for "Chief Controller of Printing and Stationery", read "Controller of Stationery".
- (ii) in Serial No. 22, in column 2, in sub-para (ii),  
in lines 6 and 7, after "establishment", read "including".
- (iii) in Serial No.-22 in column 2, in sub-para (ii), in line 4, for "require" read "required".
- (iv) in Serial No.-23, in column 4, in para (1),—  
in line 9, after "Group D", read "—".
- (v) in Serial No.-23, in column 4, in para (3) (i),—  
in line 11, for ":", read "—".
- (vi) in Serial No.-23, in column 4, in para (3)(i),—  
in line 5, after "articles", read "—".

**Page 2014—**

(21) in Schedule VI,—

in reading in the second column of the table,—

- (i) in line 4, for "individua", read "individual".

(ii) in Table, under "Administrators", para (i),—  
in line 1, for ":", read "—".

(iii) in Note below this Schedule,—

in line 8, for "invitations", read "invitations".

**Page 2015—**

(22) in Schedule vii,—

- (i) in Note 1, sub-para (a),—  
in line 3, after ":", read "and".

(ii) in Table, in column 3, against "Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food),—in sub-para (a),  
in lines 5 and 6, for "sorage", read "storage".

(iii) in Table, in column-3, insert, no : "3" opposite to no : "2" shown in column no : 2.

(iv) in Table, against "Condemnation of motor vehicles and motor cycles", in column 3,—in sub-table below para (a), under the sub-heading 'Kilometers',—  
for "20,00,000", read "2,00,000".

**Page 2016—**

(23) in Schedule VII, in Table,

in entry "Loss of Revenue", in column 3, against "(vi) Collector of Customs and Central Excise, Cochin",—

- (i) in sub-para (a),—  
in line 2, for "or", read "of"; and

in line 7, for "Excise", read "Excises".

- (ii) in sub-para (b),—  
for "cades", read "cases".

**Page 2017—**

(24) in Appendix below Schedule VII,—

- (i) in para 1(2),—

in line 5, for "Governor", read "Government".

- (ii) in para 11(1), in Note,—

in line 5, for "laid", read "paid".

[No. F.1(9)-E.II(A)/74]

S. K. DAS, Under Secy.

(व्यवहार)

रक्षा प्रधान

नई विली, 20 प्रैल, 1979

का० आ० 1518 :— राष्ट्रपति, केन्द्रीय विविध सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 34 के साथ पठित नियम 9 के उप नियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के बाण्ड (ब) तथा नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (रक्षा प्रधान) की अधिसूचना संख्या एम० आ० 629 तारीख 28 फरवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अधारित :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,— 1. साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III (अब वर्ग "ग") के भाग II में, शीर्षक "रक्षा लेखा विभाग" के प्रधान, स्तम्भ 1 में, विवाहान प्रविधिट "सभी अन्य पद" तथा स्तम्भ 2 से 5 तक की तस्वीरें अधिक्षियों के स्थान पर, स्तम्भ 1 से 5 तक में क्रमशः निम्नलिखित प्रविधियों द्वारा जाएंगी, अधारित :—

पद विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति अधिरोपित करने वाला सक्षम प्राधिकारी तथा उसके द्वारा अधिरोपित की जा सकने वाली शास्ति	अपील प्राधिकारी	
1	2	3	4	5

भाग II (वर्ग "ग"),

"कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक

(i) अनुभाग प्रधिकारी (लेखा)	रक्षा लेखा नियंत्रक	रक्षा लेखा नियंत्रक रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक अपेक्षा रक्षा लेखा उप-नियंत्रक	सभी	रक्षा लेखा महानियंत्रक (i) से (iv) रक्षा लेखा नियंत्रक
(ii) सभी अन्य पद	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक अपेक्षा रक्षा लेखा उप-नियंत्रक	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक अपेक्षा रक्षा लेखा उप-नियंत्रक रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक अपेक्षा लेखा प्रधिकारी/रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक अपेक्षा लेखा प्रधिकारी	**सभी स्वतंत्र उप कार्यालयों के प्रधारी (i) से (iv)	रक्षा लेखा नियंत्रक रक्षा लेखा महानियंत्रक उप कार्यालयों के प्रधारी (i) से (iv)

कार्यालय रक्षा लेखा महा नियंत्रक

सभी पद	रक्षा लेखा उप महानियंत्रक	रक्षा लेखा उप महानियंत्रक	सभी रक्षा लेखा महानियंत्रक
--------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

\*\* (प्रशासन अपेक्षा उप-कार्यालय के प्रधारी);

(II) साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग IV (अब वर्ग 'घ') के भाग III में शीर्षक "रक्षा लेखा विभाग" के प्रधान, स्तम्भ 1 में, विवाहान प्रविधि "सभी अन्य पद" तथा स्तम्भ 2 से 5 तक की तस्वीरें अधिक्षियों के स्थान पर, स्तम्भ 1 से 5 तक में क्रमशः निम्नलिखित प्रविधियों द्वारा जाएंगी, अधारित :—

पद विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	अधिरोपित करने वाला सक्षम प्राधिकारी तथा उसके द्वारा अपील प्राधिकारी अधिरोपित की जा सकने वाली शास्ति	प्राधिकारी	शास्ति
1	2	3	4	5

भाग III (वर्ग 'घ')

कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक

सभी पद	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक अपेक्षा रक्षा लेखा उप नियंत्रक	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक अपेक्षा **रक्षा लेखा उप-नियंत्रक	सभी	रक्षा लेखा नियंत्रक (i) से (iv) रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक अपेक्षा रक्षा लेखा उप-नियंत्रक
--------	--	--	-----	--

\*\*प्रशासन अपेक्षा उप कार्यालय के प्रधारी

@स्वतंत्र उप-कार्यालयों के प्रधारी

1

2

3

4

5

कार्यालय, रक्षा नेतृत्वा महा नियंत्रक—

सभी पद

रक्षा नेतृत्वा उप महा नियंत्रक,

रक्षा नेतृत्वा उप महानियंत्रक,

सभी

रक्षा नेतृत्वा महा नियंत्रक

रक्षा नेतृत्वा सहायक महानियंत्रक  
भ्रष्टाचार  
प्रशासन प्रत्युभाग में नेतृत्वा भ्रष्टिकारी } }  
प्रशासन प्रत्युभाग में नेतृत्वा भ्रष्टिकारी } }  
(i) से (iv) } }  
रक्षा नेतृत्वा उप महा नियंत्रक"

[सं. 360/सी/एस/79]

## (Department of Expenditure)

## (Defence Division)

New Delhi, the 20th April, 1979

**S.O. 1518.**— In exercise of powers conferred by sub-rule (2) of Rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of Rule 12, and sub-rule (1) of Rule 24, read with Rule 34 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Defence Division) No. S. R.O. 629, dated 28th February, 1965, namely :—

In the Schedule to the said Notification (I) in Part II, General Central Service Class III (now Group C) under the heading "Defence Accounts Department" for the existing entries " All other posts" in column 1 and the correspondence entries in Columns 2 to 5 the following entries shall respectively be substituted in Columns 1 to 5, namely :—

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose Authority	Appellate Authority Penalties	
1	2	3	4	5

## PART II (GROUP 'C')

"Office of the Controller of  
Defence Accounts.

(i) Section Officer (Accounts)	Controller of Defence Accounts.	Controller of Defence Accounts Joint Controller of Defence Accounts OR Deputy Controller of Defence Accounts	All **(i) to (iv)	Controller General of Defence Accounts. Controller of Defence Accounts
(ii) All other posts	Joint Controller of Defence Accounts OR Deputy Controller of Defence Accounts	Joint Controller of Defence Accounts OR **Deputy Controller of Defence Accounts	** All I/c. of independ- ent sub offices (i) to (iv)	Controller of Defence Accounts. Controller of Defence Accounts

OR

Accounts Officer

Office of the Controller General  
of Defence Accounts

All posts	Deputy Controller Gen- eral of Defence Accounts	Deputy Controller General of Defence Accounts	All	Controller General of Defence Accounts
-----------	--	--	-----	---

\*\*(in charge of Administration or a sub-office)"

(II) in Part III, General Central Service Class IV (now Group 'D'); under the heading "Defence Accounts Department" for the existing entries "All other posts" in column I and the corresponding entries in Columns 2 to 5 the following entries shall respectively be substituted to Columns 1 to 5 namely :—

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose and penalties which it may impose		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
<b>PART III (GROUP 'D')</b>				
"Office of the Controller of Defence Accounts All posts	Joint Controller of Defence Accounts OR Deputy Controller of Defence Accounts	Joint Controller of Defence Accounts OR ** Deputy Controller of Defence Accounts	** ALL	Controller of Defence Accounts
Office of the Controller General of Defence Accounts : All posts	Deputy Controller General of Defence Accounts.	Assistant Controller of Defence Accounts OR Accounts Officer/Asstt. Controller of Defence Accounts OR Accounts Officer	(i) to (iv) @	** Joint Controller of Defence Accounts OR Deputy Controller of Defence Accounts.

\*\*In charge of administration or a sub-office.

@In charge of independent sub-offices.

Office of the Controller General of Defence Accounts : All posts	Deputy Controller General of Defence Accounts.	Deputy Controller General of Defence Accounts Assistant Controller General of Defence Accounts OR Accounts Officer in the Administration Section.	All (i) to (iv)	Controller General of Defence Accounts. Deputy Controller General of Defence Accounts."
---	--	--	--------------------	--

[No. 366/C/S/79]

केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क : परिवहन बंगाल, कলकत्ता

कलकत्ता, 5 अप्रैल, 1979

सीमा शुल्क

कांग्रा० 1519.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहृतीय, परिवहन बंगाल, कलकत्ता के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेज/सेक्टर स्तर पर व्यापार सूचना सं० 23 सीमा 7 के० उ० 78 विनाक 2-2-78 के अधीन नये तिरे से पुनर्गठन तथा रचना करने के लिये परिवामस्वरूप समाहृती की प्रधिसूचना सं० 1/77-सीमा शुल्क, परिवहन बंगाल, दि० 17-11-77 में संलग्न तालिका में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

मनुसूची

(1) (2)

प्रधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, 60, 62, 64, 67, 68,  
केशोराम रेयन रेज नयासराय, बाक्साना तथा 69, 72।

सराय जिला हुगली

तथा

निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क,  
केशोराम रेयन सेक्टर, बाक्साना नयासराय,  
जिला हुगली

[अधिसूचना सं० 1/79 सी०स० VIII(40)-2-सीमा०/प०ब० 77]  
के०एस० मुखर्जी, समाहृती

68 GI/79-3

Office of the Collector of Central Excise & Customs :  
West Bengal

Calcutta, the 5th April, 1979

CUSTOMS

S.O. 1519.—Consequent on re-organisation and formation of new set up in Central Excise Range/Sector level of the Collectorate of Central Excise and Customs, West Bengal, Calcutta under Trade Notice No. 23/GL-7/CE/78 dated 2-2-78, the Schedule appended to Collector's Notification No. 1/77-Customs, West Bengal dated 17-11-77 is amended as below :—

SCHEDULE

1	2
Superintendent of Central Excise & Customs Kesoram Rayon Range at Nayasarai, P.O. Nayasarai, Dist. Hooghly.	60, 62, 64, 67, 68, 69, 72.
&	
Inspector of Central Excise & Customs Kesoram Rayon Sector P.O. Nayasarai, Dist. Hooghly.	

[Notification No. 1/79/C. No. VIII(40) 2 CUS/WB/77]  
K. L. MUKHERJI, Collector

## उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय

मद्रास, 19 अप्रैल, 1979

सीमा-शुल्क

का०आ० 1520.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उप-खण्ड (ग) खण्ड 152 के अन्तर्गत, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा) नहीं दिल्ली से जारी की गयी अधिसूचना संख्या 79 सीमा-शुल्क VII तारीख 18 जुलाई 1975 के प्रधानकारों का प्रयोग करते हुए उत्पाद शुल्क भमहार्ता, मद्रास, और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से अधिसूचना संख्या 37 सीमा शुल्क दिनांक 1 फरवरी 1963 के अनुमार के द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क समाहर्ता के कार्यालय के अन्तर्गत "सीमा-शुल्क समाहर्ता" भी नियुक्त है, तभिननाहु, राज्य के अधिकारी जिसे में हीसुर तालुक में "जुजूदाई गांव" को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत (1962 का 52) "भाण्डागार स्टेशन" घोषित करते हैं।

[सी० न० 8/40/3/79-सीमा शुल्क नीति]

माधव देवा, समाहर्ता

Office of the Central Excise Collectorate

Madras, the 19th April, 1979

CUSTOMS

S.O. 1520.—In exercise of the powers conferred by Notification 79/Customs VII dated 18th July, 1975 issued by the Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance), New Delhi under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, the Collector of Central Excise, Madras also appointed as "Collector of Customs" within the jurisdiction of the Madras Central Excise Collectorate by Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 37 Customs dated 1st February, 1963 hereby declare "Zuzuvadi" village, Hosur Tuluk in Dharmapuri District, Tamil Nadu State to be a "Warehousing Station" under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[C. No. VIII/40/3/79-CUS. POL.]  
M. G. VAIDYA, Collector

## वाणिज्य, नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नहीं दिल्ली, 30 अप्रैल, 1979

का० आ० 1521.—केन्द्रीय सरकार, चाप नियम, 1954 के नियम 3 और 4 के साथ पठित चाप अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

(i) सचिव, असम सरकार, उद्योग विभाग, असम सरकार, दिसपुर, को, संपूर्ण सचिव, असम सरकार, उद्योग विभाग, असम सरकार, दिसपुर, के स्थान पर और (ii) श्री सतीश चन्द्र ककोटी,

सम्पादक, असम बाणी, गोहाटी, असम, को उक्त धारा की उपधारा (1) के प्रधीन स्थापित चाप बोर्ड के सदस्यों के रूप में 31 मार्च, 1981 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, नियुक्त करती है, और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 622 (ग), तारीख 30-10-78 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त सूचना में:—

(क) मद 1 के सामने प्रथम स्तम्भ में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

सचिव, असम सरकार, उद्योग विभाग, असम सरकार, दिसपुर।

(ग) "उपभोक्ता द्वितीय का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति" के मामने विधान प्रविष्टि सं० 24 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

25. श्री सतीश चन्द्र ककोटी, सम्पादक, असम बाणी, गोहाटी, असम।

[सं० ई० 12012(1)/78-प्लॉट(ए)]

श्रीमती आदर्श मिश्र, उपसचिव

## MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLY AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 30th April, 1979

S.O. 1521.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) read with rule 4 and 5 of the Tea Rules, 1954, the Central Government hereby appoints (i) the Secretary to the Government of Assam, Department of Industries, Government of Assam, Dispur vice Joint Secretary to the Government of Assam, Department of Industries, Government of Assam, Dispur and (ii) Shri Satish Chandra Kakoti, Editor, Asom Bani, Gauhati, Assam, as members of the Tea Board established under sub-section (1) of the said section upto, and inclusive of, the 31st March, 1981, and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S. O. 622(E) dated 30-10-1978, namely :—

In the said notification :—

(a) for the entry in the first column against item 1, the following shall be substituted, namely :—

Secretary to the Government of Assam, Industries Department, Government of Assam, Dispur.

(b) After the existing entry No. 24 against "Persons representing Consumer interests", the following shall be added, namely :—

25. Shri Satish Chandra Kakoti, Editor, Asom Bani Gauhati, Assam.

[No. E-12012(1)/78-Plant. (A)]  
SMT. ADARSH MISRA, Dy. Secy.

(नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता विभाग) :—

## भारतीय मानक संस्था

नहीं दिल्ली, 1979-04-27'

का०आ० 1522.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन विभाग) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुभार भारतीय मानक संस्था की प्रांग से अधिसूचित किया जाता है कि जिस मानक विभाग की डिजाइन उसके शास्त्रीय विवरण तथा तस्वीरन्धी भारतीय मानक के शीर्षक संहिता नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वह भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किया गया है:

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन विभाग) प्रधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार यह मानक विभाग 1979-03-01 से सार्व होगा।

## प्रनुस्त्री

कम मानक चिह्न की उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी  
संख्या डिजाइन

तत्त्वज्ञानी भारतीय मानक की पद संख्या और मानक चिह्न की डिजाइन का शास्त्रिक विवरण

1. IS : 8259

प्राक्सीडीटॉन-मिथाइल पायसनीय  
तेज द्रवIS : 8259-1976 प्राक्सीडीटॉन पायसनीय  
तेज द्रव की विशिष्टि

भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें "ISI" शब्द होते हैं, संख्या (2) में दिक्काई गई तीली और प्रनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में विख्यात गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पद संख्या दी गई है।

[सं. सीएमडी/13 : 9]

## INDIAN STANDARDS INSTITUTION

(Department of Civil Supplies &amp; Co-operation)

New Delhi, the 1979-04-27

**S.O. 1522.**—In pursuance of sub-rules (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1979-03-01 :

## SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. IS : 8259	Oxydemeton-methyl emulsifiable concentrates	IS : 8259-1976 Specification for oxydemeton-methyl emulsifiable concentrates.		The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters "ISI", drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.



[No. CMD/13 : 9]

**का० आ० 1523.**—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि प्राक्सीडीटॉन मिथाइल पायसनीय तेज द्रव की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस प्रनुस्त्री में दी गई अधीरे के प्रनुस्त्र की गई है।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) 1952 और उसके अधीन द्वारा नियमों के तिमित यह मानक चिह्न 1979-03-01 से लागू होगी :

## प्रनुस्त्री

कम उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी सं०	तत्त्वज्ञानी भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक तेज चूर्ण	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
1. प्राक्सीडीटॉन मिथाइल पायसनीय तेज चूर्ण	IS : 8259-1976 प्राक्सीडीटॉन-मिथाइल पायसनीय तेज 100 लिटर चूर्ण की विशिष्टि	रु 15.00	

[मं. सी एम डी/13 : 10]

**S.O.1523.**—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fee(s) per unit for oxydemeton-methyl EC details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1979-03-01:

**SCHEDULE**

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Oxydemeton-methyl emulsifiable concentrates	IS: 8259—1976 Specification for oxydemeton-methyl emulsifiable concentrates.	100 Litres	Rs. 15.00

[No. CMD/13 : 10]

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1979

**का०आ० 1524.**—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 4 के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियम (3) उपविनियम (1) के अनुसार प्राप्त प्रधिकारों के प्रधीन यहां प्रमुखता में दिए गए भारतीय मानकों के संशोधन जारी किए गए हैं:

**अनुमति**

कम संशोधित भारतीय मानक की पद संख्या	जिस राजपत्र में भारतीय संशोधन की संख्या	संशोधन का संशित विवरण	संशोधन स्थान
सं०	मानक के निर्धारित होने और तिथि	होने की तिथि	
एवं शीर्षक	की सूचना छीं थी उसकी संख्या, तिथि एवं शीर्षक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. IS: 82—1973 रंग रोगन के विनरों तथा घोलकों के नमूने सेने तथा परीक्षण की पद्धतियां (प्रथम पुनरीक्षण)	—	संख्या, 1 जून, 1976	(पृष्ठ 11, सारणी 2, खाता 2, अस्ति वर्णन)—"0.51" के स्थान पर "0.5" कर लें।	संशोधन का संशित विवरण	संशोधन स्थान
2. IS: 226—1975 सरखना इस्पात (मानक किस्म) की विशिष्ट (पांचवा पुनरीक्षण)	—	संख्या, 1 अप्रैल, 1976	(पृष्ठ 6, खंड 6-1) खंड के अंत में निम्न विषय जोड़ें: ‘सेक्षण होने पर विकल्प रूप में नमूने जाल से लिए जा सकते हैं।	संशोधन का संशित विवरण	संशोधन स्थान
3. IS: 278—1969 बांड के लिए यात्व-सीक्षण की कटिदार तार की विशिष्ट (द्वितीय पुनरीक्षण)	एस०ओ० 639 विनाक 1970-02-21	संख्या, 4 अगस्त, 1975	खंड ए-2-2 में संशोधन किया गया है।	संशोधन का संशित विवरण	संशोधन स्थान
4. IS: 628—1963 साइकिल की पेंडल जड़त की विशिष्टि (पुनरीक्षण)	एस०ओ० 1760 विनाक 1963-06-29	संख्या 4 जनवरी, 1976	खंड 5-2 तथा आकृति 4 के स्थान पर नए विए गए हैं।	संशोधन का संशित विवरण	संशोधन स्थान
5. IS: 630—1961 साइकिल की तीसियों (सारी) तथा तीली तिपलों की विशिष्टि (पुनरीक्षण)	एस०ओ० 553 विनाक 1963-03-02	संख्या, 5 जनवरी, 1976	1. आकृति 1 संशोधित की गई है; 2. खंड 3.1.1 के स्थान पर तथा खंड दिया गया है; 3. पृष्ठ 4 (रिप्रिट का पृष्ठ 6) सारणी 1, जाना 8, प्रथम वर्णन—"1.723" के स्थान पर "1.783" कर लें। 4. पृष्ठ 4 (रिप्रिट का पृष्ठ 6) सारणी 1, "साकेतिक लम्बाई" शीर्षक को उसके नीचे के इन्वराज के साथ हटाएं।	संशोधन का संशित विवरण	संशोधन स्थान

1	2	3	4	5	6
6.	IS: 648-1970 चुम्बकीय सरकिंडों एस०ओ० 1107 के लिए अनश्वेरियटेड विद्युत इस्पात दिनांक 1971-03-20 चहरों की विशिष्टि (वित्तीय पुनरीक्षण)	संख्या 1, जूलाई 1975	1. खंड 8.5.3 के विद्यमान कार्मुका के स्थान पर नया कार्मुका दिया गया है। 2. सारणी 4 में संशोधन किया गया है।	1975-07-31	
7.	IS: 661-1974 शीत भंडारों के उष्मा रोधन की रीति संहति (वित्तीय पुनरीक्षण)	—	संख्या 1, जून, 1976	(पृष्ठ 7, सारणी 1, (*) चिन्ह वाली पाद टिप्पणी) — विद्यमान पाद टिप्पणी के स्थान पर निम्न टिप्पणी कर लें : "IS: 4671-1968 उष्मा रोधन के लिए कूले पालीस्टाइरीन की विशिष्टि के अनुकूल कूला पालीस्टाइरीन इस्तेमाल किया जाए।"	1976-06-30
8.	IS: 723-1972 इस्पात की ग्रु-खनित तिर चाली तार की कीलों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	एस०ओ० 2015 दिनांक 1975-07-28	संख्या 1, सितम्बर, 1975	(पृष्ठ 1, सारणी) "प्रथम पुनरीक्षण" के स्थान पर "वित्तीय पुनरीक्षण" कर लें।	1975-09-30
9.	IS: 1239 (भाग 1)~1973 मृदु एस०ओ० 776 इस्पात की नलियों नालिकाकार वस्तुओं दिनांक 1976-02-21 तथा अन्य पिटवां इस्पात की फिटिंग की विशिष्टि भाग 1 मृदु इस्पात की नलियों (तीसरा पुनरीक्षण)	—	संख्या 2, जून, 1976	1. खंड 2.3 के पश्चात नोट 1.2 तथा 1976-06-30 3. जोड़े गए हैं 2. (पृष्ठ 13, खंड 14.4.1, पंक्ति 3) "फैनाव" शब्द के बाद "जिना दरार" शब्द जोड़ें।	
10.	IS: 1283-1968 साइकिल के कीच्छील तथा जेन की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	—	संख्या 2, नवम्बर, 1975	1. खंड 3.2 के स्थान पर एक नया खंड दिया गया है, तथा 2. (पृष्ठ 4, (8) चिन्हांकित पैरा के साथ वाली पाद-टिप्पणी) हटा दें।	1975-11-30
11.	IS: 1322-1970 जल रोक तथा एस०ओ० 120 नमी सह बनाने के लिए बिटुमेन नमदों दिनांक 1973-01-13 की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	—	संख्या 1, फरवरी, 1976	1. खंड 3.2.1 के स्थान पर नया खंड दिया गया है 2. (पृष्ठ 5, (*) चिन्हांकित पाद-टिप्पणी) विद्यमान पाद-टिप्पणी के स्थान पर निम्न टिप्पणी कर लें : भारतीय टाटा की विशिष्टि (भाग 2)---16 प्रतिशत द्रव्य लाभ की निविदा पर 305 तथा 229 ग्राम/मी <sup>2</sup> 3. सारणी 1 ते 2 में संशोधन किया गया है। 4. खंड ए-2.4.1 के विद्यमान कार्मुके के स्थान पर नया कार्मुका दिया गया है। 5. नई सामग्री (ई) "झी" के पश्चात जोड़ी गई है।	1976-02-29
12.	IS: 1556-1967 कंकोट प्रदलन के एस०ओ० 3961 लिए सहज खिची इस्पात के तार की विशिष्टि जास्ती की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	एस०ओ० 3961 दिनांक 1968-11-09	संख्या 1, अप्रैल, 1976	1. खंड 11.3 के स्थान पर नया खंड दिया गया है। 2. (पृष्ठ 7, ±चिन्हांकित पाद टिप्पणी) विद्यमान पाद टिप्पणी के स्थान पर निम्न टिप्पणी कर लें : "इस्पात के तार की उत्कम नमन परीक्षण पद्धति (प्रथम पुनरीक्षण)"	1976-04-30
13.	IS: 1697-1974 एरियोजीन खाद्य एस०ओ० 424 में की विशिष्टि दिनांक 1975-02-15 (प्रथम पुनरीक्षण)	—	संख्या 1, मई, 1976	1. (पृष्ठ 7, खंड ए-1.3, पंक्ति 6) "एलो-राइड" के स्थान पर "हाइड्रोफ्लाइड" कर लें। 2. (पृष्ठ 5, खंड 3.2 (ए) -विद्यमान सामग्री के स्थान पर निम्न कर लें : (क) शब्द "खाद्य रंग"	1976-05-31
14.	IS: 1711-1970 स्वयं बन्द होने एस०ओ० 1277 वाले टोटियों की विशिष्टि दिनांक 1972-05-27 (प्रथम पुनरीक्षण)	—	संख्या 1, अप्रैल, 1976	(पृष्ठ 4, खंड 5.1, पंक्ति 1) "गुरुत्वाकरण शमिल तथा आई" शब्द हटा दें।	1976-04-30

1	2	3	4	5	6
15.	IS : 1848-1971 लिखने तथा चिन्ह- कारी कागजों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	एस०ओ० 2975 दिनांक 1973-10-13	संख्या 2, मार्च, 1976	उद्योग तथा नागरिक पूर्वि मंत्रालय भारत सरकार ने प्रतिवार्ष कर दिया है कि कागज के जो कारब्राने सहेद मूद्रण कारब्रा शीक्षिक तथा मरकारी कागजों के लिए यह रहे हैं, वे उम्मे 0.003 प्रतिशत नावन- दार हरे रंग को आमा देंगे तकि इन प्रकार के कागज के लिए भावा ०। इसा प्रमाणत प्रतिवार्ष है इनकि भारतीय मानक में इस प्रकार आमा देने का राज- धान करने के लिए यह संशोधन जारी किया जा रहा है। (पृष्ठ 1, खंड 3, 6 खंड 3, 6 के पश्चात)	1976-03-31
16.	IS : 1867-1975 रबड़ की गरम पानी की बोतलों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 मई, 1976	निम्न तथा खंड जोड़ : “3.7 मर्फें छाई का कागज देविए (गारणी 1 का कप संख्या 17) पर भी आमा दी जाए आमायुक्त आमा उग रंग से अधिकाधिक मिली होगी जिसकी स्पीड्डिटि संख्या की ओर से ममय समय पर दी जाती रहेगी। इस प्रकार आमायुक्त वागज में जमक सम्बन्धी भरेका नहीं लागू होगी।	
17.	IS : 1891-(भाग II)-1972 बाहकों एस०ओ० 423 तथा एलिवेटरों के रबड़ के पट्टों की दिनांक 1975-02-15 विशिष्टि भाग 2 तापरोधी पट्टे	—	संख्या 1 फरवरी, 1976	(पृष्ठ 5, खंड 3, 4, 3, पंक्ति 3) “20 प्रतिशत” के स्थान पर “80 प्रतिशत” कर लें।	1976-05-31
18.	IS : 1891-(भाग 4)- 1971 रबड़ एस०ओ० 510 बाहकों तथा एलिवेटरों के रबड़ के दिनांक 1974-02-23 पट्टों की विशिष्टि भाग 4 स्वास्थ्य पट्टे	—	संख्या 1 सितम्बर, 1975	खंड 3, 1, 2 तथा 6, 4 हटा दिया गया है। 2. (पृष्ठ 7, खंड 6, 3) “ $100 \pm 10\%$ ” के स्थान पर “ $70 \pm 10\%$ ” बदल लें।	1975-09-30
19.	IS: 1977-1975 संरचना इस्पात (माध्यारण किस्म) की विशिष्टि (धूमरा पुनरीक्षण)	—	संख्या, 1 जून, 1976	1. सारणी 1 के स्थान पर एक नई सारणी दी गई है। 2. खंड 6, 1 में संशोधन किया गया है।	1976-06-30
20.	IS : 2201-1973 समंजनीय ऊचाई बाली मर्जों के साथ लगी खड़े नक्के बाली मिलिंग मरीन का परीक्षण चार्ट (प्रथम पुनरीक्षण)	—	संख्या, 1 मई, 1976	पृष्ठ 10, खाना 2 में आकृति के स्थान पर नई आकृति दी गई है।	1976-05-31
21.	IS: 2232-1967 ब्रॉडवार बाली एम० ओ० 4562 तथा कैसेल डिवरियों की विशिष्टि दिनांक 1967-12-23 (प्रथम पुनरीक्षण)	—	संख्या, 3 जनवरी, 1976	सारणी (1) में संशोधन किया गया है।	1976-01-31
22.	IS : 2269-1967 पट्टोंकोण सॉकेट-वार एम० ओ० 4633 टोपी बाली पेंच की विशिष्टि दिनांक 1967-12-30	—	संख्या, 1 फरवरी, 1976	सारणी 1, 2 तथा 3 में संशोधन किया गया है।	1976-02-29
23.	IS : 2315-1963 तार के रस्तों के एस०ओ० 2038 लिए ब्रॉडस्ताने (चिक्कल) की विशिष्टि दिनांक 1963-07-20	—	संख्या, 1 जून, 1976	संख्या, 1 के स्थान पर नया खंड दिया गया है।	1976-06-30
24.	IS : 2510 (भाग 2/अनुभाग 2) -- एस०ओ० 1081 1965 ए सी धारा सकिं ब्रेकर की विशिष्टि भाग 2 परीक्षण अनुभाग 2,1000 से 11000 बोल्ट तक बोल्टसा के लिए	—	संख्या, 2 मार्च, 1975	1. (पृष्ठ 30, खंड ए-4, 4) इस खंड को हटा दें तथा आद के खंडों की संख्या ठीक कर लें। 2. खंड ए-4, 3 के पश्चात एक टिप्पणी जोड़ी गई है।	1975-10-31

1	2	3	4	5	6
25. IS : 2558-1974	पांती 4 आर. एस०ओ० 424 खाद्य येड की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	दिनांक 1975-02-15	संख्या, 2 मई, 1976	1. सारणी 1 तथा खंड 3.2 (ए) में संशोधन किया गया है। 2. (पृष्ठ 6, खंड 3.2 जी) "जी" के पश्चात् निम्न सामग्री जोड़ दें : "एच" विद्यमान प्रमुख रंजक मध्य जात पदार्थों के नाम 3. परिणिष्ट "ए" के पश्चात् परिणिष्ट 'बी' जोड़ दिया गया है। 4. (पृष्ठ 8)—पृष्ठ के नीचे निम्न पाद टिप्पणी जोड़ दें : "ए" प्रमरेन्य, खाद्ययेड के लिए विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	1976-05-31
26. IS : 2762-1964	तार के रस्मों के एस०ओ० 226 स्लिंगों तथा स्लिंग पादों की विशिष्टि दिनांक 1965-01-16		संख्या, 3 जून, 1976	(पृष्ठ 23, सारणी 4, कालम 5, ग्रीष्मिक) "हुक की भार असता" के स्थान पर "केन के हुक की भार असता" कर लें।	1976-06-30
27. IS : 2831-1975	संरचना इस्पात (भाधारण किम्म) में पुनर्वेलवन के निए कार्बन इस्पात के बिलेट, ब्लूम, और मिल्नी की विशिष्टि (इमग पुनरीक्षण)		— संख्या, 1 जून, 1976	1. (पृष्ठ 8, खंड 7.1 पंक्ति 1) ब्लूम तथा स्लेट शब्द हटा दें। 2. खंड 7.1 के पश्चात् नया खंड 7.2 जोड़ा गया है तथा विद्यमान खंड 7.2 की संख्या 7.3 कर दी गई है।	1976-06-30
28. IS : 3966-1964	भीतरी सूखम मापियों (जिनमें स्टिक सूखम मापी भी शामिल है) की विशिष्टि	एस०ओ० 1501 दिनांक 1965-05-08	संख्या, 1 जून, 1976	1. खंड 3.2 तथा 9.2 में संशोधन किया गया है। 2. पृष्ठ 5, तथा 9 पर विद्यमान पाद टिप्पणियां नई पाद टिप्पणी से बदल दी गई हैं।	1976-06-30
29. IS : 2026-1968	विशुल लेपन के एम०ओ० 3728 निए बंग-मवण की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	दिनांक 1969-09-13	संख्या, 1 जून, 1976	सारणी 2 के स्थान पर नई सारणी दी गई है।	1976-06-30
30. IS : 3196-3974	अल्प दाढ़ द्रवणीय गंतों के लिए 5 लिटर से प्रधिक जल समाई वाले बेलडकूत अल्प कार्बन इस्पात के गैस सिलिंडर की विशिष्टि (इमग पुनरीक्षण)		— संख्या, 1 अक्टूबर, 1975	1. खंड 8.1 का संशोधन किया गया है 2. खंड 9.1 तथा 11.1 (ए) के स्थान पर नई सामग्री दी गई है।	1975-10-31
31. IS : 3196-1974	अल्प दाढ़ द्रवणीय गंतों के लिए 5 लिटर से प्रधिक जल समाई वाले बेलडकूत अल्प कार्बन इस्पात के गैस सिलिंडर की विशिष्टि (इमग पुनरीक्षण)		— संख्या, 2 मार्च 1976	खंड 11.2.1 के प्रथम पैरा के स्थान पर नया पैरा दिया गया है।	1976-03-31
32. IS : 3224-1971	संपीड़ित गैस एस०ओ० 120 सिलिंडरों के लिए बाल्व फिटिंग की विनांक 1973-01-13 विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)		संख्या, 3 मार्च 1976	1. खंड 1.2 तथा 5.1.1 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं। 2. (पृष्ठ 12, सारणी 4) "मियाइल ओमाइड" तथा इसके सामने के सब हैन्दराज हटा दें। 3. सारणी 3 का संशोधन किया गया है।	1976-04-30
33. IS : 3498-1975	धातुनु की मेजों (कार्यालय बाजारी) की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)		— संख्या, 1 जून, 1976	1. (पृष्ठ 7, खंड 5.3 (भी) IS : 2932- 1964 प्रथम : 2933-1964 के स्थान पर IS : 151-1950 कर लें।	1976-06-30

1	2	3	4	5	6
34.	IS : 3498-1966 धातु की कुर्सियों एस०ओ० 2602 दिनांक संख्या 3 (कार्यालय मार्ग) की विशिष्टि (प्रथम 1966-08-27 पुनरीक्षण			2. (पृष्ठ 7, पाद टिप्पणियों) विषमान “६ तथा “८” चिह्न वाली पाद टिप्पणियों के स्थान पर निम्नविविल कर लें : सामान्य कार्यों के लिए वांछित रंग के फिलिं देने, स्प्रे बरने, स्टोव विधि इनैमल वाले नैयार मिश्रित रंग रोगन की विशिष्टि - खंड 1. १ के स्थान पर नया खंड दियागया 1976-03-31 है ।	
35.	IS : 4097-1967 नल कूर्सी में पैक एस०ओ० 1720 दिनांक संख्या 1 के लिए कंकड़ की विशिष्टि 1968-05-18			1. (पृष्ठ 4, खंड 4. 1 अनौपचारिक मारणी 1976-06-30 संख्या 6) इसका अन्दराजांरं महित हटा दें । 2. खंड 4. 2 तथा 0. 1 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं । 3. (पृष्ठ 4, खंड 6) “ऐक्वीफरैक रेशियों” के स्थान पर “पैक ऐक्वीफरैक रेशियों” बदल लें ।	
36.	IS : 4119-1967 लकड़ी के कोयले एस०ओ० 4062 दिनांक संख्या 1 वाली इस्त्रियों की विशिष्टि 1967-12-23 प्रत्रैल, 1976			1. मारणी 1 संशोधित की गई है । 1976-04-30 2. खंड 5. 1. 1, 5. 3. 1 तथा 5. 3. 3 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं । 3. खंड 6. 1. 1 में टिप्पणी के बाद पाद टिप्पणी जीड़ी गई है । 4. खंड 6. 1 के प्रथम वाक्य के स्थान पर नया वाक्य दिया गया है । 5. खंड 5. 1 पृष्ठ 7 में “साइज” शब्द के पश्चात् एक वाक्य जोड़ा गया है ।	
37.	IS : 4204-1974 ड्राफ्टिंग कुर्सियों एस०ओ० 988 दिनांक की कार्यपारक अपेक्षाएँ (प्रथम पुनरीक्षण) 1976-03-06			1. (पृष्ठ 6, खंड 4. 3)-IS : 814-1970” 1976-06-30 के स्थान पर IS : 814 (भाग 1)-1974” कर लें । 2. (पृष्ठ 6, पाद टिप्पणियों) II(चिन्हांकित पाद टिप्पणी के स्थान पर निम्न टिप्पणी बदल दें : भंगचना इस्पात के धातु शार्कोवैलिंग के लिए लाग चड़े हलैट्ड्राइ. की विशिष्टि भाग- 1- जादरों को छोड़ कर अन्य उत्पादों की वैलिंग (जैवा पुनरीक्षण)	
38.	IS : 4654-1974 वैराफीम मोम की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 प्रत्रैल, 1976	मारणी 1 में संशोधन किया गया है । 1976-04-30	
39.	IS : 4964 (भाग 2)-1975 साली दुनी सूती बनियामों की विशिष्टि भाग 2 बनियामों (प्रथम पुनरीक्षण)	—	संख्या 1 जून, 1976	1. मारणी 1 तथा 3 में संशोधन किया गया है । 1976-06-30 2. (पृष्ठ 9 तथा 10) सारणी 4 व 5 खाना 3)-दोनों सारणियों में से बनियाम की लम्बाई जाने के पश्चात् “*” चिह्न हटा दें । 3. खंड 0. 4 के पश्चात् खंड 0. 5 जोड़ा गया है ।	
40.	IS : 4985-1968 भरने के पानी की एस०ओ० 3110 दिनांक “सूलाई” के लिए अनन्यकृत पीबीसी 1970-02-07 प्राइंटों की विशिष्टि		संख्या 4 प्रत्रैल, 1976	1. खंड 6. 1 तथा 7. 2 हटा दिए गए हैं तथा बाद के खंडों की संख्या तीव्रमार्टीकार की गई है । 2. (पृष्ठ 17 जैवे रिप्रिट का पृष्ठ 16) खंड ४-2. 1 (ई), पृष्ठ 1)-“120” “वी” ब्लाक के स्थान पर “120 डलबी इस्पात वी ब्लाक कर लें ।	1976-04-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41. IS : 4995 (भाग 2)—1974 बालेश्वर तथा चूर्ण भास्मप्री के भंडारण के लिए प्रबलित कंकाल के बिन की विजाइन को कस्तीटिया भाग 2 विजाइन कस्तीटिया (प्रथम पुनरीक्षण)	—	संख्या 1, जून, 1976	1. (पृष्ठ 13, खंड 5. 3, 5. 4, "एन" की व्याख्या के सामने)—"0.003" के स्थान पर "0.003" कर लें। 2. (पृष्ठ 16, खंड 5. 7. 3, पंक्ति 4)—"26 प्रतिशत" के स्थान पर "2. 5 प्रतिशत" कर लें।	1976-06-30	
42. IS : 5502-1969 विकाने परिवर्त्ये थाले एस० औ० 5032 सहृदय कूटने के डीजल इंजन की विशिष्ट विनांक 1971-11-06	संख्या 1 नवम्बर, 1975	1. (पृष्ठ 10, सारणी 2, आना 3 का वीर्वक) "मिन" हटाएं। 2. खंड 16. 1 तथा 17. 1 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं। 3. (पृष्ठ 11, खंड 17. 2, दूसरा बाक्य) —हटा दें। 4. (पृष्ठ 13, खंड 28. 1 (जी) "सम्पर्क दबाव" के स्थान पर "आहत दबाव" कर लें। 5. (पृष्ठ 13, खंड 2. 6. 1 (एस०) —यह भव हटा दें।	1975-11-30		
43. IS : 5513-1969 विकाने यंत्र की विशिष्ट	एस० औ० 1387 विनांक 1975-05-03	संख्या 1, नवम्बर, 1975	1. (पृष्ठ 4, सारणी 1, ऋम संख्या 8, आना 2) "मोल्ड ई" के स्थान पर "मोल्ड ई, मोल्ड ई 1 तथा क्लैम्पिंग रिंग" कर लें। 2. खंड 4. 5 के बाद खंड 4. 5. 1 जोड़ा गया है।	1975-11-30	
44. IS : 6178-1971 कठोर किनारे थाले एस० औ० 3055 जै-पीनों की विशिष्ट तथा सुरक्षा-अपेक्षाएं विनांक 1973-10-27	संख्या 1, जून, 1976	1. पृष्ठ 4, खंड 3. 1. 4 (वी) IS : 2932-1964 के स्थान पर IS : 51-1950 कर लें। 2. (पृष्ठ 4 त्रि "चिन्हांकित पाद टिप्पणी) त्रि चिन्हांकित पाद टिप्पणी के स्थान पर निम्न टिप्पणी कर लें: "सामान्य कार्यों के लिए बाल्छित रंग के किनारे बनें, स्त्रों करें, स्टोव विशिष्ट हैनेमल थाले तेमार पिंकित रंग दोगन की विशिष्ट"	1976-06-30		
45. IS : 6235-1971 फैरा चुम्बकीय एस० औ० 231 प्राक्सिसिल्डों तथा सम्बद्ध भागों से बने विनांक 1974-01-26 पाट-कोर्टों के परिणाम	संख्या 2, जून, 1976	सारणी 1 संशोधित की गई है	1976-06-30		
46. IS : 6297 (भाग 1) (1971 हैलीक्स्ट्रा- एस० औ० 3255 निकी साज सामान के ट्रांसफोर्मर और विनांक 1974-11-24 प्रेरित (पावर शक्ति, स्पंद और स्विच थाले) की विशिष्ट भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं और परीक्षण	संख्या 3, मई 1976	1. खंड 6. 2. 17 में संशोधन किया गया है। 2. खंड 6. 2. 3. 2 के पश्चात खंड 6. 2. 3. 3 जोही गई है तथा बाद के खंडों तथा आकृतियों की संख्याएं जहां भी हों ठीक कर ली जाएं।	1976-05-31		
47. IS : 6315-1971 भारी द्वारों के लिए एस० औ० 510 (इव नियंत्रित) कार्ब स्ट्रिंगों की विशिष्ट विनांक 1974-02-23	संख्या 1 अगस्त, 1975	1. (पृष्ठ 4, खंड 2. 6, पंक्ति 2)—"द्वार" खंड हटा दें। 2. आकृति 1 के स्थान पर नवी आकृति दी गई है। 3. खंड 7. 2. 8. 1, तथा 8. 4 के स्थान पर नये खंड दिए गए हैं। 4. (पृष्ठ 8, खंड 2, पंक्ति 2)—"2 सैकंड" के स्थान पर "20 सैकंड" कर लें।	1975-08-31		

1	2	3	4	5	6
48. IS : 7142-1974 अल्प वाल इवलीय एस० औ० 776	गैसों के लिए 5 लिटर से कम जल समाई दिनांक 1976-02-21	संख्या 1, मित्रमार, 1975	1. खंड 5. 1. 3 तथा 9. 1 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं। 2. (पृष्ठ 10, खंड 8. 1, पहला वाक्य) विद्यमान पहले वाक्य के स्थान पर निम्न वाक्य कर लें।	1975-09-30	
	वाले बेलडक्ट अल्प कार्बन इस्पात के गैस सिलिंडर की विशिष्ट		“प्रत्येक तान उपचारित सिलेंडर का प्रथमैतिक परीक्षण किया जाएगा।		
49. IS : 7142-1974 अल्प वाल इवलीय एस० औ० 776	गैसों के लिए 5 लिटर से कम जल समाई विनांक 1976-02-21	संख्या 2, मार्च, 1976	3. (पृष्ठ 11, खंड 11. 1 “ए” )—विद्यमान पाठ के स्थान पर निम्न कर लें।	1976-03-31	
	समाई वाले बेलडक्ट अल्प कार्बन इस्पात के गैस सिलिंडर की विशिष्ट		“क” समाव वरीक्षण प्लेट सामर्थी पर एक लम्बाई की दिशा में तथा एक तिरक्षी दिशा में		
50. IS : 7394-1974, 5 लिटर तक सक्रियता का इधन के पेट्रोलियम रिजर्व इधन के लिए उच्च घनत्व पाली-इयाहसीन के घर्ता (जेरी इन्हों) की विशिष्ट	—	संख्या 1, मार्च, 1976	1. खंड 3. 1. 1 तथा 3. 1. 2 संजोधित किए गए हैं। 2. (पृष्ठ 4, पाद टिप्पणी, पंक्ति 3) विद्यमान पाद टिप्पणी के स्थान पर निम्न कर लें : “सांचा डलाई तथा एसट्रजन के लिए उच्च घनत्व पौलीइयाहसीन सामग्रियों की विशिष्ट	1976-05-31	
51. IS : 7430-1974 फेरोन्यूकीय आकस्माइनों के बने पेंच कोरों के माप	—	संख्या 1, जून, 1976	मार्गी संजोधित की गई है	1976-06-30	
52. IS : 7460-1974 गावतुम रोलर बेयरिंग के लिए छूटें	—	संख्या 1, जुलाई, 1976	खंड 3 के घटीन आकृतियों के स्थान पर नयी आकृति दी गई है।	1976-07-31	
53. IS : 7461-1974 गावतुम रोलर बेयरिंगों की सीमा-परिमापों का सामान्य नक्शा	—	संख्या 3, जुलाई, 1976	खंड 3. 1 के घटीन आकृतियों के स्थान पर नयी आकृति दी गई है।	1976-07-31	
54. IS : 7634 (भाग 3)—1975 भरने के पारी की समाई के लिए प्लास्टिक पाइप कार्य की रीति संहिता भाग 3 अनन्यकृत पीढ़ीसी पाइपों का लगाना तथा उनमें जोड़ देना	—	संख्या 2, मार्च, 1976	1. खंड 2. 2. 4. 2 (बी) में संजोधन किया गया है। 2. (पृष्ठ 6, खंड 2. 2. 4. 1 (बी), पंक्ति 3)—“एंड” के स्थान पर “एंड” कर लें। 3. (पृष्ठ 7, खंड 2. 2. 4. 2(बी) “5”, पंक्ति 1) “हॉट” शब्द के स्थान पर “नॉट” कर लें।	1976-05-31	
55. IS: 7741 (भाग 1)—1975 साउड सीकरों की विशिष्ट भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं तथा परीक्षण	—	संख्या 1, जून, 1976	(पृष्ठ 18, खंड 4. 1 अनीपचारिक सारणी भूतिम पंक्ति) —हुटा दें।	1976-06-30	

इन भारतीय मानकों की प्रतियां विभी के लिए भारतीय मानक संस्था, मानक भवन 9 बहादुरगाह अफर मार्ग, नई बिल्ली-110002, में तथा इसके नामकारी कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता बंडेगां, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, पटना और विवेन्द्रम में उपलब्ध हैं।

New Delhi, the 24th April, 1979

**S.O. 1524.**—In pursuance of regulation 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed have been issued under the powers conferred by the sub-regulation (1) of Regulation 3 of the said Regulations.

## SCHEDULE

Sl. No. and title of the Indian Standard No. amended	No. and Date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian Standard was notified	No. and Date of the Amendment	Brief particulars of the Amendment	Date from which the amendment shall have effect	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. IS : 82-1973 Methods of sampling and test for thinners and solvents for paints (first revision).	—	No. 1 June 1976	(Page 11, Table 2, col 2, last Line)—Substitute '0.5' for '0.51'.	1976-06-30	
2. IS : 226-1975 Specification for structural steel (Standard quality) (Fifth revision)	—	No. 1 Apr 1976	(Page 6, clause 6.1)—Add the following matter at the end of the clause : 'Alternatively, in case of sections, the samples may be taken from the web.'	1976-04-30	
3. IS : 278-1969 Specification for galvanized steel barbed wire for fencing (second revision)	S.O. 639 dated 1970-02-21	No. 4 Aug 1975	Clause A-2.2 have been amended.	1975-08-31	
4. IS : 628-1963 Specification for bicycle pedal assembly (Revised)	S.O. 1760 dated 1963-06-29	No. 4 Jan 1976	Clause 5.2 and Fig. 4 have been substituted by new ones.	1976-01-31	
5. IS : 630-1961 Specification for bicycle spokes (plain) and nipples for spokes (Revised)	S.O. 553 dated 1963-03-02	No. 5 Jan 1976	(i) Fig. 1 has been amended; (ii) Clause 3.1.1. has been substituted by a new one; (iii) [Page 4] (Page 6 of the Reprints), Table 1, col 8, first row)—Substitute '1.783' for '1773'. (iv) [Page 4 (page 6 of the Reprints), Table 1]—Delete column heading 'NOMINAL LENGTH' along with entries under it.	1976-01-31	
6. IS : 643-1970 Specification for non-oriented electrical steel sheets for magnetic circuits (second revision)	S.O. 1107 dated 1971-03-20	No. 1 Jul 1975	(i) Existing formula of clause 8.3.5 has been substituted by a new one and (ii) Table 4 has been amended	1975-07-31	
7. IS : 661-1974 Code of practice for thermal insulation of cold storages (second revision)	—	No. 1 Jun 1976	[Page 7, Table 1, foot-note with asterisk (*) mark]—Substitute the following for the existing foot-note :  Expanded polystyrene, conforming to IS - 4671-1968, Specification for expanded polystyrene for thermal insulation purposes, shall be used.'	1976-06-30	
8. IS : 723-1972 Specification for steel countersunk head wire nails (first revision)	S.O. 2015 dated 1975-06-28	No. 1 Sep 1975	(Page 1, Title)—Substitute '(Second Revision)' for '(First Revision)'.	1975-09-30	
9. IS : 1239 (Pt I)—1973 Specification for mild steel tubes, tubulars and other wrought steel fittings part I mild steel tubes (Third revision)	S.O. 776 dated 1976-02-21	No. 2 Jun 1976	(i) Notes 1, 2 & 3 have been added after clause 2.3. and (ii) (Page 13, clause 14.4.1, line 3)—Add the words 'without cracking' after the word 'expansion'.	1976-06-30	
10. IS : 1283-1968 Specification for bicycle free-wheels and chains (first revision)	—	No. 2 Nov 1975	(i) clause 3.2 has been substituted by a new one and (ii) (Page 4, foot-note with paragraph (\$) sign—Delete the foot-note.	1975-11-30	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. IS : 1322-1970 Specification for bitumen felts for water-proofing and damp-proofing (second revision)	S.O. 120 dated 1973-01-13	No. 1 Feb 1976	(i) clause 3.1.2. has been substituted by a new one; (ii) [Page 5, foot-note with (*) mark] Substitute the following for the existing foot-note : “Specification for Indian hessian : Part 11 305 and 229 g/m <sup>2</sup> at 16 percent contract regain.” (iii) Tables 1 and 2 have been amended (iv) Existing formula of clause A-2.4.1 has been substituted by a new one. (v) New matter(e) has been added after (d)	1976-02-29	
12. IS : 1566-1967 Specification for hard-drawn steel wire fabric for concrete reinforcement (first revision)	S.O. 3961 dated 1968-11-09	No. 1 Apr 1976	(i) clause 11.3 has been substituted by a new one. (ii) (Page 7, foot-note with ‘†’ mark)—Substitute the following for the existing foot-note : ‘†Method for reverse bend testing of steel wire (first revision);	1976-04-30	
13. IS : 1697-1974 Specification for erythrosine, food grade (first revision)	S.O. 424 dated 1975-02-15	No. 1 May 1976	(i) (Page 7, clause A-1.3, line 6)—Substitute ‘hydroxide’ for ‘chloride’. (ii) [Page 5, clause 3.2(a)]—Substitute the following for the existing matter : (a) The words ‘FOOD COLOUR’.	1976-05-31	
14. IS : 1711-1970 Specification for self-closing taps (first revision)	S.O. 1277 dated 1972-05-27	No. 1 Apr 1976	(Page 4, clause 5.1, line 1)—Delete the words ‘gravity and die’.	1976-04-30	
15. IS : 1848-1971 Specification for writing and painting papers (first revision)	S.O. 2975 dated 1973-10-13	No. 2 Mar 1976	The Government of India, Ministry of Industry and Civil Supplies has made it obligatory that the paper mills producing white printing paper for educational and Government purposes shall tint the paper with 0.005 per cent of brilliant green dye. To provide for the above provision of tinting under the Indian Standard, this Amendment is being issued in view of the compulsory ISI Certification Marking for this type of paper.  [Page 4, clause 3.6)—Add the following new clause after 3.6: ‘3.7 White printing paper [see Sl. No. (xvii) of Table 1] may also be tinted. In the case of tinted paper the colour shall be a close match to the shade approved by the Institution from time to time. The requirement of brightness shall not apply in the case of printing paper so tinted.’	1976-03-31	
16. IS : 1867—1975 Specification for rubber hot water bottles (first revision).	—	No. 1 May 1976	(Page 5, clause 3.4.3, line 3)—Substitute ‘80 percent’ for ‘20 percent’.	1976-05-31	
17. IS : 1891 (Pt. II)—1972 Specification for rubber conveyor and elevator belting Part II hear-resistant belting.	S.O. 423 dated 1975-02-15	No. 1 Feb. 1976	Clause 2.1.3 has been added after clause 3.1.2.	1976-02-29	
18. IS : 1891 (Pt IV)—1971 Specification for rubber conveyor and elevator belting Part IV hygienic belting.	S.O. 510 dated 1974-02-23	No. 1 Sep. 1975	(i) clauses 3.1.2 and 6.4 have been deleted (ii) (Page 7, clause 6.3)—Substitute ‘70±10C’ for ‘100±10C’.	1975-09-30	
19. IS : 1977—1975 Specification for structural steel (ordinary quality) (second revision).	—	No. 1 Jun 1976	(i) Table 1 has been substituted by a new one (ii) Clause 6.1 has been amended.	1976-06-30	
20. IS : 2201—1973 Test chart for milling machines with tables of variable height, with vertical spindle (first revision).	—	No. 1 May 1976	Existing figure given at page 10, col.2 has been substituted by a new one.	1976-05-31	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. IS : 2232—1967 Specification for slotted and castle nuts (first revision).	S.O. 4562 dated 1967-12-23.	No. 3 Jan. 1976.	Table 1 A has been amended.	1976-01-31	
22. IS : 2269—1967 Specification for hexagon socket head cap screws (first revision).	S.O. 4633 dated 1967-12-30	No. 1 Feb. 1976	Table 1, 2 and 3 have been amended.	1976-02-29	
23. IS : 2315—1963 Specification for thimbles for wire ropes.	S.O. 2038 dated 1963-07-20	No. 1 Jun. 1976	Clause 2.3 has been substituted by a new one.	1976-06-30	
24. IS : 2516 (Pt II/Sec 2)—1965 Specification for alternating current circuit-breakers Part II tests section 2 voltage above 1000 up to and including 11000 volts.	S.O. 1081 dated 1966-04-09	No. 2 Oct. 1975	(i) (Page 30, clause A-4.4)—delete this clause and re-number the subsequent clause. (ii) A note has been added after clause A-4.3.	1975-10-31	
25. IS : 2558—1974 Specification for pon- ceau 4 R, food grade (first revision).	S.O. 424 dated 1975-02-15	No. 2 May 1976	(i) Table 1 and clause 3.2 (a) have been amended. (ii) [Page 6, clause 3.2 (g)]—Add the following matter after (g) : '(h) Names of major dye intermediates present'. (iii) Appendix 'B' has been added after Appendix 'A'. (iv) (Page 8)—Add the following foot-note at the bottom of the page: '*Specification for Amaranath, Food Grade (first revision)'.	1976-05-31	
26. IS : 2762—1964 Specification for wire rope slings and sling legs.	S.O. 226 dated 1965-01-16	No. 3 Jun. 1976	(Page 23, Table IV, col 5, heading)—Substitute 'Load capacity of hook on crane' for 'Load capacity of hook'.	1976-06-30	
27. IS : 2831—1975 Specification for carbon steel billets, blooms and slabs for re-rolling into structural steel (ordinary quality) (second revision).	—	No. 1 Jun. 1976.	(i) (Page 6, clause 7.1, line 1)—Delete the words 'blooms and slabs'. (ii) New clause 7.2 has been added after clause 7.1 and the existing clause 7.2	1976-06-30	
28. IS : 2966-1964 Specification for internal micrometers (including stick micrometers).	S.O. 1501 dated 1965-05-08	No. 1 Jun. 1976	(i) clauses 3.2 and 9.2 have been amended (ii) Existing foot-notes at pages 5 and 9 have been substituted by a new one.	1976-06-30	
29. IS : 3026—1968 Specification for tin salts for electroplating (first revision).	S.O. 3728 dated 1969-09-13	No. 1 Jun. 1976	Table 2 has been substituted by a new one.	1976-06-30	
30. IS : 3196—1974 Specification for welded low carbon steel gas cylinder exceeding 5 litre water capacity for low pressure liquefiable gases (second revision).	—	No. 1 Oct. 1975	(i) clause 3.1 have been amended. (ii) clause 9.1 and the matter of clause 11.1 (a) have been substituted by new ones.	1975-10-31	
31. IS : 3196—1974 Specification for welded low carbon steel gas cylinder exceeding 5 litre water capacity for low pressure liquefiable gases (second revision).	—	No. 2 Mar. 1976	First paragraph of clause 11.2.1 have been substituted by a new one.	1976-03-31	
32. IS : 3224—1971 Specification for valve fittings for compressed gas cylinders (first revision).	S.O. 120 dated 1973-01-13	No. 3 Apr. 1976	(i) Clauses 1.2 and 5.1.1 have been substituted by new ones. (ii) (Page 12, Table 4)—Delete 'Methyl bromide' and all the entries against it. (iii) Table 3 has been amended.	1976-04-30	
33. IS : 3498—1975 Specification for metal tables (office type) (first revision).	—	No. 1 Jun. 1976	(i) [page 7, clause 5.3 (b)]—Substitute IS : 151—1950§ for 'IS : 2932—1964§ or IS : 2933—1964  '. (ii) (Page 7, foot-notes)—substitute the following for the existing foot-notes with '§' and '  ' marks : Specification for ready mixed paints, spraying, finishing, stoving, enamel, for general purposes, colour as required.	1976-06-30	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. IS : 3499—1966 Specification for metal chairs (office type).	S.O. 2602 dated 1966-08-27	No. 3 Mar. 1976	§ Clause 1.1 have been substituted by a new one.		1976-03-31
35. IS : 4097—1967 Specification for gravel for use as pack in tubewells.	S.O. 1720 dated 1968-05-18	No. 1 Jun. 1976	(i) (Page 4, clause 4.1, informal table, Sl. No. 6)—Delete along with entries against it. (ii) Clauses 4.2 and 6.1 have been substituted by a new one. (iii) (Page 4, clause 6)—Substitute 'Pack Aquifer ratio' for 'acquirer pack ratio.'		1976-06-30
36. IS : 4119—1967 Specification for charcoal-burning pressing irons.	S.O. 4562 dated 1967-12-23	No. 1 Apr. 1976	(i) Table 1 has been amended. (ii) Clauses 5.1.1, 5.3.1 and 5.3.3 have been substituted by new ones. (iii) Foot-notes have been added after the note in clause 6.1.1. (iv) First sentence of clause 6.1 have been substituted by a new sentence. (v) A sentence has been added after the word 'size' in clause 5.1 line 7.		1976-04-30
37. IS : 4204—1974 Functional requirements for drafting chairs (first revision).	S.O. 988 dated 1976-03-06	No. 1 Jun. 1976	(i) (Page 6, clause 4.3)—Substitute 'IS : 814 (Part I)—1974   ' for 'IS : 814—1970'. (ii) (Page 6, footnotes)—Substitute the following for the existing footnote against '  ' mark:   Specification for covered electrodes for metal arc welding of structural steel : Part I for welding products other than sheets (fourth revision).		1976-06-30
38. IS : 4654—1974 Specification for paraffin Wax (first revision).	—	No. 1 Apr. 1976	Table 1 has been amended.		1976-04-30
39. IS : 4964 (Pt. II)—1975 Specification for plain knitted cotton vests part II vests (first revision).	—	No. 1 June 1976	(i) Table 1 and 3 have been amended. (ii) (Pages 9 and 10, Tables 4 and 5, column 3)—Delete asterisk (*) after column heading 'Length of Vest' from both the tables. (iii) Clause 0.5 has been added after 0.4		1976-06-30
40. IS : 4985—1968 Specification for unplasticised PVC Pipes for potable water supplies.	S.O. 436 dated 1970-02-07	No. 4 Apr. 1976	(i) Clauses 6.1 and 7.2 have been deleted and subsequent clauses re-numbered accordingly. (ii) [Page 17 (page 16 of the fourth reprint), clause E—2.1(c), line 1] Substitute '120° cast steel vec block for '120° vec block.'		1976-04-30
41. IS : 4995 (Pt. II)—1974 Criteria for design of reinforced concrete bins for storage of granular and powdery materials part II design criteria (first revision).	—	No. 1 Jun. 1976	(i) (Page 13, clause 5.5.4, against explanation of n)—Substitute '0.0003' for '0.003'. (ii) (Page 16, clause 5.7.3, line 4)—Substitute '2.5 percent' for '25 percent'.		1976-06-30
42. IS : 5502—1969 Specification for smooth-wheeled diesel road roller.	S.O. 5032 dated 1971-11-06	No. 1 Nov. 1975	(i) (Page 10, Table 2, heading of col. 3)—Delete 'Min'. (ii) Clauses 16.1 and 17.1 have been substituted by new ones.		1975-11-30

1	2	3	4	5
43.	IS : 5513—1969 Specification for vicat apparatus.	S.O. 1387 dated 1975-05-03	No. 1 Nov. 1975	(iii) [Page 11, clause 17.2, second sentence] Delete. (iv) [Page 13, clause 26.1.(g)] Substitute 'Line pressure' for 'contact pressure'. (v) [Page 13, clause 26.1(h)] Delete this item.
44.	IS : 6179—1971 Specification and safety requirements for rigid sided playpens.	S.O. 3055 dated 1973-10-27	No. 1 Jun. 1976	(i) [Page 4, Table 1 Sl. No. (viii), col 2]— Substitute 'Mould E, Mould E1 and clamping ring' for 'Mould E'. (ii) Clause 4.5.1 has been added after clause 4.5. (i) [Page 4, clause 3.1.4(b)]—Substitute IS : 151—1950 and for 'IS : 2932—1964‡'. (ii) (Page 4, foot-note with '‡' mark)— Substitute the following for the existing foot-note with '‡' mark: '‡Specification for ready mixed paint, spraying, finishing, stoving, enamel, for general purposes, colour as required'.
45.	IS : 6235—1971 Dimensions of pot-croes made of ferromagnetic oxides and associated	S.O. 231 dated 1974-01-26	No. 2— Jun. 1976	Table I has been amended.
46.	IS : 6297 (Pt I)—1971 Specification for transformers and inductors (power, audio pulse and switching) for electronic equipment Part I general requirements and tests.	S.O. 3255 dated 1974-11-24	No. 3— May 1976	(i) Clause 6.2.1.7 have been amended. (ii) Clause 6.2.3.3 have been added after clause 6.2.3.2 and the subsequent clauses and figures re-numbered accordingly wherever they appear.
47.	IS : 6315—1971 Specification for floor springs (Hydraulically regulated) for heavy doors.	S.O. 510 dated 1974-02-23	No. 1 Aug. 1975	(i) (Page 4, clause 2.6, line 2)—Delete the word 'door'. (ii) Fig. 1 has been substituted by a new one. (iii) Clauses 7.2., 8.1 and 8.4 have been substituted by new ones. (iv) (Page 8, clause 8.2., line 2)—Substitute '20 seconds' for '2 seconds'.
48.	IS : 7142—1974 Specification for welded low carbon steel gas cylinder for low pressure liquefiable gases, not exceeding 5 litre water capacity.	S.O. 776 dated 1976-02-21	No. 1 Sep. 1975	(i) Clauses 5.1.3 and 9.1 have been substituted by new ones. (ii) (Page 10, clause 8.1, first sentence)— Substitute the following for the existing first sentence: 'Each heat treated cylinder shall be subjected to hydrostatic test'. (iii) [Page 11, clause 11.1(a)]—Substitute the following for the existing text: (a) Tensile tests—One is longitudinal direction and one in transverse direction on plate material.'
49.	IS : 7142—1974 Specification for welded low carbon steel gas cylinder for low pressure liquefiable gases, not exceeding 5 litre water capacity.	S.O. 776 dated 76-02-21	No. 2— Mar 1976	(i) First paragraph of clause 11.2.1 has been substituted by a new one.
50.	IS : 7394—1974 Specification for high density polyethylene containers (jerry cans) for petroleum reserve fuel with nominal volume up to 5 litres.	—	No. 1 May 1976	(i) clauses 3.1.1 and 3.1.2 have been amended. (ii) (Page 4, foot-note, line 3)—Substitute the following for the existing foot-note:

1	2	3	4	5	6
51. IS : 7430—1974 Dimensions of screw cores made of ferromagnetic oxides.	—	No. 1 Jun. 1976	Table I has been amended.	1976-06-30	
52. IS : 7460—1974 Tolerances for tapered roller bearings.	—	No. 1 July 1976	Figures under clause 3 have been substituted by a new one.	1976-07-31	
53. IS : 7461—1974 General plan of boundary dimensions for tapered roller bearings.	—	No. 1 July 1976	Figures under clause 3.1 have been substituted by a new one.	1976-07-31	
54. IS : 7634 (Pt. III)—1975 Code of practice for plastics pipe work for potable water supplies Part III laying and jointing of unplasticized PVC pipes.	—	No. 2 May 1976	(i) Clause 2.2.4.1 (b) has been amended. (ii) [Page 6, clause 2.2.4.1(d), line 3]— Substitute 'end' for 'and'. (iii) [Page 7, clause 2.2.4.2(d) (5), line 1]— Substitute 'not' for 'hot'.	1976-05-31	
55. IS : 7741 (Pt. I)—1975 Specification for loudspeakers Part I general requirements and tests.	—	No. 1 Jun. 1976	(Page 18, clause 4.1, Informal Table, last row)—Delete.	1976-06-30	

Copies of these amendments are available with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Kanpur, Madras, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13: 51  
A.P. BANER JI, Dy. Director Gen.]

उद्योग मंत्रालय  
(भारी उद्योग विभाग)

नई विली, 2 मई, 1979

का० आ० 1525.—उद्योग मंत्रालय की अधिकृतना संख्या का०आ० 3544 विलीक 24 सितम्बर, 1976 में भारी उद्योग विभाग करते हुए और सार्वजनिक परिसर (ग्रन्थिकृत व्यालकार की वेष्टवाली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की द्वारा 3 द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एवं द्वारा योग्य करते हुए केंद्रीय सरकार के समकालीन अधिकारी की विभाग के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उस अधिनियम के प्रयोगान्वयों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उस अधिनियम द्वारा या के अधीन सम्पदा अधिकारी की प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कर्तव्यों का पालन स्थानीय सीमाओं के अन्दर करेगा जैसा अधिकृतना का० आ० संख्या 1891 विलीक 22 जून, 1972 की अनुसूची में परिचालित किया गया है।

[का० सं० 14-3/74-एच०प०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 2nd May, 1979

S.O. 1525.—In partial modification of the Ministry of Industry's Notification No. S.O. 3544 dated the 24th September, 1976 and in exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints Shri V. K. Shinde, Dy. Manager (Town Administration), B. H. E. L., Bhopal being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer of Government to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on Estate Officer, by or under the said Act, within the local limits as defined in the schedule to Notification S.O. No. 1891 dated 22nd June, 1972.

[F. No. 14-3/74-HEM]

का० आ० 1526.—भारी उद्योग मंत्रालय की अधिकृतना जो राजधानी विलीक 24 अगस्त, 1974 के द्वारा 2 में पृष्ठ 2339 पर संख्या का० आ० 2181 के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी, में भारी उद्योग विभाग करते हुए और सार्वजनिक परिसर (ग्रन्थिकृत व्यालकार की वेष्टवाली) अधिनियम, 1971 (1971 का केंद्रीय अधिनियम 40) की द्वारा 3 द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एवं द्वारा योग्य करते हुए केंद्रीय सरकार एवं द्वारा योग्य करते हुए केंद्रीय सरकार के स्तर के समकालीन अधिकारी के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उस अधिनियम के प्रयोगान्वयों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कर्तव्यों का पालन स्थानीय सीमाओं के अन्दर करेगा जैसा विलीक 4-10-75 की पृष्ठ 3597 की अधिकृतना का० आ० संख्या 4296 की अनुसूची में परिचालित किया गया है।

[का० सं० 14-3/74 एच० ई० एम०]

ए० सुब्रह्मण्यम्,  
अबर सचिव

S.O. 1526.—In partial modification of the erstwhile Ministry of Heavy Industry's Notification published under No. S. O. 2181 on page 2339 in Part II of the Gazette dated 24th August, 1974 and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (Central Act 40 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri Vijay Shanker, Dy. Manager (Personnel) B. H. E. L. Hardwar, being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer of Government, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on Estate Officer, by or under the said Act, within the local limits and defined in the schedule to Notification S.O. No. 4296 dt. 4-10-75.

[F. No. 14-3/74-HEM]  
N. SUBRAHMANYAM, Under Secy.

**कर्जी मंदालय**  
(कोयला विभाग)  
नई विलो, 28 मार्च 1979

काठा० 1527.—केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला बाले लैज (प्रर्जन और विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के प्रधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंदालय, कोयला विभाग की अधिकृतना सं० का० 844, तारीख 9 मार्च, 1978 द्वारा उस अधिकृतना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिविष्ट परिक्लेन में 1250.00 एकड़ (लगभग) या 506.00 हेक्टेयर (लगभग) 506 लोकपल काली भूमि में कोयले का पूर्वांकण करने के अपने आवाय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभियाप्त है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में से, इससे उपाबद्ध अनुसूची में अंजित 1241.06 एकड़ (लगभग) या 502.239 हेक्टेयर (लगभग) आप की भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बेघन उनके लिए खुदाई करने और उन्हें तकाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें छोकर में जाने के अधिकार अंजित करने के अपने आवाय की सूचना देती है।

टिप्पण 1: इस अधिकृतना के प्रत्यर्पत्ति आने वाले लैज के नवायों का विवरण कलक्टर, बिलासपुर (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कॉसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या बेस्टनैं कोलकाता लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), बिसेसर हाउस, टेम्पलरोड, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण 2: पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों की ओर आवाय अधिकृत किया जाता है, जिसमें निम्नामूलक व्यवस्था की गई है:—“प्रर्जन पर प्राप्ति 8(8)(1) कोई अधिकृत जो किसी

ऐसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के प्रधीन अधिकृतना जारी की गई है, हितबद्ध है, अधिकृतना के जारी होने के तीस विन के भीतर समस्त भूमि या उसके किसी भाग के या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों के अंजित करने पर आक्षेप कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण:** किसी व्यक्ति द्वारा यह कहना कि वह स्वयं कोपने के उत्पादन के लिए भूमि में खनन प्रचालन करता जाता है और यह कि ऐसे प्रचालन, केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किए जाने चाहिए, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत आक्षेप नहीं होता।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सभीम प्राधिकारी जो विवित रूप में किया जाएगा और सभीम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को या तो अधिकृत रूप में या विधिक व्यवसायी द्वारा सुने जाने का प्रवासर देगा तथा ऐसे सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात और ऐसी और जोच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, केन्द्रीय सरकार की ऐसी भूमि की जो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचित की गई है या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों की बाबत या तो एक रिपोर्ट देगा या ऐसी भूमि के विभिन्न पार्सलों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों की बाबत विभिन्न रिपोर्ट देगा, जिसमें उस सरकार के विनियोग के लिए उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के प्रमिलेज सहित, आक्षेपों पर उसकी सिफारियें होंगी।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे अधिकृत को भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा, जो प्रतिकर में हित का दावा करने का तब हक्कदार होगा, अब भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं आधिकारों को इस अधिनियम के अधीन अंजित कर लिया जाए।”

टिप्पण 3: कोयला नियंत्रक, 1, कॉसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन सभीम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

**अनुसूची**

राजगांवर विस्तार लैज

(कोरका कोयला लैज)

जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

रेखांक संख्या पी सी एल/सी 1 (f) III/वी भार/202/1178, तारीख 1-11-1978

(जिसमें ऐसी भूमि दर्शित की गई है जिसमें खनिजों के खनन, खदान, बेघन, खुदाई और तकाश प्रम्बेशण, इन पर कार्य करने और उन्हें छोड़ने के अधिकार अंजिन किये जाते हैं)

**खनन अधिकार**

क्रम सं०	ग्राम का नाम	नंबर सं०	पु०सं०	तहसील और थाना	लैजफल (हेक्टर में)		पौग टिप्पणी
					सरकारी भूमि	अधिकृत भूमि	
1. राजगांवर		249	19	तहसील काट घोड़ा और जिला बिलासपुर	328.390	2.856	381.246
2. केराकाशार		251	18	”	6.705	0.332	66.037 भाग
3. कोरकोमा		252	19	”	26.143	12.484	38.627 भाग
4. केरका (प्रसर्वेशित)		--	19	”	--	--	9.672 भाग
5. देंगुर श्री (प्रसर्वेशित)		--	19	”	--	--	6.657 भाग
				420.238 हेक्टर (लगभग) या 1038.43 हेक्टर (लगभग)	65.672 हेक्टर (लगभग) या 162.28 हेक्टर (लगभग)	502.239 हेक्टर (लगभग) या 1241.06 हेक्टर (लगभग)	

राजगमर ग्राम में अधित किए जाने वाले प्लाट सं० :

93/1पी, 93/2, 94 से 99, 100पी, 101, 102/2, 174 पी, 102/1, 103/1 से 103/3, 104, 105, 106/1, 106/2, 107 से 116, 117/1, 117/2, 118 से 122, 123/1 के पी, 123/1 के एच, 123/1पी, 123/2पी, 124 से 143, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2 पी से 145/3पी, 162पी, 163पी, 146/2, 159, 164पी, 165 से 170, 171पी, 172/1पी, 172/2पी, 173पी, 284/1के पी, 293पी, 294पी, 295पी, 295/1 के पी, 295/2, 296 से 300, 301, 302/1 के, 302/1 जीपी, 302/2पी, 303 से 308, 309, 311/3, 310/1पी, 310/2पी, 311/1पी, 321, 323/1पी, 719/2पी, 723पी, 724/1पी, 730/1पी, 731 से 734, 735पी, 736 पी, 737/1के, 737/1जीपी, 737/1 के एच, 738/1 से 738/4, 739, 740, 741/1 के पी, 742/1, 743/1पी, 741/2, और 742/2 743/2.

ग्राम केराकडार में अधित किए जाने वाले प्लाट सं० :

48पी, 86/1पी और 87, :

ग्राम कोरकोमा में अधित किए जाने वाले प्लाट सं० :

1/1पी, 1/2पी, 2-17/2, 3-14-15-16-17/1, 4-6-12/1-13/1पी, 5-7पी, 12/2पी, 13/2पी, 17/3, 17/4-19-20-17/5, 18, 21/1पी, 21/2पी और 43/1पी ।

ग्राम केरवा में अधित किए जाने वाले प्लाट सं० :

(प्रसर्वेक्षित)

ग्राम बैंगुरखीह में अधित किए जाने वाले प्लाट सं० :

(प्रसर्वेक्षित)

सीमा वर्णन :

क—क	रेखा ग्राम राजगमर के प्लाट सं० 93/1, 123/1के, 123/2 से होकर जाती है और प्लाट सं० 311/1 में, बिन्दु "क" पर मिलती है ।
क—ग—घ	रेखा ग्राम राजगमर के प्लाट सं० 311/1, 310/1, 302/1 के
ड—घ—छ—घ	302/1पी, 302/1 के एच, 301, 301/2, 323/1, 736, 735, 730/1, 724/1, 723, 719/2 और ग्राम राजगमर और केरवा (प्रसर्वेक्षित) की सम्मिलित सीमा के बिन्दु "घ" पर मिलती है ।
अ—आ—अ	रेखा ग्राम राजगमर और केरवा (प्रसर्वेक्षित) की सम्मिलित सीमा के निकट से गुजरती है और ग्राम राजगमर और केरवा से होकर जाती है और बिन्दु "अ" पर मिलती है ।
आ—ट—ठ	रेखा ग्राम केराकडार के प्लाट सं० 49, 86/1 और ग्राम केरवा (प्रसर्वेक्षित) और तप्पनात् ग्राम राजगमर के प्लाट सं० 742/1 743/1 से होकर जाती है और प्लाट सं० 741/1 के बिन्दु "ठ" पर मिलती है ।
ठ—च	रेखा ग्राम राजगमर के प्लाट सं० 741/1 से होकर ग्राम कोरकोमा के प्लाट सं० 43/1, 21/2 से जाती है और प्लाट सं० 21/1 में बिन्दु "च" पर मिलती है ।
ट—ड	रेखा ग्राम कोरकोमा के प्लाट सं० 21/1, से 4-6-12/1-13/1, 12/2, 13/2, 1/2, 1/2, 5-7 से और तप्पनात् ग्राम बैंगुरखीह (प्रसर्वेक्षित) और ग्राम राजगमर से होकर जाती है और प्लाट सं० 737/1 के-737/1 जी में बिन्दु "ट" पर मिलती है ।
ड—ग—त	रेखा ग्राम राजगमर के प्लाट सं० 737/1 के "737/1जी, 294, 293, 295/1के, 284/1 के, 302/2, 302/1के, 302/1पी, 145/3, 145/4, 145/5, 146/2, 159, 164, 163, 162, 171, 172/2, 173, 101-102/2, 174, 100 से होकर जाती है और प्लाट सं० 93/1 में बिन्दु "त" पर मिलती है ।
त—क	रेखा ग्राम राजगमर से होकर जाती है और प्लाट सं० 93/1 में प्रारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं० 19 (63) 77-सी-एल०]

एस० ग्राम० ए० दिव्यांगी, निदेशक

### MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 28th April, 1979

**S.O.1527.**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Coal No. S.O. 844 dated the 9th March, 1978, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 1250.00 acres (approximately) or 506.00 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification.

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 1241.06 acres (approximately) or 502.239 hectares (approximately) out of the said lands and described in the Schedule appended hereto.

**Note 1.**—The plans of the areas covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Bilaspur (Madhya Pradesh) or in the Office of the Coal Controller, 1-Council House Street, Calcutta, or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Biseaser House, Temple Road, Nagpur (Maharashtra).

**Note 2.**—Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act, which provide as follows :

## OBJECTIONS TO ACQUISITION :

"8(1)—Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the Competent authority in writing and the competent authority shall give the objectors an opportunity of being

heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendation on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under his Act."

Note 3—The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE  
RAJGAMAR EXPANSION BLOCK  
(KORBA COALFIELD)  
(DISTRICT-BILASPUR (MADHYA PRADESH))

Drawing No. WCL/C-1(E) III/DR/202.1178

Dated : 1-11-1978

(Showing the lands where rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals are to be acquired).

## MINING RIGHTS

Sl. No.	Name of Village	Khewat No.	P.C. No.	Tahsil & District	Area in Hectares		Total	Remarks
					Govt. land	Tenancy land		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rajgamar . . . . .	249	19	Tashil Katghora & District Bilaspur.	328.390	52.856	381.246	Part.
2.	Kerakchhar . . . . .	251	18	“	65.705	0.332	66.037	Part.
3.	Korkoma . . . . .	252	19	“	26.143	12.484	38.627	Part.
4.	Kerwa . . . . . (Un-surveyed)	—	19	“	—	—	9.672	Part.
5.	Dhengurdih . . . . . (Un-surveyed)	—	19	“	—	—	6.657	Part.
					420.238 Hectares (approxi- mately)	65.672 Hectares (approxi- mately)	502.239 Hectares (approxi- mately)	
					or 1038.43 acres (approxi- mately)	or 162.28 acres (approxi- mately)	or 1241.06 acres. (approxi- mately)	

Plot numbers to be acquired in village Rajgamar :

93/1P, 93/2, 94 to 99, 100P, 101-102/2-174P, 102/1, 103/1 to 103/3, 104, 105, 106/1, 106/2, 107 to 116, 117/1, 117/2, 118 to 122, 123/1Kh, 123/1Kh, 123/1 G, 123/1 Gh, 123/2 P, [124 to 143, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2P to 145/5P, 162P, 163P, 146/2-159-164 P, 165 to 170, 171P, 172/1P, 172/2P, 173P, 284/1K P, 293P, 294P, 295/1K P, 295/2, 296 to 300, 301-302/1 kh P, 302/1K-302/1 GP, 302/2P, 303 to 308, 309-311/3, 310/1P, 310/2P, 311/1P, 321, 323/1P, 719/2P, 723P, 724/1P, 730/1P, 731 to 734, 735 P, 736 P, 737/1K-737/1GP, 737/1Kh, 738/1 to 738/4, 739, 740, 741/1K P, 742/1-743/1P, 741/2 and 742/2-743/2.

Plot numbers to be acquired in village Kerakachhar :

49P, 86/1P and 87.

Plot numbers to be acquired in village Korkoma :

1/1P, 1/2P, 2—17/2, 3—14—15—16—17/1, 4—6—12/1—13/1P, 5—7P, 12/2P, 13/2P, 17/3, 17/4—4—19—20, 17/5, 18, 21/1P, 21/2P and 43/1P.

Plot numbers to be acquired in village Kerwa :

Un-surveyed.

Plot numbers to be acquired in village Dhengurdih :

Un-surveyed.

Boundary Description :

A—B—Line passes through village Rajgamar in plot nos. 93/1, 123/1K, 123/2, and meets in plot no. 311/1 at point 'B'.

B—C—D—Line passes through village Rajgamar in plot nos.

E—F—G—311/1, 310/1, 302/1K, —302/1G, 302/1Kh—301, 310/2,

H—323/1, 736, 735, 730/1, 724/1, 723, 719/2 and meets at the common boundary of villages Rajgamar and Kerwa (u/s) at point 'H'.

H—I—J—Line passes along the common boundary of villages Rajgamar and Kerwa (u/s.) and then villages Rajgamar and Kerakachhar and meets at point 'J'.

J—K—L—Line passes through village Kerakachhar in plot nos. 49, 86/1 and then proceeds through village Kerwa (u/s.) and village Rajgamar in plot no. 742/1—43/1 and meets in plot no 741/1K at point 'L'.

L—M—Line passes through village Rajgamar in plot no. 741/1K and then proceeds through village Korkoma in plot nos. 43/1, 21/2 and meets in plot no. 21/1 at point 'M'.

M—N—Line passes through village Korkoma in plot nos. 21/1, 4—6—12/1—13/1, 12/2, 13/2, 1/2, 1/1, 5—7 and then proceeds through village Dhengurdih (u/s.) and village Rajgamar and meets in plot no. 737/1K—737/1G at point 'N'.

N—O—P—Line passes through village Rajgamar in plot nos. 737/1K—737/1G, 294, 293, 295/1K, 284/1K, 302/2, 302/1K—302/1G 145/3, 145/4, 145/5, 146/2—159—164, 163, 162, 171, 172/2, 173, 102/102/2—174, 100 and meets in plot no. 93/1 at point 'P'.

P—A—Line passes through village Rajgamar and meets in plot no. 93/1 at the starting point 'A'.

[No. 19(63)/77 CL]  
S.R.A. RIZVI, Director

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई विल्सी, 21 फ्रैंस, 1979

क्रांति 1528.—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सखनक) नियमावली, 1979 के नियम 1 के अनु (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा उक्त नियमावली को 30 फ्रैंस, 1979 से नियमिति क्षेत्रों में भी सामूहिकता है, प्रधान :—

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संघर्षा 1 और 21 फ्रैंस कालीनी फैजाबाद रोड, सखनक में स्थित है।

विभिन्न में शहर की पूर्वी सीमा और गोमती नदी के उत्तरी किनारे जंक्शन से आरम्भ होकर गोमती नदी के उत्तरी किनारे के साथ-साथ परिवर्त्तन को बढ़ाते हुए उत्तर पूर्व रेल लाइन तक (सीतापुर लाइन)।

परिवर्त्तन में रेलवे लाइन और गोमती नदी के जंक्शन से रेल लाइन (सीतापुर लाइन) के साथ-साथ उत्तर को बढ़ाते हुए शहर की उत्तरी सीमा तक।

उत्तर और पूर्व में वह क्षेत्र जो शहर की उत्तर और पूर्वी सीमा रेलवे से घिरा है। इस क्षेत्र में सीतापुर रेलवे लाइन के पूर्व में आक वितरण जोन संघर्षा 13, जोन संघर्षा 6 और 7 भी शामिल हैं।

इसके प्रत्यागत भाने वाले मुख्य क्षेत्र हैं—राम सागर मिथा नगर, शेषपुरा, जुगाली, रहीम नगर, महानगर, बाबराहन नगर, चांदगंज, और हैदराबाद कालीनी और निकात गंज, रैतासपुर, ग्रनीगंज, निरासा नगर और डालीगंज।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संघर्षा 2 जी, 6 बालीनीपुर मार्ग, सखनक में स्थित है।

उत्तर में शहर की पूर्वी सीमा लाइन और गोमती नदी के जंक्शन किनारे के जंक्शन से नेकर परिवर्त्तन की ओर जाते हुए उत्तर-पूर्व रेल लाइन तक (सीतापुर लाइन)।

परिवर्त्तन में दीतापुर साइन और गोमती नदी के जंक्शन से आरम्भ होकर रेल लाइन के साथ-साथ विभिन्न की ओर जाते हुए रेलवे लाइन और सुधापाल मार्ग के जंक्शन तक। यहां से विभिन्न की ओर सुधापाल मार्ग के साथ-साथ कास कानपुर रोड से सखनक रेलवे स्टेशन तक।

विभिन्न में आर बाग रेलवे स्टेशन से जल कर उत्तरी रेलवे लाइन के साथ पूर्व की ओर (फैजाबाद लाइन) जाते हुए गोमती नदी तक।

पूर्व में इसका क्षेत्र गोमती नदी से लगा हुआ है। इस क्षेत्र में आक वितरण जोन संघर्षा 1 और आक वितरण जोन संघर्षा 4 का कुछ भाग जो कि सुधापाल मार्ग के पूर्व में तथा गंगा प्रसाद रोड और ग्रनीगंज रोड के बीच स्थित है।

[सं. एक्ट 11012/1/79-के संस्कारणों (मीटिंग) द्वारा]

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**  
(Department of Health)

New Delhi, the 21st April, 1979

**S.O. 1528.**—In pursuance of clause (3) of rule 1 of the Central Government Health Scheme (Lucknow) Rules, 1979, the Central Government hereby extends the said rule with effect from the 30th April, 1979 to the following areas, namely :—

Central Government Health Scheme Dispensary No. 1 at, 21, Krishna Colony, Faizabad Road, Lucknow.

On the south starting from the junction of the city eastern boundary line and the Northern Bank of the river Gomti proceed West along with the Northern Bank of the river Gomti upto N. E. Railway line (Sitapur line).

On the East from the junction of the Railway line and river Gomti proceed northwise along the Railway line (Sitapur line) upto the Northern boundary line of the city.

On the North and East the area is bounded by the Northern and Eastern city boundary line.

The area includes postal delivery Zone No. 13, Zone No. 6 & 7 east of Sitapur Railway line.

The main areas included are Ram Sagar Misra Nagar, Sheikpura, Jugauli, Rahim Nagar, Mahanagar, Badshah Nagar, Chandgani, New Hyderabad Colony and Nishat Ganj, Raitaspur Aliganj, Nirala Nagar and Dalliganj.

Central Government Health Scheme Dispensary No. 2 at 6, Valmiki Marg, Lucknow.

On the North starting from the junctions of the city eastern boundary line and south bank of the river Gomti proceed West upto the N. E. Railway line (Sitapur Line).

On the West starting from the Junction of the Sitapur line and Gomti river proceed South ward along the railway line upto the junction of the Railway line and Subhash Marg, then proceed Southward along Subhash Marg Cross Kanpur Road upto Lucknow Railway Station.

On the South starting from the Charbagh Railway Station proceed Easternward along the Northern Railway Line (Faizabad Line) proceed upto river Gomti.

On the East the area is bounded by the river Gomti. The area included is postal delivery Zone No. 1 and the portion of the delivery Zone No. 4 situated on the eastern side of Subhash Marg and in between Ganga Prasad Road and Aminabad Road.

[No. S. 11012/1/79-CGHS (P) (B)]

**कानून 1529.**—संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के बंद (5) के परस्पर द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय भेदा परीक्षा तथा भेदा विभाग में कार्य कर रहे शक्तियों के संबंध में भारत के विवेक और महेश्वरा परीक्षक से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति एवं विद्वारा निम्नलिखित नियम अप्रत्येक हैं, अधर्तु :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सखनक), नियम, 1979 है।

(2) ये 30 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये सखनक शहर, भावनी भेद, नीटीकाइड एवं एसीए कमेटी, यदि कोई हो, अथवा ऐसे अन्य निकटवर्ती भेद जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विविध किए जाएं, लागू होंगे।

(4) ये सखनक शहर में अथवा उप-नियम (3) में उल्लिखित किसी अन्य भेद तथा इन इलाकों में यह रहे निम्नलिखित बंग के कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के उन सभी कर्मचारियों जिनके मुक्तालय इन्हीं इलाकों में स्थित हैं, पर लागू होंगे, अधर्तु :—

- (क) रेल सेवा में नियुक्त व्यक्ति ;
- (ख) सिविलियन सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर रक्षा सेवा अनुमानों से बेतन प्राप्त कर रहे सभी व्यक्ति (इनमें गैर-ओडोगिक कर्मचारी शामिल नहीं हैं) ;
- (ग) ये व्यक्ति जो सरकार की पूर्णकालीन सेवा में नहीं हैं;
- (घ) आकर्तिकता निवि में से बेतन प्राप्त कर रहे व्यक्ति।

2. ऐसी योजना से संबंधित जो अनुदेश विली में लागू हैं वे सखनक और अन्य भेदों में भी लागू होंगे।

3. सेंट्रल सर्विसेज (मेडिकल प्रैटेंडेंस) रूल्स, 1944 अथवा प्रासाद इंडिया सर्विसेज (मेडिकल प्रैटेंडेंस) रूल्स, 1954 में निहित किसी बात के होते हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से संबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वो अनुदेश विली में लागू हैं जो नियम 1 के उप-नियम (4) में उल्लिखित शक्तियों के संबंध में यहां परिवर्तित रूप में लागू होंगे।

[सं. एस. 11012/1/79-के-म-स्वा-यो-० (नीति) (ए)]

श्रीमती आशा शर्मा, अवतर सचिव

**S.O. 1529.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Government Health Scheme (Lucknow) Rules, 1979.
- (2) They shall come into force on the 30th April, 1979.
- (3) They shall extend to the city of Lucknow, cantonment area, notified area committee, if any or such other contiguous areas, as the Central Government may from time to time, by notification in the Official Gazette specify.
- (4) They shall apply to all persons serving in connection with the affairs of the Union, stationed and having their headquarters at Lucknow or in any other area referred to in sub-rule (3) and residing therein except the following, namely :—
  - (a) persons employed in Railway Services ;
  - (b) all persons, other than civilian Government servants (excluding non-industrial workers), paid from the Defence Services estimates ;
  - (c) persons not in whole time service of the Government ;
  - (d) persons paid out of contingencies.

2. The instructions relating to such scheme in force in Delhi, to apply to Lucknow and other areas.

3. Notwithstanding anything contained in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, or the All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954, the instructions issued from time to time by the Central Government relating to the Central Government Health Scheme as in force in Delhi shall apply mutatis-mutandis in respect of persons mentioned in sub-rule (4) of rule 1.

[No. S. 11012/1/79-CGHS(P)(A)]

Mrs. ASHA SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1979

**का०स्ट० 1530**—यह भारतीय आयुक्तिकाल परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 10) की बारा 7 की उपचारा (4) के काप पठित बारा 3 की उपचारा (1) के बांड (ब) के अनुसरण में उस्मानिया विश्वविद्यालय से डा० बाई०प्रार० रेडी, डीन, विश्वविद्यालय संकाय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद को डा० फी० नर्सिंगराव के स्थान पर 17 मार्च, 1979 से भारतीय आयुक्तिकाल परिषद् का सदस्य नियमित किया गया है।

अतः यह उक्त अधिनियम की बारा 3 की उपचारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतव्यारा भूतपूर्व स्वास्थ्य बोर्ड की 9 अनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या एस०सी० 138 में नियमित और संबोधित करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “बारा 3 की उपचारा (1) के बांड (ब) के प्रत्येक नियमित” शब्द के अन्तर्गत कम संख्या 12 और उससे तंत्रित प्रविष्टि के स्थान पर नियमित कम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“12. डा० बाई०प्रार० रेडी,  
डीन, विश्वविद्यालय संकाय,  
उस्मानिया विश्वविद्यालय,  
हैदराबाद-500007”।

[स० सी० 11013/7/79-एम०ई० (फी०)]

आर० बी० श्रीनिवासन, उप सचिव

New Delhi, the 27th April, 1979

**S.O. 1530**—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with sub-section (4) of section 7 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. Y. R. Reddy, Dean, Faculty of Medicine, Osmania University, Hyderabad, has been elected by the Osmania University to be a member of the Medical Council of India with effect from the 17th March, 1979 vice Dr. G. Narsing Rao ;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the late Ministry of Health No. S.O. 138 dated the 9th January, 1960 namely :—

In the said notification, under the heading “Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3”, for Serial No. 12 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be substituted namely :—

“12. Dr. Y. R. Reddy,  
Dean, Faculty of Medicine,  
Osmania University,  
Hyderabad-500007”.

[No. V. 11013/7/79-M.E. (Policy)]  
R. V. SRINIVASAN, Dy Secy.

कृपि और लिखा हुआ संकाय

(आयुक्तिकाल)

शुद्धि-प्रबन्ध

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1979

**का०स्ट० 1531**—इस विभाग के तारीख 11-10-72 के आदेश संख्या 52/21/68-प्रार० ई० 1 में नियमित शुद्धियां की जायें :—

स्थानान्तरण आदेश में की जाने वाली शुद्धियां  
कम संख्या

260 कालम 2 में “श्री ए०क० नायर” के स्थान पर “श्री फी०ए०पी० नायर” पढ़ें।

स्थानान्तरण आदेश में कम संख्या	की जाने वाली शुद्धियां
1906	कालम 2 में “श्री हासी देवराम चिंगोलजी” के स्थान पर “श्री हासी देवराम चिंगमजी” पढ़ें।
1910	कालम 2 में “श्री लक्ष्मा बी० भोगल” के स्थान पर “श्री लक्ष्मण बी० भीगल” पढ़ें।
329	कालम 2 में “श्री बी०ज० फिरबानी” के स्थान पर “श्री बी०ज० वीरबानी” पढ़ें।
	2. इस विभाग के तारीख 4-7-75 के आदेश संख्या 52/22/74-एफ०सी०-III (बाल्यम-II) में नियमित शुद्धियां की जायें :—
स्थानान्तरण आदेश में कम संख्या	की जाने वाली शुद्धियां
102	कालम 2 में “श्री ए०ए०स० साला” के स्थान पर “श्री ए०ए०स० साल्वे” पढ़ें।
	3. इस विभाग के तारीख 16-1-78 के आदेश संख्या 52/22/74-एफ०सी०-III (बाल्यम-9) में नियमित शुद्धियां की जायें :—
स्थानान्तरण आदेश में कम संख्या	की जाने वाली शुद्धियां
14	कालम 2 में “श्री बी०बी० के लूस्कर” के स्थान पर “श्री बी०बी० कालूस्कर” पढ़ें।
	4. इस विभाग के तारीख 10-7-78 के आदेश संख्या 52/22/74-एफ०सी०-III (बाल्यम-10) में नियमित शुद्धियां की जायें :—
स्थानान्तरण आदेश में कम संख्या	की जाने वाली शुद्धियां
35	कालम 2 में “श्री देवेन्नगिरि” के स्थान पर “श्री देवेन्नगिरि बी०” पढ़ें।
38	कालम 2 में “श्री जीवा भोटी” के स्थान पर “श्री जीवाराज भोटीभाई” पढ़ें।
58	कालम 2 में “श्री भावजी देवजी धीविन” के स्थान पर “श्री भावजी देवजी यामी” पढ़ें।
	[स० 52/1/79-एफ०सी०-III (बाल्यम-II)]
	ए०ए० कम्बोह, प्रबर सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE &amp; IRRIGATION

Department of Food

CORRIGENDA

New Delhi, the 21st, April, 1979

**S.O. 1531** :—In this Department Order No. 52/21/68-R.E.I. dated 11-10-72, the following corrections shall be carried out :

Sl. No. in the Transfer Order	Correction to be carried out
260	For the words “Shri A.K. Nair” in col. 2, read “Shri P.N. A. Nair”.
1906	For the words “Shri Hasi Deoram Chionaji” in col. 2, read “Shri Hase Deoram Chionaji”.
1910	For the words “Shri Laxman V. Mogul” in col. 2, read “Shri Laxman V. Mogal”.
329	For the words “Shri V.J. Phirwani” in col. 2, read “Shri V.J. Pirwani”.

II. In this Department Order No. 52/22/74-FC. III (Vol.II) dated 4-7-75, the following correction shall be carried out :

Sl. No. in the Transfer Order	Correction to be carried out
-------------------------------	------------------------------

102	For the words "Shri S.S. Salva" in col. 2, read "Shri H.S. Salve".
-----	--

III. In this Department Order No. 52/22/74-FC. III (Vol. IX) dated 16-1-78, the following correction shall be carried out :

Sl. No. in the Transfer Order	Correction to be carried out
-------------------------------	------------------------------

14	For the words "Shri D.V. Keluskar" in col. 2, read "Shri D.V. Kaluskar".
----	--

IV. In this Department Order No. 52/22/74-FC. III (Vol.X) dated 10-7-1978, the following corrections shall be carried out :

Sl. No. in the Transfer Order	Corrections to be carried out.
-------------------------------	--------------------------------

35	For the words "Shri Devendergiri" in col. 2, read "Shri Devendergiri P."
38	For the the words "Shri Jiva Moti" in col. 2, read "Shri Jivraj Motibhai".
58	For the words "Shri Mavji Devji Dhabhi" in col. 2, read "Shri Mavji Devji Dabhi".

[No. 52/1/79-FC. III(Vol. II)  
S.L. KAMBOH, Under Secy.

प्रावेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1979

का० ला० 1532.—अतः केन्द्रीय सरकार ने आच विभाग, क्षेत्रीय आच विभागों, उपाधि विभागों और आच विभाग के वेतन तथा लेहा कायालियों द्वारा किए जाने वाले आचारों के काय, भण्डारकरण, संचालन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कायों का पालन करना बंद कर दिया है जोकि आच निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय आच निगम के काय है।

और यह आच विभाग, क्षेत्रीय आच विभागों, उपाधि विभागों और आच विभाग के वेतन तथा लेहा कायालियों में काय कर रहे और उपरिवित कायों के पालन में लगे निम्नलिखित प्रधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिवर्त के प्रत्युत्तर में उसमें विविचित तारीख के बन्दर भारतीय आच निगम के कर्मचारी न बताने के प्रत्ये प्राप्त की उक्त अधिनियम की धारा 12ए की उपषादा (1) के परम्परा द्वारा यथा अपेक्षित मूल्या नहीं दी है।

अतः अब आच निगम अधिनियम 1964 (1964 का 37) यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12ए द्वारा प्रवत लक्षियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय आच निगम में स्थानान्तरित करती हैः—

कम अधिकारी/कर्मचारी का केन्द्रीय सरकार के भारतीय सं० नाम कार के अधीन अधीन स्थानांतरण आच निगम स्थायी पद के समय पद में स्थानांतरण की तारीख

1	2	3	4	5
1. श्री कल्प नाथ राम	वाल्मीकी	डस्टिंग प्रापरेटर	1-3-69	
2. श्री जोगेंद्र पाल	चपरासी	मन्देसाहुक	1-3-69	
3. श्री बी० के० बाजपाल	गोदाम कलक	गृण निरीक्षक-1	1-3-69	

[संध्या 52/1/79-एफ०सी० III(बास्तूम-II)]

## ORDER

New Delhi, the 23rd April, 1979

S. O. 1532.—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directors and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under Section 13 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India;

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the Circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-Section (1) of Section 12A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them.

Sl. No. Name of the Officer/ employees Permanent post held under the Central Govt. at the time of transfer to the Central Govt. transfer FCI

1	2	3	4	5
1. Shri Kalpa Nath Ram	Watchman	Dusting Operator	1-3-69	
2. Shri Joginder Pal	Peon	Messenger	1-3-69	
3. Shri B.K. Bajpal	Godown Clerk	Quality Inspector-I	1-3-69	

[No. 52/1/79-FC. III (Vol. II)]

## सारेश

का० भा० 1533 :—भ्रतः केन्द्रीय सरकार ने आष विभाग केन्द्रीय आष निवेशालयों उपाधि निवेशालयों और आष विभाग के बेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले आषालयों के क्षम, भृष्टारकरण, बंचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बंद कर दिया है जोकि आष निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय आष निगम के कृत्य है।

धूर यतः आष विभाग, केन्द्रीय आष निवेशालयों, उपाधि निवेशालयों और आष विभाग के बेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिवित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिवर्तन के प्रत्युत्तर में उम्में विनिविष्ट तारीख के अन्वर भारतीय आष निगम के कर्मचारी न बनने के प्रपत्रे प्राप्तयों को उक्त अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के परत्तुक द्वारा दिया गया असेक्ति सूचना नहीं दी गई।

भ्रतः भ्रत आष निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा प्रबतन संशोधित की धारा 12ए द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दो गई तारीख से भारतीय आष निगम में स्थानान्तरित करती हैः—

क्रम अधिकारी/कर्मचारी का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन समय	स्थायी पद	कार के अधीन समय	आष निगम में स्थानान्तरण के अधीन सारीका
1	2	3	4	5
1. श्री के० एम० तिवारी	--	उ० ए० लि०	25-4-69	
2. श्री वी० मुख्यम्	चपरामी	चपरामी	31-12-70	
[म० 52/5/79-एफ०सी० III]				
ग्रा० ए० ए० कम्बोदू, अवर सचिव				

## ORDER

S.O. 1533 :—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directors and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under Section 13 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India.

And whereas the following officers and employees, serving in the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the Circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-section (1) of section 12A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them.

Sl. No.	Name of the Officer/employees	Permanent post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of Transfer to the FCI.
1	2	3	4	5

1. Shri K.M. Tiwari	—	U.D.C.	25-4-69
2. Shri V. Subramaniam.	Peon	Peon	31-12-70

[No. 52/5/79-FC-III]  
S.L. KAMBOH, Under Secy.

## पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1979

का० भा० 1534 :—अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3(3) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भी बेद प्रकाश, आई०ए० एंड ए० एम० को तत्काल तथा प्रयत्ने आवेदनों तक भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्ण कालिक सदस्य (वित्त तथा प्रशासन) के रूप में नियुक्त करती है।

[म० ए० बी०-24011/37/77-ए० भा०]

गोपाल चतुर्वेदी, उप-सचिव

## MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 25th April, 1979

S.O. 1534.—In exercise of the powers conferred by Section 3(3) of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri Ved Prakash, IA&AS, as whole time Member (Finance & Administration) of the International Airports Authority of India with immediate effect and until further orders.

[No. AV. 24011/37/77-AA Part]

GOPAL CHATURVEDI, Dy. Secy.

## MINISTRY OF SHIPPING &amp; TRANSPORT

(Transport Wing)

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd May, 1979

S.O. 1535.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing)



## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P &amp; T Board)

New Delhi, the 26th April, 1979

**S.O. 1537.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12, and sub-rule(1) of rule 24 read with rule 34, of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Communications (Posts and Telegraphs) No. S.R.O. 620, dated the 28th February, 1957, namely :—

In the Schedule to the said notification:—

(1) In "Part II—General Central Service, Group C", the heading, "Office of the Chief Controller of Telegraph Stores and Controllers of Telegraph Stores (including Store Depots)" and the entries thereunder shall be substituted by the following entries namely:—

1	2	3	4	5
Office of the General Manager Telecommunications Stores and Controllers of Telegraph Stores (including Store Depots) :				
Staff in Higher and Lower Section grades or in identical scale of pay;	Deputy General Manager	Deputy General Manager	All	General Manager.
Junior Engineer; Wireless Supervisor				
	Assistant General Manager; Controller of Telegraph Stores.	(i) to (iv)	Deputy General Manager.	
All other Posts	Assistant General Manager	Assistant General Manager	All	Deputy General Manager.
	Controller of Telegraph Stores.	Controller of Telegraph Stores.	All	Deputy General Manager.
		Officer of T.E.S. Class II or Officer incharge of Stores.	(i) to (iv)	Assistant General Manager; Controller of Telegraph Stores.

1	2	3	4	5
				Depot or Administra- tive- Officer.

(2) In "Part II—General Central Service Group C," the heading, "Office of the Chief Accounts Officer, Telegraph Stores and Workshops and other offices under his jurisdiction" and the entries thereunder shall be omitted.

(3) In "Part-III—General Central Service, Group D," (a) the heading, "Office of the Chief Controller, Telegraph Stores and Controllers of Telegraph Stores (including Store Depots)" shall be substituted by the following entries, namely:—

"Office of the General Manager, Telecommunication Stores and Controllers of Telegraph Stores (including Store Depots)";

(b) the entry, "Deputy Chief Controller of Telegraph Stores" appearing in column 5 against the entry, "All Posts" under the heading indicated in (a) above shall be substituted by the following entries, namely :—

"Assistant General Manager";

(c) the heading "Office of the Chief Accounts Officer, Telegraph Stores and Workshops and other offices under his jurisdiction" and the entries thereunder shall be omitted.

[No. 153/18/78-Disc. II]

V. S. RAO, Asstt. Director Genl. (Disc.)

नई दिल्ली, 2 मई, 1979

**S.O. 1538.**—स्थायी ग्रावेग संख्या 627, विनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-सार महानियेशक से सिवान टेली-फोन केन्द्र में विनांक 1-6-79 से प्रमाणित वर प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है।

[संख्या 5-12/79-मी.एच.बी.०]

मार. सी. कटारिया, स्थायक महानियेशक

New Delhi, the 2nd May, 1979

**S.O. 1538.**—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1-6-1979 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Siwan Telephone Exchange, Bihar Circle.

[No. 5-12/79-PHB]

R. C. KATARIA, Asstt. Director General

## अम मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1979

## सुदृष्टिपत्र

का० आ० 1539.—अम मंत्रालय के आवेदा संख्या एल-12011/109/78 डी० 2-ए० दिनांक 20 मार्च, 1979 में, जिसके द्वारा इससे उपायक अनुसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में सैन्यल बैंक आफविडिया, हैदराबाद और उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवाद भेजा गया था, निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

उपर विनिविष्ट आवेदा की अनुसूची की लाइन 5 में आवे वाले वाक्यों “धारा 25” में संशोधन किया जाए और उन्हें “धारा 25 च” पढ़ा जाए।

[संख्या एल-12011/109/78-डी० 2-ए०]  
एस० के० मुकर्जी, अवर सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 9th April, 1979

## CORRIGENDUM

**S.O. 1539.**—The following amendment is made to the Ministry of Labour Order No. L-12011/109/78-D. II-A, dated the 20th March, 1979 referring the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India, Hyderabad and their workmen in respect of the matter referred to in the Schedule annexed thereto :—

The words, “Section 25” occurring in line 5 of the Schedule to the order referred to above may be amended to read as “Section 25F”.

[No. L-12011/109/78-D. II-A.]  
S. K. MUKERJEE, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1979

का० आ० 1540.—खान मुख्य निरीक्षक ने, कोयला खान बचाव नियम, 1959 के नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (i) के अनुसरण में, श्री हैदरजीत सिंह, खान सुरक्षा निवेशक को, श्री चंद्र प्रकाश के स्थान पर केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति के अध्यक्ष के रूप में नामनिविष्ट किया गया है;

अतः, यह, केन्द्रीय सरकार, कोयला खान बचाव नियम, 1959 के नियम 3 के उपनियम (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के अम मंत्रालय की अधिकृता सं० का० आ० 1261, तारीख 3 अप्रैल, 1975 में प्रस्तुत और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिकृता में, अध्यक्ष शीर्ष के अधीन, मद 1 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“श्री हैदरजीत सिंह, खान सुरक्षा निवेशक । नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (i) के अधीन खान मुख्य निरीक्षक द्वारा नामनिविष्ट निरीक्षक” ।

[का० सं० ए०-35017/3/78-एम०-1]

New Delhi, the 24th April, 1979

**S.O. 1540.**—Whereas the Chief Inspector of Mines has, in pursuance of clause (i) of sub-rule (1) of rule 3 of the Coal Mines Rescue Rules, 1959, nominated Shri Inderjit Singh, Director of Mines Safety, as President of the Central Coal

Mines Rescue Stations Committee vice Shri Chandra Prakash;

Now, therefore, in pursuance of sub-rule (1) of rule (3) of the Coal Mines Rescue Rules, 1959, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1261, dated the 3rd April, 1975, namely :—

In the said notification, under heading President, for the entries against item 1, the following entries shall be substituted, namely :—

An inspector nominated by the Chief “Shri Inderjit Singh, Director of Mines Safety. Inspector of Mines under clause (i) of sub-rule (1) of rule 3.”

[F. No. A-35017/3/78-MI]

का० आ० 1541.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 83 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त प्रक्रियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से संबंधित कोयला वानों को पहली जनवरी, 1979 से 31 मार्च, 1979 तक तीन माह की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 28 के उपबन्धों से छूट प्रदान करती है।

[संख्या एस०-29014/2/79-एम०-1]

**S.O. 1541.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 83 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby exempts for a period of three months from 1st January, 1979 to 31st March, 1979 mines belonging to the Bharat Coking Coal Limited from the provisions of section 28 of the said Act.

[No. S. 29014/2/79-MI]

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1979

का० आ० 1542.—सर्वश्री एन० के० सिंह और जी० बी० शुद्धे के पास प्रबंधक प्रमाणपत्र हैं और श्री आर० के० राय के पास सर्वेक्षक प्रमाणपत्र हैं;

और श्री एस० के० सिंह को 9 मार्च, 1978 तक इन्डस्ट्री कोलियरी में प्रबंधक-प्रभिकर्ता के रूप में नियोजित किया गया था और सर्वश्री जी० बी० शुद्धे और आर० के० राय को 17 मार्च, 1978 को उक्त कोलियरी में जमाना प्रबंधक-प्रभिकर्ता और खान सर्वेक्षक के रूप में नियोजित किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त उल्लिखित अवधि, उक्त इन्डस्ट्री कोलियरी में हुई दुर्घटना के, जिसमें चार अधिकारी की मृत्यु हुई है, संबंध में, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) या इन विनियमों के प्रविधीन प्रयोग के पालन में उक्तकी प्रक्रमता और प्रबंधक के कारण, प्रबंधक और सर्वेक्षक प्रमाणपत्र और आगे धारण करने के लिए अप्रयोग है।

अतः, यह, केन्द्रीय सरकार, कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 25 के अनुसरण में, एक व्यावाय गठित करती है जिसके एकमात्र प्रविधीकारी श्री महेंद्र सिंह, भा० प्र० से०, भायुक्त, भार्या छोटा नागपुर खण्ड, हजारीबाग होंगे। यह व्यावाय यह प्रबंधारण करने के लिए जांच करेगा कि क्या सर्वश्री एस० के० सिंह, जी० बी० शुद्धे और आर० के० राय ऐसे प्रमाणपत्र और आगे धारण के योग्य हैं या नहीं। केन्द्रीय सरकार यह भी निवेश देती है कि उक्त जांच निम्नलिखित असीसर की सहायता से की जाए, अर्थात् :—

श्री एम० एन० गुर्ज, सेवानिवृत्त मुख्य तकनीकी सलाहकार, ईस्टर्न कोलकाता लिंग, 100/3-ए, भालीपुर रोड, कलकत्ता-700027

[सं० एन० 11012/15/78-एम०-1]

New Delhi, the 26th April, 1979

**S.O. 1542.**—Whereas Sarvashri N. K. Singh and G. V. Dhurde who are both holders of Manager's Certificate and Shri R. K. Roy who is a holder of Surveyor's Certificate;

And whereas Shri N. K. Singh was employed as Manager-cum-Agent in the Industry Colliery upto 9th May, 1978 and Sarvashri G. V. Dhurde and R. K. Roy were employed in the said Colliery on the 17th August, 1978 as Manager-cum-Agent and Surveyor of Mine respectively;

And whereas it appears to the Central Government that the persons mentioned above are unfit to continue to hold the Manager's and Surveyor's certificates by reason of incompetence or misconduct in performance of their duties under the Mines Act, 1952 (35 of 1952) or under these regulations in relation to the accident that occurred in the said Industry Colliery causing loss of four lives;

Now, therefore, in pursuance of regulation 25 of the Coal Mines Regulations, 1957, the Central Government hereby appoints a Court consisting of Shri Mahendra Singh, I.A.S. Commissioner, North Chotanagpur Division, Hazaribagh, to hold an inquiry at Dhanbad to determine as to whether or not the said S/Shri N. K. Singh, G. V. Dhurde and R. K. Roy are fit to continue to hold such certificates. The Central Government further directs that the said inquiry may be conducted with the assistance of the following assessor, namely :—

Shri M. N. Guin,  
Retd. Chief Technical Adviser,  
Eastern Coalfields Ltd.,  
100/3A, Alipore Road,  
Calcutta-700027.

[No. N. 11012/15/78-MI]

नई विली, 28 मार्च, 1979

गुरुपत्र

**का० आ० 1543.**—दिनांक 24 फरवरी, 1979 के भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) के पृष्ठ 615 पर प्रकाशित भारत सरकार के अमंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 729, विनाक 14 फरवरी, 1979 में कम संख्या 2 के सामने की प्रक्रिया "सरकारी प्रधिकरण" के स्थान पर "अधिकरण" पढ़े।

[सं० एस० 29015/1/76-एम० I]  
मीना गुप्ता, भवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 1979

#### CORRIGENDUM

**S.O. 1543.**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 729 dated the 14th February, 1979 published at page 615 of the Gazette of India, Part-II, Section 3 Sub-section (ii) dated the 24th February, 1979, in the entry against serial No. 2 for "Government Advocate", read "Advocate".

[No. S. 29015/1/76-MI]  
MEENA GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 25th April, 1979

**S.O. 1544.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following ward of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the Industrial dispute between the employer in relation to the management of Nag's Kajora Jambad Section of Khandra Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan and their workmen which was received by the Central Government on 24th April, 1979.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL :  
CALCUTTA

Reference No. 4 of 1978

#### PARTIES :

Employers in relation to the Management of Nag's Kajora Jambad Section of Khandra Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited.

AND

Their Workmen.

#### APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Sri N. Das, Advocate, with Sri G. N. Singh, Sr. Personnel Officer.

On behalf of Workmen.—Sri Sunil Mazumdar, General Secretary, Ningha Mazdoor Union.

STATE : West Bengal

INDUSTRY : Coal Mines

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by their Order No. L-19012(50)/75-D.III(B)/D.IV(B), dated 30th August, 1977, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Nag's Kajora Jambad Section of Khandra Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited and their workmen, to this Tribunal, for adjudication. The reference reads as :

"Whether the action of the management of Nag's Kajora Jambad Section of Khandra Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Ukhra, District Burdwan in converting workers mentioned in the Annexure from piece-rate to time-rate from November, 1974 to January, 1976 was justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

#### ANNEXURES .

1. Janki Choudhary
2. Arjun Paswan
3. Baldeo Turi
4. Suresh Paswan
5. Reshan Turi
6. Mulari Hazam."

2. The parties duly filed their pleadings in the reference. At the opening of the case, a joint petition of compromise under the signature of the General Secretary of the Union and the Sub-Area Manager representing the employers was presented for acceptance. Four of the concerned workmen have also subscribed their thumb impressions to the petition by way of signature. I have gone through the Terms of Settlement in the joint petition of Compromise and am of opinion that the terms are fair and reasonable. A copy of the joint petition of compromise dated April, 19, 1979 is annexed hereto as a part of this Award.

3. I make an award in terms of the "Terms of Settlement" in the joint petition of compromise.

Dated, Calcutta,  
The 19th April, 1979.

S. K. MUKHERJEE, Presiding Officer  
[No. L-19012(50)(50)/75-D.III(B)/D-IV(B)]

BEFORE THE HONOURABLE PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
CALCUTTA

Ref : 4 of 1978

#### PARTIES :

Employer in relation to the management of Nag's Kajora Jambad Section of Khandra Colliery of Messrs Eastern Coalfields Ltd., Distt. Burdwan.

AND

Their Workmen

Joint Petition of Compromise

The above matter is pending for adjudication before your honour as per order of Ref : No. L-19012(50)/75-D.III(B)/D-IV(B) dated 30th August, 1977.

The six workmen concerned in the dispute discussed the matter with the management and agreed to settle the aforesaid dispute on the following terms.

## Terms of the settlement

The management with a view to settle the claims of the workmen mentioned below, agrees to pay the arrear wages due to them as full and final settlement of the case.

Name of the workmen.	Amount
1. Sri Janki Chaudhary	Rs. 853.03
2. Sri Murali Hajam	Rs. 588.44
3. Sri Suresh Paswan	Rs. 597.90
4. Sri Arjun Paswan	Rs. 604.51
5. Shri Baldeo Turi	Rs. 519.80
6. Sri Rasman Turi	Rs. 570.37

One of the workmen namely Sri Rasman Turi has been working as Haulage Khalasi/Trammer in Cat III of the N.C.W.A. and he agrees to continue to work as such.

The workmen agree that they shall have no further claim whatsoever in the above dispute.

The management shall make the payment before 18th April 1979 i.e. prior to the next date of hearing fixed by the Central Govt. Industrial Tribunal i.e., 19-4-79.

Both the parties agree that the instant dispute is fully and finally resolved by this settlement.

And they pray that the Honourable Presiding Officer may be graciously pleased to pass an Award in terms of the above settlement.

Dated : 19-4-79

On and behalf of the workers      On & behalf of the  
the six concerned workmen.      Employer.

Sd/- ILLEGIBLE  
Sub-Area Manager,  
Moira Sub-Area

L.T.I. of  
MURLI HAZAM  
L.T.I. of  
JANKI CHOWDHURY  
L.T.I. of  
ARJUN PASWAN  
L.T.I. of  
PASWAN TURI

Sd/- ILLEGIBLE  
19-4-79  
General Secretary

**S.O. 1545.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Ummer Colliery of Western Coalfields Limited, Ummer, District Nagpur and their workmen which was received by the Central Government on 20th April, 1979.

BEFORE SHRI S. N. JOHRI, B.Sc. LL.M., PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT  
JABALPUR, (M.P.)  
Case Ref. No. CCIT/LC(R)(26)/78

## PARTIES :

Employees in relation to the management of Ummer Colliery of Western Coalfields Limited, Ummer, District Nagpur and their workman, Shri K. D. Chandy, House No. 121, Lala Line, Gora Bazar, Kamtee, District Nagpur (M.S.).

## APPEARANCES :

For Workman—Shri Gulab Gupta, Advocate.  
For Employers—Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mines. DISTRICT : Nagpur (M.S.).

## AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide its Order No. L-18012(11)/77-D-IV(B), Dated, 11th May, 1978, for the adjudication of the following industrial dispute :—

“Whether the action of the management of Ummer Colliery of Western Coalfields Ltd. in dismissing Shri K. D. Chandy, Dumper Operator Grade I with effect from 22nd September, 1976 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?”

2. On 2-8-1976 Shri Chandy was charge-sheeted as follows :—

“On 29-7-1976 you were on duty as a Dumper Operator in the IIIrd Shift commencing from 9.00 P.M. As a routine procedure, dumper No. 350 was properly checked in workshop and was handed over to you for operation.

Knowing fully well that unauthorised riding on dumpers is strictly prohibited, you had allowed 7 unauthorised persons to ride on your dumper, which was proceeding towards quarry No. 2 of this project.

You were also instructed by the Shift Incharge Shri R.D. Shorey on the said date not to use the cause way as it was overflowing due to the floods in Amb river. The entire traffic was diverted over the newly constructed P.W.D. Bridge on the said date due to flood on the cause way. When you approached near the cause way you had stopped your dumper and saw the water overflowing from the cause way but you did not care for the danger looming just in front of you because you were under the influence of alcohol, which was confirmed according to your blood examination report, and while trying to cross over the flooded cause way, your dumper was toppled resulting into 3 fatal accidents of our workmen.

I hereby require you to state as to why disciplinary action even to dismissal from the services of the Western Coalfields Limited should not be taken against you as per the certified Standing Orders by which you are governed on account of the following charges :—

- (i) 17(c).—Wilful insubordination or disobedience, whether alone or in conjunction with others, or any lawful or reasonable order of a superior.
- (ii) 17(e).—Drunkenness while on duty at the place or work.
- (iii) 17(i).—Causing wilful damage to work in progress or to property of the employer.”

3. Of the facts narrated in the extracted charge report as above, it is not disputed that Shri Chandy did operate the dumper which met with the accident on the over flowing cause way causing loss of three lives of the workmen who along with others were allowed to ride on the dumper. After domestic enquiry Shri Chandy was found guilty of the charges levelled against him with the result that the order of dismissal from service was passed against him.

4. Management's case is that Shri Shorey Incharge of the Third Shift had specifically asked the dumper operators to go only by P.W.D. Bridge on the P.W.D. Road, still Shri Chandy wilfully disobeyed the orders and made an attempt to negotiate the overflowing cause way. He further disobeyed the general routine instructions which had been sufficiently notified that no person should be allowed to ride on a dumper. Shri Chandy was drunk. He negotiated the cause way taking a calculated risk and that ultimately resulted in the damage to the machinery of the dumper and that hampered the progress of the work. The domestic enquiry was proper and unbiased and all reasonable opportunity to defend was given.

5. The case of the workmen is that the dumper required repairs, still he was made to operate it. Shri Shorey had not given any instruction to go via P.W.D. Road after crossing bridge there. In any case the dumper could not be taken to P.W.D. road because it has no such permit and the order was therefore not a lawful order even if it is assumed that such an order was given by Shri Shorey. He had denied

that he was drunk. On the other hand his plea is that from the hospital when he came down to his house he consumed some whisky because he was feeling very nervous and the tension was mounting in his head on account of the accident and non-traceability of the two dead bodies of the workers. This consumption of the liquor must be responsible for the presence of alcohol in his blood samples which were taken subsequently when he was called back to the hospital in a vehicle. He was not drunk when the accident took place. He did not intend to damage the property of the management nor he wanted that the work should stop. Thus there was no wilfulness in the consequence that followed. The findings of the domestic enquiry were alleged to be perverse.

6. Shri Gulab Gupta, Advocate, appearing for the workman stated at the bar that he would challenge the domestic enquiry not on any procedural aspect but only on the ground of perversity. Both sides refused to adduce any evidence on the question of perversity except that the management formally proved the enquiry proceedings and other documents. However, the management took a stand that in case it is held that the findings were perverse the management would like to adduce evidence before the Tribunal. It is with this preface that I shall now proceed to examine the question of perversity as follows.

7. The first charge of dis-obedience can be divided into two parts. The first part relates to the dis-obedience of the orders given by Shri Shorey. This fact has been challenged from three angles. Firstly it is said that Shri Shorey was not a superior officer whose orders the workman was bound to follow.

Secondly he gave no such orders and thirdly the orders were not lawful hence Shri Chandy was under no obligation is based on evidence which he has rightly believed. The Shorey was Incharge Supervisor of that shift. His conclusion is based on evidence which he has rightly believed. The fact that Shri Shorey was not paid the acting allowance for acting as Pit Supervisor is not of much consequence when he was in fact acting a defacto Pit Supervisor and was giving orders which were being followed by others. The authority does not flow simply through the payment of the officiating allowance. It emanates from the defacto working position of a person at a place of hierarchy which has the sanction of the higher officers. There is no evidence that Shri Shorey had himself assumed that position and was not deputed by the Manager to work as Pit Supervisor that day. At the most it can be said that evidence on this point is not as clinching and convincing as it should have been had the management produced the order appointing Shri Shorey to work as Pit Supervisor. But Enquiry Officer has the jurisdiction to place reliance even on such evidence. It is, therefore, held that this point has no force.

8. On the factum of giving orders that the dumper operators should not go by cause way which was overflowing the Enquiry Officer has relied on the evidence of Shri Shorey (M.W.1) and Shri Appadurai (M.W.6) whose statements appear at pages 34 to 38 of the domestic enquiry file. Shri Appadurai, who was also in the same place where Shri Chandy was standing, did hear such orders being given by Shri Shorey. It is true that one of the witnesses had said that the engines of the dumpers were in starting position when these orders were given. On that basis it is argued that it is quite possible that Shri Chandy may not have heard the instructions in that loud noise created on account of the started engines of the dumpers. The theory of benefit of doubt is not applicable to domestic enquiry proceedings and as such the Enquiry Officer did not think it necessary to comment upon such possibilities. It cannot be said that his placing reliance on the evidence of these two witnesses was either illegal or improper. He has rejected the evidence of the defence witnesses on this point for cogent reasons. It is, therefore, held that it stands established that factually such orders were given by the Shift Incharge Pit Supervisor, Shri Shorey.

9. Third point of attack is about the lawful nature of those orders. The sub-area Manager, Umre, has in his report note on the accident prepared on 1-8-1976 stated that 'the line on which the new P.W.D. bridge has been constructed falls in the acquisition of N.C.D.C. whereas the cause-way and part of the road leading to No 2 quarry

belongs to the Maharashtra State P.W.D. The cause-way and the road leading to the No. 2 quarry were allowed for use of Umre Colliery since 26-11-1970 by the Executive Engineer B&C, Nagpur. Copy of the permission was enclosed by him with that statement. He further stated in the last line in his report that correspondence was going on between the N.C.D.C. and P.W.D. for the barter transfer of the land acquired but it had not been finalised till the date this accident took place. What was the nature of the acquisition, whether the land including the P.W.D. stood vested in N.C.D.C. or it was to vest when the delivery of possession was to be given are mute questions which remained unanswered by this report. There is no positive evidence of the vesting of the road in N.C.D.C. Some of the witnesses are however positive that the dumpers could not be validly operated on the State road and bridge. Normally for plying a dumper on the road a permit is required and the road tax is to be paid under Motor Vehicles Act and as the dumper which Shri Chandy operated was not having that permit etc, the order, to take the dumper via P.W.D. bridge and P.W.D. road, could not be said to be a lawful order.

10. As was held in Tata Iron and Steel Co. Vs. Its workmen (1967(14) FIR 55 Patna), the workman was not bound to follow that order which was not lawful and to this extent the charge of dis-obedience of lawful orders is not made out. This aspect of the matter was not considered by the Enquiry Officer.

11. However, I may hasten to add that disregard of the orders which were not lawful did not entitle Shri Chandy to take a calculated risk and go via cause-way which was overflowing. The order given by Shri Shorey had its positive as well as negative aspect. It was positive to the extent it gave the direction that the dumpers should be taken via P.W.D. road and bridge. Shri Chandy could disregard them as they were not lawful orders. He could have refused to take the dumper that way and since cause way was overflowing he could have validly refused to ply. He did not do so.

12. At the same time Shri Shorey had given negative direction also in the sense that he had asked all dumper operators not to go via cause-way which was overflowing. This negative order or order of prohibition was followed by Shri Chandy only in breach. There was nothing unlawful so far as this prohibitory part of the direction is concerned. Shri Chandy therefore in ultimate analysis can be held to have been rightly found guilty of dis-obedience of the lawful orders given by Shri Shorey.

13. The second aspect of this charge of disobedience is that there was a well published written direction that no person should be allowed to ride on the dumper, was followed by Shri Chandy in breach when he allowed other workers to ride on it specially those who lost their lives. The Enquiry Officer was correct in his analysis of evidence on this point when he said that the merefact that inspite of that order it was usual for the workman to ride on dumper cannot be a good justification for Shri Chandy to have fallen in the line of persons disobeying the orders and claim exoneration on the basis of that illegal practice saying that he had done only what others were doing. No illegal practice can be pleaded as a justification for an illegal act. Officers may not have been very strict with respect to those instructions till everything was going on safe but they cannot remain silent and a workman disobeying that order cannot remain exonerated when he involves the persons riding the dumper in a fatal accident. I am, therefore, of the view that Shri Chandy has been rightly held guilty of dis-obedience of the lawful orders. Defying lawful orders is a serious misconduct which may entail the punishment of dismissal specially in view of the consequences that have followed the disobedience.

14. This brings me to the charge of drunkenness. The Enquiry Officer has rightly relied on the expert opinion of Dr. Mishra on this point. There is no perversity, in that finding. Dr. Mishra has stated that soon after the accident when the victims were brought and he was attending them he found the smell of liquor coming from the side where Shri Chandy was standing. However, as he was busy in attending to the victims whose condi-

tion was serious he did not take notice of it specially because he was not asked by that time to consider whether Shri Chandy had consumed liquor or not. He had asked Shri Chandy to stay when Shri Chandy was insisting to go back to his home. Admittedly Shri Chandy was anxious to allay the fears of his family members. He was himself feeling nervous, and the tension was beating his head. He went home and he consumed whisky. Thereafter he was called back to the hospital and his blood samples were taken which indicated presence of liquor at a percentage higher than the one necessary for prosecuting a man for drunkenness. Shri Chandy's explanation was that it was so because he had consumed whisky at his residence after the accident.

15. This explanatory defence theory has been categorically ruled out by the statement of the Doctor. According to him two blood samples were taken—one at 3.30 A.M. and the other at 4 A.M. He categorically stated that the alcohol must have been consumed by Shri Chandy more than 6 hours before the samples were taken i.e. sometime before 9.30 to 10 P.M. The accident took place at about 10.15 P.M. according to the statement of Shri Shorey. On the other hand, according to the statement of Dr. Mishra Shri Chandy went to his house after zero hour and consuming liquor at about 12.15 in the night. That whisky could not produce that percentage of alcohol at 3.30 A.M. or 4 A.M. because more than 6 hours are required for the alcohol to concentrate in the blood. This expert evidence read with the report of pathological examination of blood samples amply corroborate the statement of Dr. Mishra that the smell of liquor was coming from the side where Shri Chandy was standing in the hospital before he went to his home. This evidence is sufficient for justifying an inference by the Enquiry Officer that Shri Chandy had consumed alcohol and was in the state of intoxication when he operated the dumper and caused the accident. The finding of the Enquiry Officer on this point cannot therefore be said to be perverse. Condoning drinking by a driver who is going out on high way incharge of heavy equipment would be courtious disastrous consequences. The consideration of public safety out-weigh the consequences of punishment to any individual employee on this count and those driving in state of intoxication can rightly justify a punishment of dismissal.

16. Lastly there is a charge of wilful stoppage of work and wilful damage to the property of the employer. It has been rightly argued by the learned Counsel for the workman that Shri Chandy had no intention to cause the stoppage of work wilfully or to cause damage to the dumper knowingly. Thus the wilful part of the charge cannot be held to have been sustained by any evidence.

17. However, from the circumstances of the case, it is clear that Shri Chandy was reckless in driving dumper through the overflowing cause way. Recklessness is one where the person is unmindful of the consequences and takes a calculated risk. Knowing that such serious consequences could follow, when he had been asked not to operate dumper through overflowing cause-way, is an act of taking that calculated risk which may amount to recklessness. In any case in advertance or gross negligence was obvious. Such an act itself amounted to misconduct whether defined in the Standing orders or not and is gross enough to entail a punishment of dismissal.

18. It was held in *Smith Vs. Wemves Coal Co. Ltd.* (1937) 37 B.W.C.E.C. 488(490-492) (Refer page 496 of Kothari's Law relating to disciplinary matters and Standing Orders) that a misconduct may arise out of simple orders or instructions or it may arise out of acts on the part of the workman which show a dis-regard for duty of care which he owes to his own safety or to safety of others and/or to the safety of other people's property. Mere wrong application of a particular clause of the Standing Orders cannot exonerate the workman from a misconduct which is in fact made out against him. In *Doaba Roadways Ltd. Vs. Labour Court, Jullunder* (42 FJR 140 P & H) a bus conductor who was holding a driving licence was dismissed from service when he tried to drive the vehicle in the absence of the driver endangering the life of the passengers, the Court said that he acted desparado and unmindful of the circumstances by indulging in a rash act of driving the vehicle himself even when

no accident had taken place. In the present case crossing a threatening river through a overflowing cause-way in the night when signal lights were not there and when he had been specifically directed to abstain from taking the dumper through that cause-way, Shri Chandy acted as a desparado involving risk to the lives of the persons who had been allowed to ride on a dumper inspite of prohibitory order which had been well published, and thereby committed a serious misconduct. Bombay High Court in *Sharda Prasad Vs. Central Railway* (1960-f-L.I.S. 167) illustrated acts which amounted to misconduct and one of them was 'an act of neglect, even though isolated which tends to cause serious consequences.'

19. The Enquiry Officer has thus rightly held him guilty of misconduct. The past clean record does provide extenuating circumstance but I am of the view that the gravity of the misconduct was such that even the past good conduct cannot help the man. The order of dismissal was justified. Reference is answered accordingly.

12-4-1979.

S. N. JOHRI, Presiding Officer  
[No. L-1802(11)/77-D.IV(E)]

**S.O. 1546.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Ningha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Limited, P.O. Kalipahari (Burdwan) and their workmen which was received by the Central Government on 19th April, 1979.

**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CALCUTTA**

**Reference No. 2 of 1977**

**PARTIES :**

Employers in relation to the management of Ningha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd.,

**AND**

Their Workmen.

**PRESENT :**

Sri Justice S. K. Mukherjee—Presiding Officer.

**APPEARANCES :**

On behalf of Employers—Shri N. Das, Advocate with Shri N. Jha, Sr. Personnel Officer.

On behalf of Workmen—Shri N. C. Roy, Advocate, with Shri Sunil Mazumdar.

**STATE : West Bengal**

**INDUSTRY : Coalmine**

**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, by their Order No. I-19012/39/76-D III B, dated 11th February, 1977, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Ningha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., and their workmen, to this Tribunal for adjudication. The material part of the order of reference reads :

"Whether the action of the management of Ningha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P. O. Kalipahari (Burdwan) is justified in terminating the lien of appointment of Shri Jairam Nunia, Wagon Loader of Ningha Colliery with effect from 7-7-75 is justified ? If not, to what relief workman concerned is entitled ?"

2. The concerned workman was a permanent workman of the Ningha Colliery. He was originally granted leave from May 9, 1975 to May 20, 1975. On leave being granted he left for his village home. His case is that as he was unable to resume his duties on May 21, 1975 he sent a registered letter on May 23, 1975 under Postal Receipt No. 3282 for extension of leave. He further pleaded that he was not aware

whether his prayer for extension of leave had been granted or not. Thereafter, he again applied for extension of leave by a letter of June 6, 1975 addressed to the Manager sent by Registered post under Postal Receipt No. 3307 of the Dhanbad Post Office. He did not receive any reply to the said letter.

3. There is no dispute that on 17th June, 1975 the concerned workman reported for duty. He was not allowed to resume his duties and a charge sheet was served on him. The charge sheet was in these terms :

"You proceeded on authorised leave from 9-5-75 to 20-5-75. Subsequently a letter No. N/Lab/60/75/1273 dated 31-5-75 has been sent to you intimating that your extension has been granted till 3-6-75 and no further extension will be granted later on. Your act of commission denotes as under :

1. You wilfully disobeyed responsible order of superior.
2. You are absenting continuously without permission and without satisfactory cause for more than 10 days.

Thus, you have violated Sec. 29(1) & (16) of the Standing Orders for the Coal Mining Industry.

Suspended pending enquiry."

It is common case that the enquiry was dropped by the management soon thereafter.

4. The case of the concerned workman, as pleaded and deposed by him, is that he never received the letter of May 31, 1975. Thereafter, by a letter dated 7th July, 1975 the management terminated the lien of the concerned workman on his appointment with effect from 7th July, 1975. The letter reads :

"You were granted authorised leave from 9-5-75 to 20-5-75 and subsequently extended leave from 21-5-75 to 3-6-75, and you are over-staying your leave since 4-6-75 to 3-7-75 for 27 days.

As a result you have lost lien on your appointment in accordance with the Section 11 of the standing orders for Coal Mining Industry. Your name has been kept in Badli-list." (Ext. W-2).

It is contended that this action of the management in terminating the lien is illegal. The union submits that he should therefore be permitted to resume his duties with immediate effect.

5. The management has pleaded that on the expiry of his leave on May 20, 1975, the concerned workman did not report for duty. A telegram was received from him on May 26, 1975, praying for extension of leave by two weeks on the ground that his wife was lying seriously ill. The management acceded to his prayer and extended his leave upto 3rd June, 1975. By a letter dated 31st May, 1975 they advised him that his leave had been sanctioned till 3rd June, 1975 and no further extension of leave would be granted. On June 9, 1975 a telegram was received from the concerned workman asking for a further extension of leave by one month. In the telegram no reason was given for extension.

6. The concerned workman not having resumed his duties on the expiry of the extended period of leave, a charge sheet was served on him to which reference has already been made.

7. It is stated by the management that they decided to take a lenient view of the matter and did not proceed with the enquiry. Under the provisions of Standing Order No. 11 of the certified Standing Orders of the colliery, they terminated the lien of the concerned workman on his appointment and placed his name in the badli list.

8. The certified Standing Orders under which action was taken by their management were in force in the Colliery before nationalisation of coal mines. The management claims that the said Standing Orders are still lawfully in force. These are exhibit M-4 in this case.

9. It was submitted on behalf of the management that action against the concerned workman was validly taken under Standing Order No. 11 of the said Standing Orders which provides as follows :

"11. Any direct employee of the Company other than a minor or loader who desires to obtain leave of ab-

sence shall apply in writing to the head of his department or the Manager of the Colliery. Employees who due to illiteracy do not apply in writing must apply verbally. If the employee remains absent beyond the period of leave originally granted or subsequently extended he shall lose his lien on his appointment unless :

- (1) he returns within 8 days of the expiry of the leave, and
- (2) gives an explanation to the satisfaction of the Manager of his inability to return before the expiry of leave. In case the employee loses his lien on the appointment he shall be entitled to be kept on the 'Badli' list.

10. Shri N. C. Das, learned advocate appearing on behalf of the concerned workman contended that the old certified Standing Orders cannot be held to have been lawfully in force after nationalisation of coal mines. He argued that in order to be valid, Standing Orders must be in conformity with the Model Standing Orders in Schedule IA to the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946. He contended that as there is nothing in Model Standing Orders which corresponds to Standing Order No. 11 of the certified Standing Orders on which the management relies, the said Standing Order must be held to be invalid. He went further and contended that on nationalisation of the mine, the old certified Standing Order lapsed and as no such Standing Orders have been certified, the model Standing Orders must apply. He relied on clause (d) of Standing Order No. 10 of the model Standing Orders; in particular, he relied on the provisions that "if the workman after proceeding on leave desires an extension thereof, he shall apply to the Manager, who shall send a written reply either granting or refusing extension of leave to the workman. Sanction/refusal of leave should be communicated to the workman in writing invariably." He submitted that the concerned workman is entitled to the benefit of the said Standing Order.

11. Mr. Roy also relied on Standing Order No. 17 of the model Standing Orders which relates to disciplinary action for misconduct. He relied on clause (ii) of the said Standing Order which provides :

"(ii) No order of punishment under Standing Order No. 17(i) shall be made unless the workman concerned is informed in writing of the alleged misconduct and is given an opportunity to explain the allegations made against him. A departmental enquiry shall be instituted before dealing with the charges. During the period of enquiry, the workman concerned may be suspended. The workman, may take the assistance of a co-worker to help him in the enquiry, if he so desires. The records of the departmental enquiry shall be kept in writing. The approval of the owner, agent or the chief mining engineer of the employers or a person holding similar position shall be obtained before imposing the punishment of dismissal. A copy of the enquiry proceedings shall be given to the workman concerned on the conclusion of the enquiry on request by the workman."

Mr. Roy submitted that there has been no compliance with the aforesaid provision of Standing Order No. 17 of the model Standing Orders, and therefore, the action taken by the management is not justified in law.

12. Mr. Roy further submitted that if he was right in his submission that the old Standing Orders had lapsed on nationalisation of coal mines, no action could have been validly taken against the concerned workman under Standing Order No. 11. In the alternative, he argued that assuming that the old Standing Orders did not lapse in toto, any Standing Order which was not to be found in the Model Standing Orders must be deemed to be invalid. Neither Standing Order No. 11 nor anything which at all corresponds to it, occurs in the Model Standing Orders and therefore Standing Order No. 11 must be held to be inapplicable.

13. Mr. Roy advanced a further alternative argument that if the old Standing Orders are still in force, then Standing Orders Nos. 29 and 30 should be held to govern the case. The relevant provisions of Standing Order No. 29 and Standing Order No. 30 on which Mr. Roy relied may be set out :

"29. An employee may be suspended, fined or dismissed without notice or any compensation in lieu of notice, if he is found to be guilty of misconduct, provided

that suspension without pay whether as a punishment or pending an enquiry shall not exceed 10 days. The following shall denote "Misconduct":

(16) Continuous absence without permission and without satisfactory cause for more than 10 days.

30. No orders of punishment by way of suspension, dismissal or fine shall be made unless the employee concerned is informed in writing of the alleged misconduct and is given an opportunity to explain the circumstances alleged against him. The approval of the owner, Agent or Chief Mining Engineer of the Company is required in every case of dismissal and when circumstances appear to warrant it that officer shall institute separate independent enquiries before dealing with the charges against an employee. During the period enquiries are being made on account of alleged misconduct the employee concerned shall be suspended."

He submitted that as the management has not proceeded under Standing Order No. 30 but under Standing Order No. 11, the order terminating lien on the appointment of the concerned workman is void and of no effect in law.

14. Sri N. Das, learned advocate appearing on behalf of the management submitted that there is nothing in the Industrial Employment (Standing Orders) Act by reason of which the existing certified Standing Orders can be held to have been superseded. On the contrary, it is abundantly clear from Sec. 10 of the said Act that Standing Orders finally certified under the Act will not, except on agreement between the employer and the workmen, be liable to modification until the expiry of six months from the date on which the Standing Orders or the last modifications thereof came into operation. He argued that if on nationalisation the old Standing Orders had automatically lapsed such a provision could not operate. Sri Das also relied on a decision of the Karnataka High Court in the case of the Management of Ideal Jawa (India) Pvt. Ltd. & Ors. v. T. Ramu and Others, the substance of which is reported in 1979 Labour & Industrial Cases, NOC 32, p. 22. Under the Standing Orders of a Company, the workmen were entitled to wages during the period of their suspension pending inquiry only if no penal action was taken against them as a consequence of the inquiry. The Model Standing Orders were subsequently amended entitling the workmen to get subsistence allowance during suspension. The Certified Standing Orders were not amended. The question arose whether the workmen who were suspended and then dismissed after inquiry were entitled to any payment for the period of suspension. The Court held:

"there was no provision contained in the Standing Orders of the company which entitled the workman to get the subsistence allowance or any provision contained in the Standing Orders Act on the basis of which it could be held that any amendment made by the State Government to the Model Standing Orders can be enforced straightway without any amendment to the certified Standing Orders of the particular industry or that the provisions contained in any amendment made by the Government under the Act can be treated as an amendment to the certified Standing Orders. Until a provision for payment of subsistence allowance is incorporated in the Standing Orders of the Company, the Labour Court could not grant the relief on the basis of the amendment made to the model Standing Orders by the State Government.

Sri Das further submitted that Section 12-A of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 makes it clear that where there are certified Standing Orders governing an industrial establishment, there is no scope for application of the model Standing Orders. In that view of the matter, he submitted that the case is governed by the old Standing Orders of the establishment which were and are in force.

15. Sri Das then pointed out that in terminating the lien of the concerned workman the management has taken action under Standing Order No. 11. Disciplinary proceedings having been dropped there was no further question of imposing any punishment on the concerned workman on the ground of any misconduct committed by him. There is no scope, therefore, for application of Standing Order No. 29 and 30.

Those are provisions which relate to suspension, fine or dismissal. The present case is concerned with loss of lien on appointment under the provisions of Standing Order 11. All the ingredients of Standing Order No. 11 have been satisfied i.e. the employee concerned remained absent beyond the period of leave originally granted or subsequently extended and failed to return within 8 days of the expiry of leave. The action taken by the management being in due compliance with Standing Order No. 11 must therefore be held to be valid.

16. In the written statement filed on behalf of the concerned workman it was stated that as he was unable to resume duties on the expiry of his leave on May 20, 1975, he sent a registered letter on May 23, 1975 under a postal receipt for extension of leave. It was further stated that not having received any reply as to whether his prayer for extension had been granted or not, he again applied for extension of leave by a letter sent by registered post under a postal receipt. The management's case was that neither of these letters have ever been received. What was received was a telegram on May 26, 1975 praying for extension of leave by two weeks. That telegram has been made Ext. M-1. The management's letter dated 31st May, 1975 sent by registered post has been made Ext. M-7. The workman denied that he received the letter. The management further stated that a telegram was received from the concerned workman on June 9, 1975, Ext. M-2, asking for further extension of leave. It was contended by the management that before the receipt of that telegram intimation had been given to the concerned workman by the aforesaid letter of 31st May, 1975 that no further extension beyond 3rd June, 1975 could be granted.

17. The concerned workman gave evidence before the Tribunal. It is strange that he not only failed to produce copies of the letters he claimed to have sent by registered post or the postal receipts to which a pointed reference was made in his written statement, but also did not state in his evidence that he had sent those letters. In these circumstances, it must be held that the statements made with regard to despatch of letters in his pleading are not true. He admitted having sent the two telegrams. He denied the receipt of the letter dated 31st May 1975. The despatch of the original of that letter was proved satisfactorily by Sultan Hossain, the despatch clerk in the employment of the colliery by entries in the register (Ext. M-5). The register itself has been made an exhibit by consent (Ext. M-6). He further proved the despatch of this letter by post by an entry in the Peon Book which has been marked Ext. M-9.

.18 It was not disputed that when the letter of 31st May, 1975 was despatched, and also for sometime thereafter, the concerned workman was living in his village home where the said letter was addressed by registered post. Having regard to the evidence on record, I hold that the letter dated 31st May, 1975 was duly despatched by registered post and the concerned workman must be presumed to have duly received it. It seems to me highly probable that the second telegram which was received by the management on 9th June, 1975 was despatched after the concerned workman had received the letter of 31st May, 1975. Although the management did not immediately reply to his application for extension of leave by the telegram received on May 26, 1975, they did grant the leave as applied for and sent due intimation thereof by the letter dated 31st May, 1975. Leave granted to the concerned workman validly expired on 3rd June, 1975. Admittedly he reported for duty only on the 17th June, 1975. In those circumstances the management in exercise of the powers conferred by Standing Order No. 11 terminated the lien and placed him on the badli list.

19. On the question whether the old Standing Orders are lawfully in force, I am of opinion that they are. I accept the submissions made by the learned advocate appearing on behalf of the management. There is nothing in the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 pursuant to which it is possible to hold that on nationalisation of the mines the old Standing Orders lapsed or that they have been superseded by the Model Standing Orders. Moreover, there is no evidence that the management acted mala fide in not proceeding with the enquiry and taking recourse to Standing Order No. 11.

20. I am unable to accept the contention of Mr. Roy, learned advocate appearing on behalf of the concerned workman that Standing Orders Nos. 29 and 30 govern this case. It was for the management to decide under which Standing Order they should proceed against the concerned workman for absence from duty on expiry of leave. They chose to take

action under Standing Order No. 11 by their order dated 7-7-75.

21. In conclusion, reference may be made to a decision of the Patna High Court in the case of *Pure Kustore Colliery v. Khan Mazdoor Congress and others*, 1969 I.L.L.J., 133 where the Standing Order No. 11 was in terms identical with Standing Order No. 11 in the present case. In that case the Tribunal directed that the workman be reinstated to his permanent appointment. The order was passed on the ground that it was not open to the management to terminate the lien of absentee employee on his permanent appointment and place him on the badli list without giving him an opportunity to explain and produce evidence in support of the explanation as to why he was unable to join his work in time. The Court quashed the order of the Tribunal and held that from the relevant terms incorporated in Standing Order No. 11, it was clear that the employee must lose his lien on his appointment unless he returns within eight days of the leave and also gives a satisfactory explanation as to his inability to return in time. I am in respectful agreement with the learned Judges of the Patna High Court who decided that case. Having regard to the Standing Orders by which the parties are governed, I hold that the said order is valid and justified.

22. I now proceed to answer the reference as follows : The action of the management of Ningha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Kaliphahari (Burdwan), is justified in terminating the lien of appointment of Shri Jairam Nunia, Wagon Loader of Ningha Colliery with effect from 7-7-75. The workman concerned is not entitled to any relief.

This is my award.

S. K. MUKHERJEA, Presiding Officer.  
Calcutta the 5th April, 1979.

[No. I-19012/39/76-D. III(B)/D. IV(B)]  
SHASHI BHUSHAN, Desk Officer.

New Delhi, the 27th April, 1979

**S.O. 1547.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Khetri Copper Complex of Hindustan Copper Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th April, 1979.

**CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN,  
JAIPUR**

**PRESIDED BY SHRI S. R. KOTHARI, JUDGE**  
Reference Case No. CTT-11 of 1976

Ref. :—Government of India, Ministry of Labour New Delhi Order No. L-43012(3)/76-D-IV-(B) dated 20th October, 1976.

In the Matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

The Management of Khetri Copper Complex of Hindustan Copper Limited, Khetri Nagar.

AND

Their Workmen

**APPEARANCES**

For the Management—Shri S.B.L. Agrawal.

For the Workman.—Shri Ashok Parihar.

**AWARD**

The Government of India by the above referred notification, has referred the following dispute for adjudication by this Tribunal :—

Whether the action of the management of Khetri Copper Complex of Hindustan Copper Limited in dismissing Shri Harlal Singh Punia, Mechanic 'B' in the mine of Khetri Copper Complex from service with effect from 23-9-75 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

2. On receiving the reference, notices were issued to both the parties. The Khetri Tamba Shramik Sangh, Khetri Nagar filed a claim alleging that Shri Harlal Singh was working as Mechanic 'B' in the Mines and on 23-3-75 or 25-3-75 he did not commit any misconduct but he was levelled with wrong charges of misconduct and was ultimately dismissed by the Disciplinary Authority on the false report of the Domestic Enquiry Officer. His dismissal was illegal and unfair and that being so, it deserves to be set aside. The Management has in reply submitted that Shri Harlal Singh was dismissed after proper enquiry and his dismissal is legal and proper and so no interference by the Tribunal is called for.

3. Before deciding this dispute, it would be pertinent to give certain facts which has led to the present dispute. Shri Harlal Singh was Mechanic 'B' in the Mines owned by the Management. On 23-3-75, he was charge-sheeted with having committed assault with his fists after hurling abuses and threats to Shri Devesh, Executive Engineer while he was on his duty. He was also charge-sheeted on 24-3-75 that on 23-3-75 he forcibly stopped Shri Niwas Rai, Executive Engineer from going to his office and assaulted him and snatched away official papers and tore them off after hurling abuses and obscene gestures towards him. Shri Harlal Singh denied the charges. A domestic enquiry was started and the Enquiry Officer held the charges as proved. The Disciplinary Authority on this report and after hearing Shri Harlal Singh, dismissed him from service. The Union raised the dispute before the Government and so the dispute has been referred to this Court for decision. Before proceeding to decide the dispute it will not be out of place to mention here that this reference is under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act. In the original Act there was no provisions specifically defining the powers of the Tribunals, to give relief in case of discharge or dismissal of the workmen. However, on 15-12-71, Section 11A was inserted in the main Act by the Industrial Disputes Amendment Act, 1971 (Act No. 45 of 1971) which defines the powers of the Labour Courts and Tribunals to give appropriate relief in case of discharge or dismissal of workmen. Section 11A runs as under :—

"11-A. Powers of Labour Courts, Tribunals and National Tribunals to give appropriate relief in case of discharge or dismissal of workmen. Where an industrial dispute relating to the discharge or dismissal of a workman has been referred to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal for adjudication and, in the course of the adjudication proceedings, the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, is satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified, it may, by its award, set aside the order of discharge or dismissal and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, or give such other relief to the workman including the award of any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal as the circumstances of the case may require :—

Provided that in any proceeding under this section the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall rely only on the materials on record and shall not take any fresh evidence in relation to the matter."

4. It would be pertinent to note here that before insertion of this section it was consensus of the judicial opinion that the nature and scope of the jurisdiction of the Tribunal was merely of a supervisory nature to see whether the enquiry was fair and proper and for that purpose the Tribunal could only examine whether there was want of good faith or there was victimisation or unfair labour practice on the part of the employer or the Management was guilty of basic error or violation of principles of natural justice or the findings of the Enquiry Officer were completely baseless or perverse. If the enquiry did not suffer from any of the defects the Tribunal had no jurisdiction to go into the merits of the case. However, with the insertion of Section 11A a material change has been brought out in the Act. The words "in the course of the adjudication proceedings, the Tribunal is satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified" in Section 11A clearly indicate that the Tribunal is now clothed with the power to reappraise the evidence in the domestic enquiry and satisfy itself whether the said evidence relied by the management establishes the misconduct alleged against the workman. What was originally a plausible conclusion that could be drawn by a employer by the evidence, has now given place to a satisfaction being arrived at by the Tribunal

that the finding of misconduct is correct. The Tribunal is now at liberty to consider not only whether the finding of misconduct recorded by the employer is correct but also differ from the said finding if a proper case is made out. The Tribunal has to consider the evidence on record and come to conclusion one way or the other and in cases where an enquiry has been held by the employer and a finding of misconduct arrived at, the Tribunal can now certainly differ from the finding in a proper case and hold that no misconduct is proved. I am fortified in taking the above view from the observations of Their Lordships of the Supreme Court in a case reported in 1973-I LLJ. 278 para 33 and 37 and the decision of the Kerala High Court reported in 1979 (38) F.L.R. 288.

5. In view of the above position of law and the fact that it has been held by my predecessor that the domestic enquiry was fair. I now proceed to consider the evidence on record to find out whether the conclusion arrived at by the Enquiry Officer was correct or not.

6. The charge against Shri Harlal Singh was that he assaulted Shri Devash, Executive Engineer, hurled abuses on him and threatened him, with dire consequences. He was also charged with assaulting Shri A. Niwas Rao, Senior Executive Engineer by forcibly stopping and snatching the official papers from him. Shri Devash was examined as M.W. 1 in the enquiry proceedings. He has categorically said that on 23-3-75 he was hit on the face near the ear where-by he lost his balance and fell on the table as he was going towards supervisor's room, to enquire about the break-downs in the back shift. He saw Shri Harlal Singh coming forward to give him another blow; meanwhile some persons caught hold of him and he went away. He has admitted in cross-examination that he did not get himself examined medically after the incident and the persons who had caught hold of Shri Harlal Singh were Shri R. S. Solanki, Shri Gugal Singh and a few others, whose names he does not remember. The witness was cross-examined at length and there is nothing to disbelieve his testimony, as it does not transpire that the witness is in any way interested to depose some against Harlal Singh, to implicate him falsely. Not a single question has been put to him in cross-examination to attach any motive which would tempt the witness to implicate Shri Harlal Singh falsely, in any proceedings. In his affidavit before the Court, Shri Harlal Singh has deposed that Shri Devash had personal enmity and Malice against him, but he has not shown as to why Devash bore any malice or enmity against him. The fact, that he has not put any question to the witness in cross-examination, during the enquiry shows, that it is merely an after-thought. M.W. 3 Shri A. S. Rao had also categorically stated that when he was entering the supervisor's room, he saw Shri Devash leaning on the table and found Shri Harlal Singh in an aggressive mood trying to change Devash with his hand and giving abuses. The witness has also deposed that on 23-3-75 at about 2-50 P.M. while he was parking his Scooter, Shri Harlal Singh came there and held up his right hand and gave abuses and threats and snatched away the charge-sheet papers and tore them off into pieces. This witness has also been cross-examined at length but there is nothing to show as to why this witness is deposing against Shri Harlal Singh. Apparently there seems to be no enmity or malice of the witness against Shri Harlal Singh. Even in the affidavit before the Court Shri Harlal Singh has said nothing about the conduct of Shri Rao in deposing against him. The testimony of Shri Devash and Shri Rao appears to be reliable. M.W. 2 Shri Ved Prakash has definitely deposed that Shri Harlal Singh came from behind and pushed Shri Devash on the table. Then some 3 or 4 persons caught hold of Shri Harlal Singh and brought him outside the room and Shri Devash told him that he has been assaulted. I.W. 4 Shri U. B. Singh has simply de-totally, but he has not said anything as to why Shri Devash and Shri Harlal Singh. It is not clear from the statement of Shri Devash that at the time of incident Shri U. B. Singh was present and so I think the testimony of Shri U. B. Singh is not useful to either party in the present case. M.W. 5 Shri K. K. Singh has simply deposed that on 23-3-1975 some body informed him that there was a telephone from Shri Rao to tell Shri U.B. Singh to inform Shri Harlal Singh to see him at 3 P.M. M.W. 6 Shri R. S. Mishra has corroborated the testimony of Shri Rao by deposing that at the time of parking of the Scooter, Shri Harlal Singh held up Shri Rao and snatched away his papers and threatened him with dire consequences, and also tore off the papers. This witness has also been cross-examined at length but there is

nothing to disbelieve the testimony of the witness as it does not transpire that the witness is speaking some thing false on account of any enmity or malice against Shri Harlal Singh. D.W. 1 Shri Harlal Singh has denied the incident totally, but he has not said anything as to why Shri Devash and Shri Rao have deposed against him or have tried to implicate him falsely. D.W. 2 Shri R. S. Solanki has deposed that no incident took place in his presence. This witness has been named by Shri Devash as one of the persons who took Shri Harlal Singh out of the room. The witness has denied the incident. It may be that the witness might be trying to help his co-worker. Any way, since I have held that the testimony of Shri Devash and Shri Rao are reliable, I think, no credence can be given to the testimony of this witness who has tried to give negative evidence. D.W. 3 Shri Radha Kishan has not said any thing about the incident.

7. Thus from the discussion of the evidence before the Enquiry Officer, I find that the charges have been amply proved against Shri Harlal Singh and the Enquiry Officer was right in holding the charges proved against him for assaulting Shri Devash and Shri Rao, the engineers of the non-applicant. From the papers filed by the management it becomes clear that Shri Harlal Singh had been guilty of misconduct on previous occasions also and he was warned for the same and that being so, I think, the Disciplinary Authority was justified in dismissing him from service. I hold that dismissal of Shri Harlal Singh from service by the management is just and proper.

8. I, therefore, pass an award by declaring that the action of the management of Khetri Copper Complex of Hindustan Copper Limited, in dismissing Shri Harlal Singh Punia, Mechanic 'B' in the Mine of Khetri Copper Complex from service with 23-9-75, is justified and he is not entitled to any relief whatsoever. Let the award be published according to law.

Dated 31-3-79

S. R. KOTHARI, Judge.

[No. L-43012/3/76-D. IV B./D. III B.]

**S.O. 1548.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Industrial Tribunal Rajasthan, Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Khetri Copper Complex of Hindustan Copper Limited, Khetri Nagar and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th April, 1979.

**CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN,  
JAIPUR**

**PRESIDED BY SHRI S. R. KOTHARI, JUDGE**

**Reference Case No. C.I.T.—14 of 1976**

**REFERENCE :**

Government of India Ministry of Labour, New Delhi Order No. L-43012 (1)/76-D-IV (B) dated 27th October, 1976.

**In the Matter of an Industrial Dispute**

**BETWEEN**  
The Management of Khetri Copper Complex of Hindustan Copper Limited, Khetri Nagar.

**AND**

Their Workman

**APPEARANCES**

For the Management.—Shri S. B. L. Agrawal.

For the workman.—Shri Ashok Parihar

**AWARD**

The Government of India, by the above referred notification, has referred the following dispute for adjudication by this Tribunal :—

"Whether the action of the management of Khetri Copper Complex of Hindustan Copper Limited, Khetri in dismissing Shri Bhanwari Lal, Carpenter 'B' Token No. 76, Kolhan Copper Mines with effect from 27-10-1975 is legal and justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. On receiving the reference, notices were issued to both the parties. The applicant filed the claim contending that his dismissal by the Management was illegal, as no proper domestic enquiry was conducted and he was victimised for ulterior motives by the Management. The Management in its reply controverted the allegations of the applicant.

3. Before proceeding to decide the dispute, it will not be out of place to mention here the brief facts which have led to this dispute in the reference. Shri Banwarilal joined his duties as Carpenter in the Hindustan Copper Limited, Khetri Copper Complex on 22-11-67. On 15-3-75, he was issued a Charge-sheet whereby it was alleged that on 13-3-75 while he was on duty, he committed theft of 2 'V' belts at about 8.15 A.M. from the Sampling Shed, which were discovered at about 9.15 A.M. on 15-3-75 hidden in the Carpentry Shed of Geological Section where he was working. Banwarilal denied the charge and hence a domestic enquiry was started against him. The Enquiry Officer after recording the evidence of both the parties, gave an enquiry report in which he held the charge as proved on the basis of the enquiry report, and after hearing the applicant, the Disciplinary Authority also held the charge to be proved, and after notice to Shri Banwarilal he dismissed him from service. This dismissal was challenged by Shri Banwarilal before the Government as being in the nature of victimisation and unfair labour practice and the Government referred the dispute to this Court for decision. On 31-5-77, my learned predecessor framed a preliminary issue as to whether the domestic enquiry was fair and proper, and since no evidence was produced by both the parties, my learned predecessor after hearing both the parties at length held that the domestic enquiry was fair. After this decision, since the workman wanted to produce evidence against the mala fide intention of the Management, he was allowed to produce the evidence. The workman examined himself and one witness Shri Ram Chandra. In rebuttal, the Management examined Shri Mittal. After closure of the evidence, both the parties argued out their respective cases before me, and I proceed to decide the dispute after dealing with the contentions of the parties. Before proceeding to decide the dispute it will not be out of place to mention here that this reference is under Section 10 (1) (d) of the Industrial Dispute Act. In the original Act there was no provision specifically defining the powers of the Tribunals to give relief in case of discharge or dismissal of the workmen. However, on 15-12-71, Section 11A was inserted in the main Act by the Industrial Disputes Amendment Act, 1971 (Act No. 45 of 1971), which defines the power of the Labour Courts and Tribunals to give appropriate relief in case of discharge or dismissal of workman. Section 11A runs as under :—

**"11-A. Powers of Labour Courts, Tribunals and National Tribunals to give appropriate relief in case of discharge or dismissal of workmen.** Where an industrial dispute relating to the discharge or dismissal of a workman has been referred to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal for adjudication and, in the course of the adjudication proceedings, the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, is satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified, it may, by its award, set aside the order of discharge or dismissal and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, or give such other relief to the workman including the award of any lesser punishment lieu of discharge or dismissal as the circumstances of the case may require :

Provided that in any proceeding under this section the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, shall rely only on the materials on record and shall not take any fresh evidence in relation to the matter."

4. It would be pertinent to note here that before insertion of this Section, it was the consensus of the judicial opinion that the nature and scope of the jurisdiction of the Tribunal was merely of supervisory nature to see whether the enquiry was fair and proper and for that purpose the Tribunal could only examine whether there was want of good faith or there was victimisation or unfair labour practice on the part of the employer or the Management was guilty of basic error or violation of principles of natural justice or the findings of the Enquiry Officer were completely baseless or perverse. If the

enquiry did not suffer from any of the defects, the Tribunal had no jurisdiction to go into the merits of the case. However, with the insertion of Section 11A a material change has been brought about in the Act. The words "in the course of adjudication proceedings, the Tribunal is satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified" in Section 11A clearly indicates that the Tribunal is now clothed with the power to re-appraise prove the evidence in the domestic enquiry and satisfy itself whether the said evidence related by the management establishes the misconduct alleged against the workman what was originally a plausible conclusion that could be drawn by a employer by the evidence has now given place to a satisfaction being arrived at by the Tribunal that the finding of misconduct is correct. The Tribunal is now at liberty to consider not only whether the finding of misconduct recorded by the employer is correct but also to differ from the said finding if a proper case is made out. The Tribunal has to consider the evidence on record and come to conclusion one way or the other and in cases where an enquiry has been held by the employer and a finding of misconduct arrived at, the Tribunal could now certainly differ from the finding in a proper case and hold that no misconduct is proved. I am fortified in taking the above view from the observations of their Lordships of the Supreme Court in a case reported in 1973-I L.L.J. 278 Paras 33 and 37 and the decision of Kerala High Court reported in 1928 (38)/L.R.P. 288. In view of the above proposition of Law and the fact that it has been held by my predecessor that the domestic enquiry was fair, I now proceed to consider the evidence on record to find out whether the conclusion arrived at by the Enquiry Officer is correct or not, and whether the order passed against employee is correct.

The applicant was charged with the theft of 2 V belts from the sampling Shed. During the course of enquiry the Management examined five witnesses to support the charge Shri H.C. Mittal deposed that on 15-3-75 there was complaint about the theft of the belts. On this Shri G.P. Verma, Geologist along with samplers Balvir Singh and Sanwat Ram and Ram Chander tried to search it. It was not found in sampling shed. Ram Chander and Balveer Singh suspected the belts in the carpentry shop and when they peeped through the window, they saw that V. belts were lying behind the wooden almirah of Banwarilal. He and G.P. Verma also confirmed this fact. M.W. 2 G. P. Verma, M.W.3 Sanwat Ram and M.W.4 Balveer Singh have corroborated me testimony of Shri Mittal. Balveer Singh has not even been cross-examined by the applicant, which shows that his testimony is not challenged. It is no doubt true that the witnesses have admitted that at the time of recovery of V. belts from the carpentry shop, where Banwarilal used to work, Banwarilal was not present, but this by itself is not sufficient to hold the testimony of the witnesses is not reliable. Inspite of lengthy cross-examination of witnesses, nothing has been elicited to show that the witnesses are either speaking false deliberately or that they are interested against the petitioner in any way. Then M.W. 5 S.S. Subedar has deposed that when the belt were found, he asked Banwarilal about the matter, but Banwarilal denied his complicity in it, however, later he came to him and said that he had committed a mistake and he shall never do it again and he admitted his guilt before him. This witness has not at all been cross-examined by Shri Banwarilal. This shows that his testimony goes unchallenged. There is nothing on record to show that the extra judicial confession of Shri Banwarilal before this witness was in any way involuntary or the result of some coercion or the threat. Reading the entire evidence minutely I am of the opinion that the charge was amply proved against Shri Banwarilal and there is nothing to hold that the finding of the Enquiry Officer about it is in any way incorrect or wrong. Shri Banwarilal has deposed before this Court that Shri H. S. Mittal was personally prejudiced against him because he refused to serve him at his home. One Shri Ram Chander, sampler has also supported Banwarilal in this respect. Shri Ram Chander is a dismissed employee of the Copper Complex, Khetri Project. The testimony of Shri Banwarilal does not appear to be correct as no question was put by him to the witness about it during the course of enquiry. Then such allegations may be made at any time by any body. Shri Mittal has denied this fact and has deposed that there was another carpenter Shri Budhi Prakash working under him, and so there was no question of asking Shri Banwarilal to serve him at his home. The evidence of Shri Banwarilal about his victimisation or about the mala fides of Shri H.C. Mittal does not inspire any confidence and cannot be believed. That being so, there is nothing to indicate any victimisation or

unfair labour practice against Shri Banwarilal in the order of dismissal passed against him by the Management. I, therefore, hold that Shri Banwarilal is not entitled to any relief from this Tribunal, as the order passed by the Management is proper.

5. I pass an award holding that the action of the Management of Khetri Copper Project of Hindustan Copper Limited, Khetri in dismissing Shri Banwarilal, Carpenter-B, Token No. 76, Kolhan Copper Mines, with effect from 27-10-1975, is legal and justified and he is not entitled to any relief whatsoever. Let this award be published in accordance with law.

Dated 31-3-1979

S. R. KOTHARI, Judge  
[No. I-43012/1/76-D IV (B) III]  
A. K. ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1979

का०आ० 1549—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि सोकहित में गोपनीय अधिकारी के अन्दर अन्दर अन्दरालालों और औपधालयों की सेवाओं के जिनके लिए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2(क) (1) के अधीन संबंधित सरकार है, जिन्हें उक्त अधिनियम की प्रथम अनुमूल्यी में प्रदिष्टिं 9 द्वारा शामिल किया गया है, उक्त अधिनियम की प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा औपित करनी चाहिए;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (3) के उपखंड (6) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अस्पतालों और औपधालयों में उक्त सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से ले. माम की कालाबधि के लिए लोक उपयोगी सेवा औपित करनी है।

[म० एस० 11017/3/79/झ० 1 (ए)]  
एल० के० नारायणन्, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th April, 1979

S.O. 1549.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that services in the hospitals and dispensaries within the Union Territory of Delhi, for which the Central Government is the appropriate Government under Section 2(a) (i) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act 14 of 1947), which are covered by entry 9 in the First Schedule to the said Act, should be declared to be public utility services for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act 14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said services in hospitals and dispensaries to be public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S. 11017/3/79/D1(A)]  
L. K. NARAYANAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1979

का०आ० 1550—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसमं कास्ट बिट मविस, अ०-२६, गोपनीय हंडस्ट्रियल इंस्टेट, नईगाँव काम गोड, बड़ला, मुम्बई-३१, नामक स्थापन में गम्बुद लिंगोजक और कर्मचारियों की अत्यधिक इस बात पर महसूल हो गई है कि कर्मचारी भवित्व निष्प्र और प्रकार्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 मई, 1977 को प्रवृत्त हुई भवित्व जारी।

[स० एस० 35018/20/79-प० ११]

New Delhi, the 23rd April, 1979

S.O. 1550.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Fast Print Service, B-26, Royal Industrial Estate Naigaum Cross Road, Wadala, Bombay-31, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of May, 1977.

[No. S. 35018/20/79-PF. II]

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1979

का०आ० 1551—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भवित्व निधि और प्रकार्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रयोग परन्तु इनकार्यों का प्रयोग करने हुए, संबंधित विषय में प्रावधान जाच करने के पालन- १ जूनाई, 1977 से मैसमं स्वयं प्रदेश संट फोरमट इवलपमेंट कार्यालय लिमिटेड, भोपाल (मध्य प्रदेश) जिसके अन्तर्गत (1) मध्य प्रदेश फोरमटी टेक्निकल अग्रिस्टेम्प प्रोजेक्ट, जगदलपुर, (2) कंपनी प्रोजेक्ट चिक्कीजन, हड्डी रोड, होणगाबाद, (3) बारधाट प्रोजेक्ट डिक्कीजन, मिवरी, (4) लामता प्रोजेक्ट डिक्कीजन, बालाबाद, (5) बन्दवापारा प्रोजेक्ट डिक्कीजन, जलविहार कालांती, तेलीवध, पोस्ट बाक्स 69, रायपुर, (6) मोवगाव प्रोजेक्ट डिक्कीजन, मिविल लाइन, मंडला, (7) कोटा पंडिया प्रोजेक्ट डिक्कीजन, मत्य निवास जराहा भाटा, मिवी कालांती, विलासपुर, (8) रायपुर भटोरी प्रोजेक्ट डिक्कीजन, मदर इटमी रोड, बेतुल, (9) कुम्भम प्रोजेक्ट डिक्कीजन, 345, राहट दाउन, जगलपुर, (10) नानपुर प्रोजेक्ट डिक्कीजन, 298/1, गिरिल बांड, थाना के सामने, मंडला, (11) उमरिया प्रोजेक्ट डिक्कीजन, उमरिया, जिला शाहजोल, मध्य प्रदेश, (12) पताबाराम प्रोजेक्ट डिक्कीजन, बालदंबवाल, मोती लालाब के निकट, राजनन्द गांव और (13) अटागढ़ प्रोजेक्ट डिक्कीजन, बलदंब बाग, मार्ती लालाब के निकट, राजनन्द गांव (मध्य प्रदेश) स्थित उक्ती शास्त्रांग भी हैं, नामक स्थापन को उक्त परन्तुके लिए प्रिनिविष्ट करती है।

[म० एस० 35019/(27)/79-प० ११]

New Delhi, the 24th April, 1979

S.O. 1551.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter hereby specifies with effect from the first day of July, 1977 the establishment known as Messrs. Madhya Pradesh State Forest Development Corporation Limited, Bhopal (Madhya Pradesh) including its branches at (1) Madhya Pradesh Forestry Technical Assistance Project, Jagdalpur (2) Kesla Project Division, Itarsi Road, Hoshangabad, (3) Baragh, Project Division, Seoni, (4) Lamta Project Division, Balaghat (5) Barnawapara Project Division, Jalvihar Colony, Telibandha, Post Box 69, Raipur, (6) Mobaon Project Division, Civil Lines, Mandla, (7) Kota Pandaria Project Division, Satya Nijwas Jaraha Bhata Sindhi Colony, Bilaspur (8) Ramapur Bhatori Project Division, Sadar Itarsi Road, Betul, (9) Kundam Project Division, 645, Wright Town, Jabalpur, (10) Nainpur Project Division, 298/1, Civil Ward, Opposite Police Station, Mandla, (11) Umaria Project Division, Umaria, District Shahdol, Madhya Pradesh, (12) Panabarara Project Division, Baldeobag, Near Moti Talab, Rajnandgaon and (13) Antagarh Project Division, Baldeo Bag, Near Moti Talab, Rajnandgaon (Madhya Pradesh) for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019 (27) 79-PF. II]

का० आ० 1552.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मध्य प्रदेश स्टेट फोरस्ट डिव्हिजनल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल (मध्य प्रदेश) जिसके अन्तर्गत (1) मध्य प्रदेश फोरस्टी टेक्निकल प्रसिस्टेन्स प्रोजेक्ट, जगदलपुर, (2) केसला प्रोजेक्ट डिव्हिजन, इटसी-रोड, होशगांव, (3) बार्गाट प्रोजेक्ट डिव्हिजन, सिवनी, (4) नामता प्रोजेक्ट डिव्हिजन, बालवाडा, (5) बर्नवापारा प्रोजेक्ट डिव्हिजन, जलविहार कालोनी, तेलीबन्ध, पोस्ट बाक्स 69, रायपुर, (6) मोबांग एंट्री प्रोजेक्ट डिव्हिजन, मिविल लाइन्स, भेड़ला, (7) कोटा पंडिरियों प्रोजेक्ट डिव्हिजन, सत्य निवास जराहा भाटा सिन्धी कालोनी, जिलासपुर, (8) रायपुर भटोरी प्रोजेक्ट डिव्हिजन, सदर इटसी रोड, बेतूल, (9) कुन्दम प्रोजेक्ट डिव्हिजन, 645, राइट टाउन, जबलपुर, (10) नैनपुर प्रोजेक्ट डिव्हिजन, 298/1, सिविल बाई, थामा के सामने, मंडला, (11) उमरिया प्रोजेक्ट डिव्हिजन, उमरिया जिला शाहजहानपुर, मध्य प्रदेश, (12) पनाबारास प्रोजेक्ट डिव्हिजन, बलदेब बाग, मोती तालाब के निकट, राजनन्द गांव और (13) अंतागढ़ प्रोजेक्ट, बलदेब बाग, मोती तालाब के निकट, राजनन्द गांव, (मध्य प्रदेश) स्थित उमरिया शाखाएँ भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महसूत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकार्य उपबन्ध प्रविनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः यद्युपि, उक्त प्रविनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रविनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह प्रधिसूचना 1 जुलाई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[मं. एस० 35019(27)/79-पी०एफ०-11(i)]

S.O. 1552.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Madhya Pradesh State Forest Development Corporation Limited, Bhopal (Madhya Pradesh) including its branches at (1) Madhya Pradesh Forestry Technical Assistance Project, Jagdalpur, (2) Kesa Project Divisions, Itarsi Road, Hoshangabad, (3) Barghat Project Divisions, Sconi, (4) Lamta Project Division, Balaghat, (5) Barnawapara Project Division, Jalvihar Colony, Telibandha, Post Box 69, Raipur, (6) Mobaon Project Division, Civil Lines, Mandla, (7) Kota Pandaria Project Division, Satya Niwas Jaraha Bhatta Sindhi Colony, Bilaspur, (8) Rampur Bhatori Project Division, Sadar Itarsi Road, Betul, (9) Kundam Project Division, 645, Wright Town, Jabalpur, (10) Nainpur Project Division, 298/1, Civil Ward, Opposite Police Station, Mandla, (11) Umariya Project Division, Umariya District Shahdol, Madhya Pradesh, (12) Panabarsa Project, Division, Baldeobag, Near Moti Talab, Rajnandgaon and (13) Antagarh Project Division, Baldeo Bag, Near Moti Talab, Rajnandgaon (Madhya Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1977.

[No. S. 35019(27)/79-PF. II (i)]

नई दिल्ली, 3 मई, 1979

का० आ० 1553.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एंट्रीज, मिलिंग एंट्रीस एंड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन, कोटा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महसूत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकार्य उपबन्ध प्रविनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकार्य उपबन्ध प्रविनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः यद्युपि, उक्त प्रविनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रविनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह प्रधिसूचना 1 मार्च, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[मं. एस० 35019(53)/79-पी०एफ० II]

New Delhi, the 3rd May, 1979

S.O. 1553. Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sakthi Agencies, Selling Agents and Dealers, K. K. Road, Kottayam District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1979.

[No. S. 35019/53/79-PF. II]

का० आ० 1554.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पंजाब डिस्ट्रिक्ट डिव्हिजन लिमिटेड, ए-27, फेस 7, भोजपुरीगिक क्लॉन, एस०ए०एफ० नगर, (मोहाली), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महसूत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकार्य उपबन्ध प्रविनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः यद्युपि, उक्त प्रविनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रविनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह प्रधिसूचना 1 जनवरी, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[मं. एस० 35019(45)/79-पी०एफ० II]

S.O. 1554.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Punjab Display Devices Limited, A-27, Phase VII, Industrial Area, S.A.S. Nagar, (Mohali), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1979.

[No. S. 35019/45/79-PF. II]

का० आ० 1555.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जीपर (एडिशन) (प्राइवेट) लिमिटेड, 259/145, एस०ए०एफ० एंड एंट्रीस एस्टेट, सेवनी, बंदर रोड, मुम्बई-15 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महसूत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकार्य उपबन्ध प्रविनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस० 35018(25)/79-पी.एफ० II]

**S.O. 1555.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Zipper (India) Private Limited, 259/145, ACME Industrial Estate, Sewri Bunder Road, Bombay-15, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1978.

[No. S. 35018/25/79-PF. II]

**का० आ० 1556—**यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेस जीपर पैकेजिंग, सिंह इंडस्ट्रियल एस्टेट, राम मंदिर रोड, गोरे गांव (परिवार), मुम्बई-62 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निवि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस० 35018(24)/79-पी.एफ० II]

**S.O. 1556.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Gipar Packaging, Singh Industrial Estate, Ram Mandir Road, Goregaon (West) Bombay-62, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1976.

[No. S. 35018/24/79-PF. II]

**का० आ० 1557—**केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेस यूटाइल फैरियर, 317, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट मार्केट के लिंक, मुम्बई-38, नामक न्यायपाल से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निवि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस० 35018/37/79-पी.एफ० II]

**S.O. 1557.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs United Carrier, 317, Shaheed Bhagat Singh Road, Near Fort Market, Bombay-400038 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1977.

[No. S.35018/37/79-PF. II]

**का० आ० 1558—**केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेस टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाग्ले इंडस्ट्रियल प्लॉट प्लॉट नं. ८/278, रोड नं. १६-ए, ठाणे-४, जिसके प्रालयन १०६/१०७ कृष्णा नगर डॉ. अंबेडकर रोड, परेल मुम्बई-१२ स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निवि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस० 35018/31/79-पी.एफ० II]

**S.O. 1558.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Timber Trading Corporation, Wagle Industrial Estate, Plot No. A/278, Road No. 16-A, Thane-4 including its branch at 106/107 Krishna Nagar, Dr. Ambedkar Road, Parel, Bombay-400012, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1978.

[No. S.35018/31/79-PF. II]

**का० आ० 1559—**केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेस मन्त्रभाई प० मेठ एण्ड एम्पर्स, जन्म भूमि बैंडर्स, वालचन्द हीराचन्द मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-१ नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निवि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 अगस्त, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस० 35018/36/79-पी.एफ० II]

**S.O. 1559.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Manubhai A. Sheth and Others, Janmabhoomi Chambers, Walchand Hirachand Marg, Fort, Bombay-400001, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of August, 1977.

[No. S-35018/36/79-P.F. II]

**का० आ० 1560.**—केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेंस इ०ए० वर्डी एंड कॉम्पनी, चाट्टैंड अफाउंडम, 403, ए०पी०ज० हाउस, 130, बोर्ड अमाचार मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-23, नामक स्थापन से मध्यबूद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मई, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[मं० एम० 35018/41/79-पी०ए० II]

**S.O. 1560.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs D. F. Birdy and Company, Chartered Accountants, 403, Apeejay House, 130, Bombay Samachar Marg, Fort, Bombay-400023, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1978.

[No. S-35018/41/79-P.F. II]

**का० आ० 1561.**—केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेंस मउदी अरबियन एपरलाइंस, एस.प्रैंट टार्क्स, नर्मान प्लाईंट, मुम्बई-21, नामक स्थापन से सध्यबूद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[मं० एम० 35018/42/79-पी०ए० II]

**S.O. 1561.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Saudi Arabian Airlines, Express Towers, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1978.

[No. S-35018/42/79-P.F. II]

**का० आ० 1562.**—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेंस इ०ए० वर्डी एंड कॉम्पनी, चाट्टैंड अफाउंडम, 403, ए०पी०ज० हाउस, 130, बोर्ड अमाचार मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-23, नामक स्थापन से मध्यबूद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[मं० एम० 35018/49/79-पी०ए० II]

**S.O. 1562.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Roop Sangam, 385, N. C. Kelkar Road, Laxmi Building, 1st Floor, Dadar, Bombay-28, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1978.

[No. 35018/49/79-P.F. II]

**का० आ० 1563.**—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेंस कामत इ०ए० कॉम्पनी, एशियन बिल्डिंग, निकोल रोड, बलार्ड एस्टेट, मुम्बई-38, नामक स्थापन से मध्यबूद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[मं० एम० 35018/38/79-पी०ए० II]

**S.O. 1563.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kamat and Company, Asian Building, Nicol Road, Ballard Estate, Bombay-400038, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1978.

[No. S-35018(38)/79-P.F. II]

का० आ० 1564.—केंद्रीय परकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेसं जेमलाइट इंडस्ट्रीज, प्लाट नं० बी०-24, बाथे इंडस्ट्रियल एस्टेट, थाना-4 नामक स्थापन से भवत्ता नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्य, इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अ० २ प्रकारण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, यदि, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय स कार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1978 को प्रकृत हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018/29/79-प००५० II]

**S.O. 1564.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as M/s. Gemlite Industries, Plot No. B-24, Wagel Industrial Estate, Thana-4 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1978.

[No. S-35018/29/79-PF. II]

का० आ० 1565.—मैसेसं ब्रिटिश इंस्टीट्यूट प्राफ इंजीनियरिंग टेक्नो-लॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई (जिसे इसमें पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकारण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19), जिसे इसमें आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कूट नेते के लिए प्रावेदन किया है;

और केंद्रीय सरकार की राय में अभिवाय की दरों की बाबत उक्त स्थापन के भविष्य निधि नियम, उसके कर्मचारियों के लिए उन नियमों से कम अनुकूल नहीं हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 6 में विविरित हैं। कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रसुविधाओं का भी उपयोग कर रहे हैं जो उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल नहीं हैं, जो उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम के अधीन या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उपबन्धित हैं;

अतः, यदि, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबन्ध प्रमुखों में विविरिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपयोगों के प्रबोधन से कूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास के समान होने से 15 दिन के भीतर संवाद करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन निविष्ट करे।

2. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक:-

(1) उक्त स्थापन के भविष्य निधि (जिसे इसमें आगे भविष्य निधि कहा गया है) में अभिवायों के विनिधान की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन

समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कि ए गए मिलेंगे का पालन करेगा;

(2) यह अधिन रखने के लिए सम्यक सावधानी बरतेगा कि उक्त स्थापन की बाबत गठित न्यासी बोर्ड, भविष्य निधि अभिवायों को केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए नियमों के अनुसार विनिधान करे और उक्त न्यासी बोर्ड द्वारा भविष्य निधि अभिवायों के लिए विनिधान के लिए जिम्मेदार होगा।

3. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि मायूल, महाराष्ट्र की ऐसी विवरणियां भेजेगा जो केंद्रीय सरकार, समय समय पर निविष्ट करे।

4. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रस्तुत कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण या पास देगा।

5. निधि के प्रशासन पर, जिसके प्रत्यंगत लेखाओं का रखा जाता, लेखाओं और विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, संबंधों का अवतारण निरीक्षण प्रभारों का सदाय, आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक करेगा।

6. उक्त स्थापन के सबथ में नियोजक प्रति वर्ष हर एक सबस्य के आते में ऐसी दर पर, जो न्यासी बोर्ड अवधारित करें तथा जो उस दर से कम नहीं होती जो समय समय पर केंद्रीय सरकार अवधारित करे, द्वाज जमा करेगा।

7. नियोजक केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित रूप में भविष्य निधि नियमों की ओर जब कभी उसमें संशोधन किया जाए तो ऐसे संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मूल्य बातों का अनुवाद भी उक्त स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रवर्शित करेगा।

8. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो उक्त अधिनियम या उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि या छूट प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले वहने ही से सबस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित होता है तो नियोजक भविष्य निधि के अभिवायों की दर समुचित रूप से बढ़ा देगा जिससे कि उक्त स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन की प्रसुविधाएं उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल न ही जाए जिनकी व्यवस्था उक्त अधिनियम के अधीन की गई है।

9. यदि उस बर्ग के स्थापनों के लिए, जिसमें नियोजक का स्थापन आता है, भविष्य निधि के अभिवायों की दर उक्त अधिनियम के अधीन बढ़ा दी जाती है तो नियोजक भविष्य निधि के अभिवायों की दर समुचित रूप से बढ़ा देगा जिससे कि उक्त स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन की प्रसुविधाएं उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल न ही जाए जिनकी व्यवस्था उक्त अधिनियम के अधीन की गई है।

10. उक्त स्थापन घपने भविष्य निधिका नेतृत्वाधित सुलभपत्र हर वर्ष प्रावेशिक भविष्य निधि मायूल, महाराष्ट्र, की वर्ष समाप्त होने से तीन मास के भीतर, भेजेगा।

11. उक्त स्थापन के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भविष्य निधि मायूल, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से उक्त स्थापन के कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाष्य ही वहां प्रावेशिक भविष्य निधि मायूल, महाराष्ट्र, उसे अनुमोदित करने से पूर्व, कर्मचारियों को अपना धूपितकोण स्पष्ट करने से पूर्व युक्तियुक्त अवकर से।

[सं० एस० 35014/30/79-प००५० II]

**S.O. 1565.**—Whereas, Messrs British Institute of Engineering Technology (India) Private Limited, Bombay (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable than those specified in section 6 of the said Act, and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

2. The employer in relation to the said establishment;

- (i) Shall comply with the directions issued by the Central Government, from time to time, under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the said Act in regard to the investment of contributions to the provident fund;
- (ii) Shall take due care to see that the Board of Trustees constituted in respect of the establishment invest the provident fund contributions in accordance with the directions issued by the Central Government, from time to time, and shall be responsible for such investment of contributions to the provident fund by the said Board of Trustees.

3. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra as the Central Government may, from time to time, direct.

4. The employer in relation to the said establishment shall furnish to each employee an annual statement of account or a Pass Book.

5. All expenses involved in the administration of the provident fund, including the maintenance of accounts, submission of accounts and returns, transfer of accumulations, payment of inspection charges, shall be borne by the employer of the said establishment.

6. The employer in relation to the said establishment shall credit every year to the account of each member interest at such rates as may be determined by the Board of Trustees and such rate shall not be less than the one determined by the Central Government from time to time.

7. The employer shall display on the notice board of the said establishment, a copy of the rules of the provident fund as approved by the Central Government and, as and when amended, the amendments thereto, along with a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

8. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund under the said Act or the said Scheme or the provident fund of another exempted establishment, is employed in the said establishment, the employer

shall immediately enrol him as a member of the fund of the establishment, and accept the past accumulations in respect of such employee and credit the same to his account.

9. The employer shall enhance the rate of contribution to the provident fund appropriately if such rate for the class of establishments in which his establishment falls is enhanced under the said Act so that the benefits under the provident fund scheme of the said establishment shall not become less favourable than the benefit provided under the said Act.

10. The said establishment shall submit an audited balance sheet of the provident fund every year to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, within three months of the close of the year.

11. No amendment of the rules of the provident fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, and where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees of the said establishment, the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees of the said establishment to explain their point of view.

[No. S-35014/30/79-PF. II]

**का० मा० 1566.**—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ब्लू एंजेल, लक्ष्मी बिल्डिंग, 385 एस० सो० केलकर रोड, दादर, मुम्बई 28 नामक स्थापन से संबंध नियोजक श्रीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निषि और प्रकीर्ण उपर्युक्त अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपर्युक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

प्रत: भ्र, उक्त अधिनियम की घारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपर्युक्त उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018/48/79-पी०एफ० II]

**S.O. 1566.** Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Blue Angel, Laxmi Building, 385, N. C. Kelkar Road, Dadar, Bombay-400028 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1978.

[No. S-35018(48)/79-PF.II]

**का० मा० 1567.**—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फारमस्ट्रिक्टिल्स, 23 हमारा स्ट्रीट, मुम्बई-23, नामक स्थापन से संबंध नियोजक श्रीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निषि और प्रकीर्ण उपर्युक्त अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपर्युक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

प्रत: भ्र, उक्त अधिनियम की घारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपर्युक्त उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018/44/79-पी० एफ० II]

**S.O. 1567.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Thomas Pharmaceuticals, 23, Hamam Street, Bombay-40023, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1978.

[No. S-35018(44)/79-PF. II]

**का० आ० 1568.**—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ईरान नेशनल एयरलाइंस कारपोरेशन, सुन्दर महल, रैमन ड्राइव, मुम्बई-20 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः यद्य, उक्त अधिनियम की घारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1975 को प्रकृत हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018/34/79-पी०एफ० II(i)]

**S.O. 1568.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Iran National Airlines Corporation, Sunder Mahal, Marine Drive, Bombay-400020 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1975.

[No. S-35018(34)/79-PF. II(i)]

**का० आ० 1569.**—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ट्रोमार्का ट्रेक्नीकल सर्विसेज, 607, एमबीसी सेंटर, नरीमन प्लॉट मुम्बई-21, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः यद्य, उक्त अधिनियम की घारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1976 को प्रकृत हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018( 43)/79-पी०एफ० II (i)]

**S.O. 1569.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Troika Technical Services, 607, Embassy Centre, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees'

Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1976.

[No. S-35018(43)/79-PF. II(i)]

**का० आ० 1570.**—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सती डिस्ट्रीब्यूटर्स, मीना बाजार, 5वा फ्लोर, कोलाबा कौजावे, मुम्बई-39 जिसके अंतर्गत 33/18 राजमहल विलास एक्सटेंशन, बंगलोर-6 स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः यद्य, उक्त अधिनियम की घारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1977 को प्रकृत हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018( 39)/79-पी०एफ० II(i)]

**S.O. 1570.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sati Distributors, Meena Bazar, 5th Floor, Colaba Causeway, Bombay-39, including its branch at 33/18, Rajamahal Vilas Extension, Bangalore-6, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1977.

[No. S-35018(39)/79-PF.II(i)]

**का० आ० 1571.**—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की घारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 1 फरवरी 1977 से मैसर्स मती डिस्ट्रीब्यूटर्स, मीना बाजार, 5 वा फ्लोर कोलाबा कौजावे, मुम्बई-39, जिसके अंतर्गत 33/18, राजमहल विलास एक्सटेंशन, बंगलोर-6 स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिविष्ट करती है।

[सं० एस० 35018( 39)/79-पी०एफ० II(ii)]

**S.O. 1571.**—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of February, 1977 the establishment known as Messrs. Sati Distributors, Meena Bazar, 5th Floor, Colaba Causeway, Bombay-39, including its branch at 33/18, Rajamahal Vilas Extension, Bangalore-6, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018(39)/79-PF. II(ii)]

का० आ० 1572.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्रीय उपबंध प्रविनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 1 नवम्बर, 1976 से मैसर्ट ट्रोप्राइका टेक्निकल सर्विसेज 607, एम्बेसी सेंटर, नरीमन प्लाईट, मुम्बई 21, नामक स्थापन को उक्त परतुक के प्रयोगों के लिए विविदिष्ट करती है।

[सं० एस० 35018(43)/79-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 1572.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of November, 1976 the establishment known as Messrs Troika Technical Services, 607, Embassy Centre, Nariman Point, Bombay-21, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018(43)/79-PF. II.(ii)]

का० आ० 1573.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्रीय उपबंध प्रविनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 1 जुलाई, 1975 से मैसर्ट ईरान नेशनल एयरलाइंस, कारपोरेशन, सुन्दर महल, मैरिल ड्राइव, मुम्बई-20, नामक स्थापन को उक्त परतुक के प्रयोगों के लिए विविदिष्ट करती है।

[सं० एस० 35018(34)/79-पी० एफ० II(ii)]

दंसराज छाड़ा, उप-सचिव

S.O. 1573.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of July, 1975 the establishment known as Messrs Iran National Airlines Corporation, Sunder Mahal, Marine Drive, Bombay-20, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018/34/79-PF. II(ii)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.